1	2	3	4
118.	M-8	6069	Mountaineering
119.	M-9	5736	Trekking
120.	M-10	5852	Trekking
121.	Mulkila (M 04)	6517	Mountaineering
122.	T-l	5669	Trekking
123.	T-2	6035	Mountaineering

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Bhupender Yadav to move the Motion of Thanks on the President's Address.

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति के प्रति निम्नलिखित रूप में कृतज्ञता ज्ञापित की जाए:-

"राष्ट्रपति ने 31 जनवरी, 2020 को संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में जो अभिभाषण दिया है उसके लिए राज्य सभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित सदस्य राष्ट्रपति के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।"

माननीय उपसभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण किसी भी सरकार के संकल्प, योजना, कार्यपद्धति और दर्शन को प्रस्तुत करता है। प्रधान मंत्री, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पांच वर्ष का एक सफल कार्यकाल पूरा करने के बाद जनता ने इस सरकार को पुन: जनादेश दिया। विगत पांच वर्षो में जिस मज़बूत नींव को रखकर भारत आगे बढ़ा है, उसको इस सदी के मज़बूत भारत के रूप में आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने इस अभिभाषण के माध्यम से अपना संकल्प रखा है। मज़बूत भारत बनाने का अर्थ है एक ऐसा भारत, जो पुरातन संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, पर वह इक्कीसवीं सदी के अनुकूल भी हो। एक ऐसा भारत, जिसमें पुरानी समस्याओं का समाधान हो, तो विकास की नई इमारत भी खड़ी की जाए। एक ऐसा भारत जिसमें गरीब, अवसर मिलें और हर क्षेत्र का विकास करते हुए विश्व मंच पर भारत को ऊंचाइयों पर

पहुंचाया जाए। मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने अपनी नीति, नीयत, कार्य-योजना और कार्यपद्धति में समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का काम किया है।

महोदय, अभी हाल ही में देश में विशिष्ट सेवाओं के लिए पद्म पुरस्कार दिए गए। 2014 के बाद हमें जो देखने में आया है कि अब देश में जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, वे कैसे लोगों को दिए जाते हैं, यह बताने के लिए मैं कुछ नाम आपके सामने बताना चाहूंगा। एक मैला ढोने वाली, अति दलित समुदाय की राजस्थान की महिला बहन सुश्री ऊषा चौमार, दलित सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले श्री एम.के. कुंजोल, हल्दी की खेती को लाभकारी आंदोलन में बदलने वाली, मेघालय की हमारी आदिवासी किसान बहन सुश्री त्रिनिति साईऊ, बीज माता के नाम से प्रसिद्ध, महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाली आदिवासी महिला सुश्री रहिबाई सोम पोपेरे, लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले हमारे फैज़ाबाद के मोहम्मद शरीफ, राजस्थान के हमारे गायक भाई श्री रमज़ान खान उर्फ मुन्ना मास्टर, दो दशकों से अधिक समय से बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रहे जम्मू के एक दिव्यांग कार्यकर्ता श्री जावेद अहमद टॉक, 1984 के भोपाल गैस की त्रासदी के बचे लोगों के लिए संघर्ष करने वाले श्री अब्दुल जब्बार, गुजराती व्यंग्यकार श्री शाहबुद्दीन राठौर। लेकिन हम सब देख रहे हैं कि देश में माहौल क्या बनाया जा रहा है? देश में माहौल किस प्रकार का खड़ा किया जा रहा है? देश के माहौल को किसलिए विभाजनकारी बनाया जा रहा है? ऐसे लोगों को यह सोचना होगा कि यह सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के आधार पर हर गरीब भारतवासी को सम्मान देना चाहती है।

आजकल हमारे कॉंग्रेस के लोग संविधान बहुत पढ़ रहे हैं, यह बहुत खुशी की बात है, लेकिन इस देश के संविधान को 1974 में आपने ही तिरस्कृत करके देश में इमरजेंसी लगाई थी। चलो अब आप संविधान पढ़ने लग गए, आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ने लग गए, लेकिन मेरा आपसे यह कहना है कि जब आप संविधान को पढ़ें, संविधान का सम्मान करें, तो संविधान को पूरा पढ़ें। इसलिए अगर आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो संविधान के आर्टिकल 44 में लिखा गया है कि "State shall endeavour to provide for its citizens a uniform civil code (UDC) throughout the territory of India." यह आप क्यों नहीं पढ़ते? हम जब बात करते हैं, तब आप हम पर आरोप लगाते हैं। आप संविधान को पूरा नहीं पढ़ते हैं। संविधान में ही आर्टिकल 44 के साथ आर्टिकल 48 में लिखा है कि "... organise Agriculture and Animal Husbandry." संविधान में गौरक्षा की बात की गयी है, आप तो उसको नहीं पढ़ते। संविधान में तो आर्टिकल 51A में Fundamental Duties की बात की गयी है, आप तो उसको नहीं पढ़ते। संविधान में जो टेम्पोरेरी चीज़ थी, आर्टिकल 370, उसको हमने बदला तो आपत्ति है, परन्तु आपने तो अपने टाइम में भारत के संविधान की प्रस्तावना को ही बदल दिया था। हालांकि हमारे संविधान में क्या कहा गया था, संविधान निर्माताओं ने क्या कहा था कि भारत में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। यह तो पहले से थी। यह हमारी संस्कृति में थी, यह हमारे विश्वास में थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि हम जब पार्टी के नये

सदस्य बनाते हैं, हम इस पार्टी की शपथ लेते हैं, तो हमारी पंचनिष्ठाओं में से दो प्रमुख निष्ठाएँ हैं- सर्वधर्म समादर भाव और उसके साथ समतामूलक समाज की स्थापना। हम इन मूल्यों से निकले हुए हैं। हम भारत की पुरातन संस्कृति के मूल्यों से निकले हुए हैं।

महोदय, अभिभाषण में कहा गया है कि लोकतंत्र का जो जनादेश होता है, वह लोकतंत्र का जनादेश सबसे पवित्र होता है और हम सब इस लोकतंत्र के जनादेश को मानते रहे हैं। 1952 के पहले चुनाव में हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा। हम हर बार हारे। 1990 में हम पहली बार अधिकृत रूप से विपक्ष की पार्टी बने। हमने कभी लोकतंत्र के ऊपर उँगली नहीं उठायी। हमने हमेशा लोकतंत्र का सम्मान किया, लेकिन आप 5 साल से क्या कर रहे हो? आप लोकतंत्र के जनादेश पर, EVM पर प्रश्न उठा रहे हो। हम तो कभी नहीं उठाते। हम तो कोई चुनाव हारते हैं, कोई जीतते हैं। हम तो चुनाव आयोग की मर्यादा को, चुनाव कराने के निष्पक्ष तरीके को हमेशा मानते हैं, परन्तु आप जब हारते हो, तो आप लोकतंत्र पर भी उँगली उठाने से नहीं चूकते। आप लोकतंत्र में और किस प्रकार का विरोध करते हो?

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने किस प्रकार के लोगों को अवार्ड दिये। वह लिस्ट मैंने पढ़ी है, लेकिन आपने हमारी सरकार आने के बाद किस प्रकार से काम किया। 2014 में पूरे देश में एक असत्य का आन्दोलन चला दिया- 'अवार्ड वापसी, अवार्ड वापसी।' क्या हुआ भाई? इस देश में तो सबको अभिव्यक्ति की आजादी है। 2015 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बच्चों से क्या कहलवाया ! आपकी पार्टी के नेता वहाँ पर गये, लेकिन देश तो वहीं रहा, नौजवान वहीं तरक्की करते रहे। 2016 में गरीबों के लिए हम 'आधार कानून' लेकर आये तो विरोध करने का काम आपने किया और 2017 में जब 'सर्जिकल स्ट्राइक' हुई, तब सेना पर भी प्रश्न उठाकर आपने देश की मर्यादा को तोड़ने का काम किया। 2018 में आपने राफेल जैसा असत्य आरोप लगाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी माँगनी पड़ी। आजादी के बाद यह पहली बार हुआ है कि किसी दल के नेता को सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी माँगनी पड़ी हो। हम महिलाओं के उत्थान के लिए 'तीन तलाक' का कानून लाये, तो आप विरोध करो। हम यह कहते हैं कि जो देश की सम्पत्ति को, देश को छोड़ कर गये हैं-- इन्दिरा जी के समय में 'शत्रु सम्पत्ति विधेयक' आया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण उस विधेयक की पुनर्स्थापना करने के लिए हम संशोधन लाये तो आप 'शत्रु सम्पत्ति विधेयक' का विरोध करते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के 700 साल पुराने विवाद को सुलझाने का काम किया गया है। मैं कहता हूँ, आप न्यायालय में जाकर दलील दे सकते हो। यह पक्ष ठीक है, यह पक्ष गलत है, आप कह सकते हो। वहाँ पर जाकर, आपके जो नेता हैं, वे कोर्ट में क्या दलील दे रहे हैं कि इसको निर्णीत मत करो, भारतीय जनता पार्टी जीत जायेगी। भारतीय जनता पार्टी जीते या हारे, लेकिन देश में राम की सनातन संस्कृति के मूल्य बने रहें, यह हमारी मान्यता है। इसलिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि सरकार ने एक बहुत बड़े विवाद को बहुत पारस्परिक सौहार्द्र के साथ, बड़े सद्भाव के साथ, लोगों को विश्वास में लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय

के निर्णय की परिपालना करायी है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने भारत के विकास में कभी किसी दृष्टिकोण के साथ भेदभाव नहीं किया। हमने देश में सभी दृष्टिकोणों का समान रूप से आदर किया है और इसलिए इस अभिभाषण में सरकार ने संकल्प किया है कि भारत कैसा बनना चाहिए। महात्मा गांधी के स्वराज का भाव होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक भारत का दृष्टिकोण होना चाहिए, सरदार पटेल के एक भारत, श्रेष्ठ भारत की कल्पना होनी चाहिए, दीनदयाल जी के अंत्योदय का लक्ष्य होना चाहिए तो राम मनोहर लोहिया जी के समतामूलक समाज का सपना सबको साकार करना चाहिए। पांच साल में माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उसको लेकर चले हैं और यही कारण है कि वर्ष 2014 में हमें जितने वोट मिले थे, उससे चार करोड़ ज्यादा लोगों ने पुन: उनको चुनकर देश को चलाने का संकल्प दिया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि न्याय का महत्व वे लोग जानते हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है। इस देश में, यह जो देश है, इसकी बड़ी परम्परा रही है। हमारा सांस्कृतिक गौरव बहुत बड़ा रहा है और इस देश के विभाजन को कोई इनकार नहीं कर सकता। आज हमारे विपक्ष के लोगों के द्वारा शाहीन बाग में एक आंदोलन चलाया जा रहा है। मैं इसे विपक्ष के लोगों के द्वारा इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे कॉंग्रेस के बहुत बड़े विचारक और चिंतक श्री दिग्विजय सिंह जी वहां जाकर भाषण देकर आए, श्री शशि थरूर जी वहां जाकर भाषण देकर आए। आप पार्टी के श्री अमानतुल्लाह खान, जो वहां के विधायक हैं, उन्होंने वहां भाषण दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि इस आंदोलन को कॉंग्रेस का तथा आप पार्टी का एक नैतिक समर्थन है, एक अप्रत्यक्ष समर्थन है। हो सकता है कि उनकी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार में यह विषय आता हो, लेकिन मैं इसके मूल विषय पर एक बात उठाना चाहता हूं और मैं पूछना चाहता हूं, आप मुझे यह बताइए कि शाहीन बाग के मंच पर एक छोटी सी बच्ची के मुंह से अगर देश के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ हिंसक बातें कही जाएं और भीड़ उस पर ताली बजाए, उसका व्हाट्सऐप पोस्ट बनाकर सर्कुलेट करे तो आप यह तो बताइए कि स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी के दौर के नाम पर आप बच्चों के मन में कि प्रकार का ज़हर घोल रहे हैं। क्या आप उसकी निन्दा नहीं कर सकते?

मैं एक दूसरा विषय यह उठाना चाहता हूं कि ठीक है, आप देश के राजनीतिक नेता हैं, आप उस आंदोलन में जाएं। परंतु क्या आपने उन लोगों को यह स्पष्ट किया कि इस नागरिकता संशोधन कानून का आपकी समस्या से कोई लेना-देना नहीं है। यह नागरिकता संशोधन कानून में आप जबरदस्ती कर रहे हैं। आप किसी और विषय पर बोलें तो ठीक है, लेकिन आपने भी अपने कर्त्तव्य के नाते उसको यह स्पष्ट करने का काम नहीं किया। फिर उसके बाद क्या किया?

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, the amendment is anti-Constitution.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. T.K. Rangarajan, please take your seat. Nothing is going on record.

SHRI T.K. RANGARAJAN: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are a senior Member of the House. You are not supposed to intervene like this.

श्री भूपेन्द्र यादव: यह होने के बाद आपने उससे आगे एक और कदम बढ़ाया। आपने आगे कदम बढ़ाकर अपनी राज्य सरकारों से भी प्रस्ताव पारित कराया। यह तो शुक्र है कि एक दिन कपिल सिब्बल जी बहुत ईमानदारी से कह बैठे कि राज्य सरकारों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। यह अलग बात है कि कॉंग्रेस के दबाव में अगले दिन वह 180 डिग्री बदल गए। परंतु सच्चाई यही है कि आपने वापस अपने संविधान पर चोट करने का काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ठीक है, माननीय रंगराजन जी कह रहे हैं, ठीक है भारत के सामने बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए हैं, जब दुनिया के मानवाधिकार में जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। एक समय था, भारत तिब्बत के साथ खड़ा हुआ था। एक समय था, जब श्रीलंका में जिन लोगों पर अत्याचार हुए, हम उनके साथ खड़े हुए थे। दुनिया के जितने देशों में जहां-जहां अत्याचार होता है, वहां-वहां भारत का उसको नैतिक समर्थन है। मैं इस सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इतने दिनों से शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा है, क्या किसी ने भी ऐसा कहा कि हमारे पड़ोस के इस्लामिक देशों में धार्मिक आधार पर जो अत्याचार होते हैं, उसके लिए भारत सरकार को भी दबाव बनाना चाहिए। क्योंकि आप इस प्रकार की मानवता की बात नहीं करना चाहते, आप केवल राजनैतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं।

भारत और पड़ोसी देशों में क्या अंतर है? मेरे बहुत अच्छे मित्र देरेक ने संसद में एक विषय उठाया था। आप इसकी बात को समझिए, फिर आप मुझे कहिए कि यह एंटी-कंस्टीट्यूशन है। देरेक जी ने 11 दिसम्बर, 2019 को भाषण दिया था। मैं देरेक भाई के भाषण को क्वोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा -

"My grandfather and his younger brothers stayed back in India and the elder brother was in Pakistan. So, we have the O'Briens of India and the O'Briens of Pakistan in 1947. We are in touch. Now, what happened? The O'Briens of Pakistan either left to Canada, England or Australia or they married, they converted into Islam and they have gone, but the O'Briens of India because of the power of our Constitution are still standing here." इसी को पूरा करने के लिए हम लोग यह कानून लेकर आए हैं ताकि और किसी ओब्राईन को न तो जबर्दस्ती इस्लामिक बनना पड़े, न देश छोड़ने को मजबूर होना पड़े। हमने शरणार्थियों को शरण देने का काम किया है। यह भारत की संस्कृति है। यह उदात्त सहिष्णुता की, मानवता की भारत की संस्कृति है। हम अपने अड़ोस-पड़ोस के घटनाक्रमों पर आँख मींच कर

*Not recorded.

बैठ जाएँ? पाकिस्तान में 23 प्रतिशत आबादी से 3 प्रतिशत हो जाएँ और हम चुप बैठे रहें? बांग्लादेश में 30 प्रतिशत आबादी अपना देश छोड़ने को मजबूर हो जाएँ और हम चुप बैठे रहें? यह मानवता का तकाज़ा और यह भारत का तकाज़ा नहीं है। हमने भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए अब खूब नारे लगते हैं कि एनआरसी वापस लो, एनपीआर वापस लो, यह सरकार रजिस्टर बनाने आ रही है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस देश के एक बहुत बड़े स्टॉलवर्ट नेता हैं, उनका इस देश में बहुत बड़ा संसदीय अनुभव रहा है। वे भारत के राष्ट्रपति भी बने। हम सब उनका सम्मान करते हैं, श्री प्रणब मुखर्जी। वे 2003 में इस संसद की गृह मंत्रालय की स्थाई समिति के चेयरमैन थे और 2003 में पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम थी, उसमें अभी के कुछ वरिष्ठ सदस्य भी उस समय उसके सदस्य थे। मेरे सामने आदरणीय मोतीलाल वोरा जी बैठे हैं, वे उस समय होम कमेटी के सदस्य थे। कपिल सिब्बल जी उस समिति के सदस्य थे। अम्बिका सोनी जी उस समय समिति की सदस्या थीं। हमारे बिहार में आरजेडी के लोग एनआरसी को लेकर बहुत शोर मचा रहे हैं, जब कि लालू प्रसाद जी भी उस समय उस समिति के सदस्य थे। राम जेठमलानी जैसे बड़े वकील, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, हम तो उनका बहुत सम्मान करते थे, उनसे वकालत सीखी है, वे उस समिति के सदस्य थे। उस समिति ने एक रिपोर्ट दी। समिति की रिपोर्ट में कहा, "The proposed provision makes it mandatory for a person to make an application for issue of a National Identity Card. The Government, however, later on realised that that provision, as contained in the Bill, does not clearly reflect its intention to enumeration and the automatic grant of the National Identity Card. Hence, there was no need for a person to make an application for the purpose. An application was required only in case of a dispute यह समिति का प्रपोजल था, वोरा जी मेरे सामने बैठे हैं। It further says, "Accordingly, the Government has proposed to make a change in sub-section 2 of the proposed Section 14(a), which should read as under: "The procedure to be followed in compulsory registration of citizens of India shall be such, as may be prescribed." आप आज जो हमको कह रहे हैं, लेकिन समिति की यह recommendation आपने दी थी और उसके बाद इतना ही नहीं किया, कॉंग्रेस की एक स्थिति रही है कि आपको यह लगता है कि सत्ता में आप हैं, तो सब ठीक है और सत्ता में आप नहीं हैं, तो सब खराब हो रहा है। उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में अमेंडमेंट आया और कमेटी ने सेक्शन 14(ए) के संबंध में जो कहा था, उसके संदर्भ में अमेंडमेंट में क्या आया? "Issue of National Identity Card: The Central Government may compulsorily register every citizen of India and issue a National Identity Card to him." यह कब आया? यह insert कब हुआ? यह 3 दिसम्बर, 2004 को insert हुआ। मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री कब बने? वे 22 मई, 2004 को प्रधान मंत्री बने। अब बताइए?

उपसभापति महोदय, आखिर हम देश में भरमाने की राजनीति क्यों कर रहे हैं? हम देश को बार-बार क्यों बॉटना चाहते हैं? हम देश को गुमराह क्यों करना चाहते हैं? मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि यह सरकार आने के बाद जब हमने 'सबका साथ, सबका विकास', की बात की, तो हमने सबसे पहले देश के 115 पिछड़े जिलों को चुना, जिनको हमने आकांक्षी जिला बनाया। हमने उनको पिछड़ा जिला नहीं कहा, बल्कि हमने उनको Aspirational District कहा। हमने कहा कि अगर भारत आगे बढ़ा है और हमारा यह क्षेत्र पीछे है, तो आप भी आगे बढ़ें। हमारे जो 115 आकांक्षी जिले बने, क्या वे भाजपा शासित राज्य के बने? नहीं, ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि उनमें अगर आन्ध्र प्रदेश का कडपा जिला है, तो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला भी है।

अगर उसमें हमारे मेघालय और मिज़ोरम के जिले हैं, तो हरियाणा के नूह जैसे पूरे minority वाले जिले को भी चुना गया है। आपको तो खुशी होगी कि हम केरल के वायनाड जिले को भी विकसित कर रहे हैं, ताकि भविष्य में वह princely state न रह जाए। हम अमेठी में भी फैक्ट्री लेकर आ गए हैं, ताकि वह भी लोकतंत्र की अनुभूति के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें। हमने सारे जिलों को चुना है। यहाँ पर वैस्ट बंगाल के लोग बैठे हैं। वैस्ट बंगाल में नदिया जिला है, दक्षिण दिनाजपुर है। ये जिले क्यों चुने गए हैं, यह किसका संकल्प है? यह इस पूरे सदन का संकल्प होना चाहिए कि जो हमारे 115 जिले रह गए हैं, वहाँ पर महिलाओं का स्वास्थ्य, वहाँ पर शिक्षा, वहाँ पर पीने का पानी, वहाँ पर उद्योगों का विकास, वहाँ पर पर्यावरण का संरक्षण, उनका विकास क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए, मैं आपके माध्यम से सारे सदन को यह कहना चाहता हूँ कि हमें राजनीति के इस दो-मुँहेपन को बंद करना चाहिए। इन 115 जिलों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी बात रहेगी कि हम positive रहें, हम सकारात्मक रहें, लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर positive न भी रहें, तो कम से कम positive बोल दीजिए। अगर आप हमारे लिए positive बोल भी नहीं सकते, हो सकता है कि राजनीतिक मजबूरियाँ हों, आपको अच्छा नहीं लगता हो कि positive बोलें, तो कहीं positive लिख दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि लिखने से यह इस रिपोर्ट की तरह स्थायी हो जाएगा, तो लिखिए भी मत, लेकिन कम से कम positive बातों का साथ तो दीजिए। अगर आप positive बातों का साथ भी नहीं देना चाहते, तो कम से कम जो positive काम कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाओ, उनका मनोबल तो मत गिराओ और अगर इतना भी न करो, तो इस बात को तो समझो कि हम देश के 115 जिलों में सब गरीबों के हिस्से की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, कम से कम उसमें बाधा न बनिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ।

महोदय, हमने पुरानी समस्याओं का समाधान करते हुए विकास के नए रास्तों पर आगे बढ़ने का काम किया है। देश में लंबे समय से आर्टिकल 370 एक तात्कालिक धारा थी और हम जानते हैं कि जिस तरीके से जम्मू-कश्मीर का विकास होना चाहिए था, जम्मू-कश्मीर का विकास नहीं हुआ। जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र कहीं न कहीं तीन परिवारों का बंधक बनकर रह गया, लेकिन

370 को हटाने के बाद आज जम्मू-कश्मीर में 4,400 पंचायतों के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए, 300 से ज्यादा Block Development Council के चुनाव हुए और परिणाम कितना होता है कि 2018 तक -- मैं फिर 70 सालों के लिए कहूँगा, तो काँग्रेस के हमारे मित्र कहते हैं कि 70 साल मत बोलिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2018 तक केवल 3,500 घर "प्रधान मंत्री आवास योजना" के अंतर्गत बने, पर दो साल के अंदर-अंदर उनकी संख्या बढ़ी और 24,000 मकान" प्रधान मंत्री आवास योजना "के अंतर्गत बने और इस बार नैफेड ने जम्मू-कश्मीर से सेब की पूरी खरीद की। हमने जम्मू-कश्मीर के किसानों को फायदा पहुंचाने का काम किया है।

महोदय, देश में एक बहुत लंबे समय से समस्या, हमारे उत्तर-पूर्व की समस्या थी। हमारे बोडो समुदाय के लोगों की समस्या थी। बोडो मूवमेंट भी देश के अंदर चला, वह बड़ा हिंसक मूवमेंट रहा। वह मूवमेंट 20 से 30 साल तक चला। 30 साल तक उस मूवमेंट के चलने का परिणाम क्या रहा? वह 30 साल जो मूवमेंट चला, उसके कारण 4,000 से ज्यादा लोगों की जान गई, लेकिन मैं सरकार को यह बधाई देना चाहता हूँ और विशेष रूप से अभिभाषण में जिन लक्ष्यों को रेखांकित किया है कि बोडो आंदोलन में बोडो समझौता करवाकर सरकार ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों में शांति और विकास के नए रास्तों को आगे बढ़ाने का काम किया है।

इसमें चार बहुत बड़ी बातें हुई हैं। पहली, प्रधान मंत्री जी ने सरकार में आने के बाद अपनी ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाया, यह उस ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए एक सकारात्मक दिशा से उठाया हुआ कदम है। दूसरा, बोडो समझौतों के माध्यम से देश में नए राज्यों का निर्माण और क्षेत्रीय पुनर्गठन, जातीय संघर्षों को समाप्त करना और राजनीतिक स्थिरता लाने का एक अच्छा मॉडल दिया कि हम एकीकृत असम के भाग होते हुए, किस प्रकार से असम का भाग बनकर भी विकास कर सकते हैं। तीसरा, हम जानते हैं कि हमारे बगल के देश म्यांमार में और बाकी जगहों पर भी देश के पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति फैलाने के जो अड्डे बने हुए थे, हम उसमें समाधान की दिशा में आगे बढ़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे उत्तर-पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में शांति और समाधान का नया मार्ग खुलेगा। 1990 के दशक में जितने लोग इस अशांति के कारण हिंसा के शिकार होते थे, उस संख्या में बहुत बड़ी गिरावट आई है। आज हमारा पूर्वोत्तर और उत्तर-पूर्वी राज्य विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

बोडो के अलावा एक और समझौता हुआ है। मुझे लगता है कि जब हम राष्ट्रीय परिदृश्य पर बात करना चाहते हैं, तो उसका भी जिक्र होना चाहिए। हमारी जो ब्रू जनजाति है, जिनकी मिज़ोरम और त्रिपुरा में दशकों से समस्या थी और छोटा-सा समाज होने के कारण जिनकी आवाज़ दिल्ली तक नहीं आ पाती थी, उस ब्रू जनजाति का भी समझौता कराकर सरकार ने त्रिपुरा में उनकी सेटलमेंट की व्यवस्था करके एक लम्बी समस्या का समाधान करने का काम किया है।

भारत में सरकार आने के बाद हमने आर्थिक क्षेत्र में एक clean economy देने के लिए काफी कदम आगे बढ़ाए हैं। हम एक नई इलेक्ट्रोनिक पॉलिसी को लाए, Ease of Doing Business

में आगे बढ़े, उपभोक्ता खर्च में वृद्धि करते हुए देश में व्यापार को आगे बढ़ाने का काम किया, कारोबार की सुगमता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने का काम किया। देश में कर-विवाद की जो सबसे ज्यादा समस्या थी, उसका निपटारा सरकार द्वारा कर-विवाद के लिए "सबका विश्वास योजना" के माध्यम से करने का काम किया गया और निवेश में भी तेजी लाने का काम किया गया। हमने माना है कि सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के विकास को आगे बढ़ा सकती है, इसलिए इस सरकार की यह उपलब्धि रही है कि हमने 121 करोड़ लोगों को आधार और 60 करोड़ लोगों को रुपे-कार्ड दिया है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इकोनॉमी पर अपनी जो थीसिस लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि बिना economic inclusion के empowerment नहीं हो सकता है। उन्होंने हमेशा देश की मुद्रा और economic empowerment के विषयों को लेकर अपनी थीसिस दी। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि देश का जो सबसे बड़ा डिजिटल ऐप है, उसका नाम उसने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर "भीम ऐप" रखकर देश के सब गरीबों और पिछड़ों को economic inclusion देने का एक बड़ा काम किया है। महोदय, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, पर यह सच है कि यह तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि हमने उस ऐप को "भीम ऐप" नाम दिया, वरना अगर कॉंग्रेस की सरकार होती, तो नाम पर एक ही परिवार का पेटेंट होता, कोई दूसरा नाम हो नहीं सकता था।

महोदय, हम भी कहते हैं कि देश में डिजिटल क्रांति राजीव गाँधी जी लेकर आए। हम इस बात से कभी इन्कार नहीं करते। हमने अभिभाषण में यह कहा है कि जवाहरलाल नेहरू जी का आधुनिक भारत का दृष्टिकोण था, तो वह आधुनिक भारत का दृष्टिकोण था। हम ऐसे छोटे और संकुचित राजनीति के विषयों को नहीं करते, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब हम देश में economic inclusion के लिए JAM की त्रिमूर्ति- जनधन, आधार और मोबाइल को लेकर आए हैं, तो फिर आपकी तरफ से विरोध क्यों होता है? आधार को आपकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों दी जाती है? जनधन पर आपकी तरफ से इस तरह की संशय वाली बातें क्यों की जाती हैं? आप पॉजिटिव और सकारात्मक होकर, कम से कम गरीब आदमी का जो economic empowerment हो रहा है, उसके लिए हमारा साथ क्यों नहीं देते? मुझे इस संकल्प-पत्र के माध्यम से यह बताते हुए खुशी है कि इस सरकार के माध्यम से....

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक): भूपेन्द्र जी, आधार का विरोध पहले किसने किया था? यह याद नहीं है? ...**(व्यवधान)**... जीएसटी का विरोध पहले किसने किया था? ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: जयराम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: भूपेन्द्र जी, आप चेयर को ऐड्रेस करें।

श्री भूपेन्द्र यादव: उपसभापति महोदय, जयराम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... जीएसटी के समय में जो सेंट्रल टैक्स था, उसके प्रति राज्यों को यह लगता था कि केन्द्र की जो सरकार है, वह पता नहीं हमको पूरा पैसा देगी या नहीं देगी, लेकिन हमने उनको विश्वास

में लिया और विश्वास में लेकर उनसे कहा कि आपको यह पैसा मिलेगा और फिर उस विश्वास के आधार पर जीएसटी आया। सच्चाई यह है। ...**(व्यवधान)**...

श्री के.के. रागेश (केरल): *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. Please. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... Please.

श्री भूपेन्द्र यादव: आपका बजट में देंगे, समाधान करेंगे। ...**(व्यवधान)**... हमारे जो कम्युनिस्ट मित्र हैं, आज आपके ही मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि जो सीएए का विरोध कर रहे हैं, वे पृथकतावादी और सांप्रदायिक लोग हैं। आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आप किसके साथ हैं। आपने तो पत्र लिखा था कि बंगलादेश के जो लोग आए हैं, उनको नागरिकता दी। आपका स्टैंड बदल सकता है, लेकिन इसके लिए आप नैतिक रूप से स्वयं को जिम्मेदार मानेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा नहीं करता हूं। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seats. Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... Bhupenderji, please continue.

SHRI T.K. RANGARAJAN: Sir, debate and intervention are part of parliamentary proceedings. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rangarajan, please take your seat. ...*(Interruptions)*...

श्री भूपेन्द्र यादव: महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद देश की सुरक्षा को लेकर, देश की सेना को लेकर बड़े अभूतपूर्व कार्य करने का काम हमारी सरकार ने किया है। देश के सैनिक कौन हैं, किसी ने कहा है कि -

"तुम्हारे शहर के सारे दीये तो सो गए लेकिन,

हवा से पूछना कि दहलीज़ पर ये कौन जलता है!"

देश की सीमाओं पर सुरक्षा करने वाले हमारे सैनिक और हमारे देश की सेना को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि एक लम्बे समय से, जो सीडीएस का पद था, जो Chief of Defence Staff का पद था, उसको बनाकर सरकार ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है, क्योंकि पूरे देश में, हमारे पड़ोस और दुनिया भर में बड़े विकास हुए हैं, लेकिन

*Not recorded.

युद्ध की कार्य-पद्धति, प्रणाली और तकनीकों में बदलाव आया है। आज ज्यादा एकीकृत कमान की बात कही जाती है, इसलिए hybrid war are जैसा दुनिया भर में विशेष रूप से विभिन्न युद्धों से स्पष्ट है कि एकरूप पारंपरिक नियंत्रण के तहत तकनीकी रूप से सुसज्जित एकीकृत बलों के महत्व को स्पष्ट रूप से सामने रखकर सरकार के द्वारा पारम्परिक युद्ध की स्थिति से निकलकर भारत की सेना को आधुनिक बनाने का काम किया है। भारत, जो अभी तक विश्व पटल पर एक सामंजस्यपूर्ण शक्ति के रूप में उभरने का लक्ष्य बना रहा है, उसे न केवल तात्कालिक सीमाओं पर खतरे को कम करना है, बल्कि हमारे देश के सामने चुनौती है कि स्वयं के आर्थिक हितों से सक्षम होकर मित्र राष्ट्रों की सहायता करना है या अंतर्राष्ट्रीय कार्यो में सहयोग के लिए संचालन करने में सक्षम होना है। सैन्य ताकत और क्षमता, आज दुनिया में कूटनीति और खुद के हितों को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण घटक है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सीडीएस की नियुक्ति के लिहाज़ से हमारे देश के सशत्र बलों के एकीकरण के लिए एक बहुत बड़ा विषय कहा है। हालांकि सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा मंत्री जी को सलाह देने के लिए एक व्यवस्था उपलब्ध करायी है, लेकिन भविष्य में भी मिसाइल फोर्स, cyber force, Space States और स्पेशल फोर्सज़ को केन्द्र में रखते हुए दुर्लभ रणनीतिक संसाधनों को नियंत्रित करने और उसको आवश्यकता अधिकारित आवंटन करने के लिए सरकार ने रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़े कदम उठाए हैं। इसलिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा को लेकर सरकार ने आगे कदम बढ़ाए हैं।

महोदय, आज हम भारत की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो Millennium goal तय किए, उसमें उन्होंने sustainable development के लिए शहरों के goal तय किए और sustainable development का जो goan number 11 ज्न्होंने कहा कि हमारे शहर ऐसे होने चाहिए जो inclusive हों, समावेशी हों, सुरक्षित हों, सतत् हों और उसके साथ ही साथ sustainable हों, इसको देखते हुए दिल्ली में दो master plan बने, लेकिन दोनों master plan बनने के बाद भी दिल्ली की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। दिल्ली में कॉंग्रेस की सरकार रही लेकिन दिल्ली में कॉंग्रेस की सरकार ने केवल प्रमाण-पत्र जारी करने का काम किया, स्थायी समाधान नहीं किया। उसका परिणाम यह रहा कि दिल्ली में 40 लाख लोग लगातार बिना पर्याप्त सुविधाओं के रहते रहे, लोगों को अपनी संपत्ति का सही मूल्य नहीं मिला, लोगों को बैंकों के लोन नहीं मिले, लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिला, वहां सड़कें पूरी नहीं बनीं, वहां सीवर पूरी तरह से नहीं आया, वहां मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलीं। हमारी सरकार ने आने के बाद दिल्ली की 1,737 अनधिकृत कॉलोनियों को पूरा करके दिल्ली को sustainable और Millennium goal के हिसाब से एक अच्छी राजधानी बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया। दिल्ली में आज बहुत ज्यादा स्लम का एरिया है, इसलिए स्लम एरिया में भी, चूंकि लोग गरीबी के कारण जीवन जी रहे हैं और वे अपनी पूरी बात बता नहीं पाते हैं, तो हमारी सरकार ने इस दिशा में भी काम को आगे बढ़ाने का काम किया है और दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के विषय को भी आगे बढ़ाया है। उस नाते इस सरकार ने बड़ा काम किया है। मैं तो कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी

जी को यह एक आशीर्वाद रहा है कि उन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए बहुत तेज गति से करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण किया - गुरु नानक देव जी का जो जन्म स्थान है, उनके प्रकाश पर्व पर उसे पूरा करके हमारे देश के सिख समाज के लिए एक बहुत बढ़िया काम करने का अवसर उनको मिला, जिसको पूरा करने का काम उन्होंने किया है। सरकार के लिए बधाई का एक विषय और भी है। सरकार ने इस वर्ष एक और सिख गुरु, क्योंकि सिख गुरुओं ने देश में समता का संदेश दिया है, मानवता का संदेश दिया है। गुरु नानक देव जी का कहना है- "एक नूर ते सब जग उपजया" - एक ही ईश्वर के प्रकाश से हम सब प्रकाशित हैं। इस देश में जाति प्रथा के विरुद्ध, इस देश में मानवता के लिए और इस देश में सेवा और संकल्प के लिए सिख गुरुओं ने हम सब को प्रकाश दिया। सरकार ने गुरु नानक देव जी का तो 550वां प्रकाश पर्व मनाया ही, लेकिन उसके साथ-साथ गुरु तेग बहादुर जी का भी 400वां प्रकाश पर्व मनाने की बात कही है।

महोदय, हम जानते हैं कि कॉंग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज़ों ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। जिस समय उन्होंने कॉंग्रेस की स्थापना की थी, उस समय कॉंग्रेस केवल एक छोटा राजनैतिक संवाद का केन्द्र थी। लेकिन कॉंग्रेस को राष्ट्रवाद की धार देने वाले, देश में स्वराज्य का संकल्प करने वाले, देश को अपने स्वराज्य के आधार पर निर्माण करके देश में राष्ट्रवाद का ज्ञान देने वाले और गीता के कर्मयोग शास्त्र को लिखकर जिन्होंने देश में राष्ट्रवाद के विषय को प्रखर रूप से आगे बढ़ाया है, उन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की भी 100वीं जयंती मनाने का संकल्प इस सरकार ने किया है। हमारा यह मानना है कि तिलक महाराज का जो राष्ट्रवाद है, उसी राष्ट्रवाद के आधार पर आज हम चल रहे हैं। इसलिए कॉंग्रेस को अपनी अंतरात्मा में भी झांकना चाहिए कि तिलक महाराज के दिए गए राष्ट्रवाद और गीता के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए हम अपने देश को स्वराज से सुराज की ओर ले जाएं, इसलिए इस अभिभाषण में सरकार ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं जयंती मनाने का जो कार्यक्रम किया है, उसमें कहा है कि सरकार उनके सुराज के आदर्श पर चलते हुए कार्य-संस्कृति में परिवर्तन, पारदर्शिता और जमीनी स्तर पर काम को आगे बढ़ाने का काम करेगी।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक लंबे समय से हमारे देश के अंतर्गत बहुत सारे विषयों को बांटा गया है। मैं कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी ने हमेशा अपना भजन गाया: रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम।...**(व्यवधान)**... और इस देश में ..... **(व्यवधान)**... और इस देश में ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया बैठकर न बोलें।

श्री भूपेन्द्र यादव: राम इस देश के सांस्कृतिक प्रतीक हैं और इसलिए इस सरकार ने बहुत पुराने राम मंदिर के विषय को न्यायालय के द्वारा सुलझाकर एक अच्छा कार्य किया है और हजारों भारतवासियों के मन में यह एक दिव्य सपना है और केवल भारत में ही नहीं, भारत में आगे

भी सब विषयों को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए इस संकल्प पत्र में यह कहा गया है कि यह सारा काम करते हुए...**(व्यवधान)**...

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): *

श्री उपसभापति: आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। प्लीज़... प्लीज़। भूपेन्द्र जी, आप चेयर को संबोधित करें।

श्री भूपेन्द्र यादव: उपसभापति महोदय, मैं यह कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि आखिर कॉंग्रेस इस बात का जवाब दे कि उन्होंने 70 साल में इस विषय को क्यों नहीं सुलझाया और अब जब यह विषय सुलझाने के लिए न्यायालय में आया, तो न्यायालय में तथ्यों पर argument न करके, political argument करके मामले को उलझाने का प्रयास क्यों किया गया है? जिन्होंने इसे उलझाने का प्रयास किया, जिन्होंने इसके राजनीतिकरण करने का प्रयास किया, कपिल सिब्बल जी का नाम क्यों कहलवा रहे हो मेरे मुंह से? जिन्होंने इसे उलझाने का प्रयास किया, जिन्होंने लगातार सारे विषयों को उलझाए रखा, वे स्वयं अपने आप में झांके। हम देश को बनाने के लिए, पॉज़िटिव बात करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। इस संकल्प-पत्र में यह कहा गया है कि कर्तव्य पथ पर यह सरकार आगे बढ़ती रहेगी। मैं सरकार को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि सरकार के संयोजन में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में "चन्द्रयान-2" में पूरे देश में, इस देश के नौजवानों में ऊर्जा और तकनीकी के लिए एक उत्साह का माहौल निर्मित हुआ। उसके साथ-ही-साथ सरकार ने तुरंत "चन्द्रयान-3" को स्वीकृति प्रदान की और "चन्द्रयान-3" की स्वीकृति के साथ-साथ इसरो के माध्यम से "गगनयान" और "आदित्य-1" मिशन को भी आगे बढ़ाने का संकल्प इस सरकार ने किया है।

महोदय, 2014 के बाद जो यह यात्रा चली है, इस यात्रा में देश की कृषि के क्षेत्र में, देश की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, देश के विकास के क्षेत्र में, शासन में पारदर्शिता के स्तर में यह देश आगे बढ़ा है। ...**(व्यवधान)**... सर, मैं correction के नाते कहना चाहता हूं कि सन् 2020 में लोकमान्य तिलक महाराज की पुण्यतिथि का जो कार्यक्रम है, उसको आगे बढ़ाते हुए सरकार ने कर्त्तव्यपथ पर इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए हमारी आप आलोचना करते हैं, करिए, लेकिन देश में कम से कम आपसी विभाजन का वातावरण मत बनाइए; आप हमारा विरोध करते हैं, करिए, लेकिन लोकतंत्र में ईवीएम पर किसी प्रकार का प्रश्नचिन्ह मत लगाइए; आप राजनैतिक रूप से हमें पसंद नहीं करते, मत करिए - आप राजनैतिक प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, लेकिन देश में विकास का positive और सकारात्मक मार्ग अपनाइए क्योंकि हम यह तय करके आए हैं कि:

"चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो,

कुछ भी करो, कर्तव्य पथ से किन्तु भागूंगा नहीं।"

---

*Not recorded.

बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Sudhanshu Trivedi to make his speech seconding the Motion.

डा. सुधांशु त्रिवेदी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, अभी भूपेन्द्र यादव जी ने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो अपने विचार रखे हैं, मैं उनका अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम सबने राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण सुना। दोबारा इस सरकार के आने के बाद विगत 6 महीने में जो कुछ भी कार्य हुए, निर्णय हुए, उन पर सदन के दोनों तरफ बैठे हुए लोगों के विचार अलग-अलग हो सकते हैं, मत अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है, जिससे इस सदन में बैठा हुआ हरेक व्यक्ति और राजनैतिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हरेक व्यक्ति आज के समय में प्रभावित है। वह है, crisis of credibility in politics - राजनीति में विश्वसनीयता का संकट। एक आरोप लगता था कि लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, लेकिन आपने देखा कि विगत 6 महीने में इतने निर्णय हुए - चाहे ट्रिपल तलाक हो, धारा 370 हो, आतंकवाद विरोधी अधिनियम का विषय हो, सीएए का विषय हो - सबके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन इन सबने भारत की जनता में कम से कम एक बात स्थापित की कि जो कहा जाता है, वह किया जाता है। यानी crisis of credibility को समाप्त करने में, मैं मानता हूं कि पिछले 6 महीने एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। साथ-ही-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब crisis of credibility के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है तो कार्य और मार्ग इतना आसान नहीं होता है। उसके ऊपर बहुत से कांटे बिछे हुए होते हैं, लेकिन उन कांटों के बीच में से सहजता से चलते हुए आगे जाने की प्रेरणा हमें मिलती है, जब हम कहते हैं कि:

"श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्ण मार्ग, स्वयं स्वीकृत न: सुगं कार्येत।"

यानी कांटों से भरे हुए मार्ग के बीच में से स्वयं सुगम मार्ग बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीने में जो कुछ हुआ, उसके लिए मैं यह पंक्ति कहना चाहूंगा कि:

"दर्द की रात गयी, ग़म के ज़माने भी गए,

मोदी जी की हिम्मत से, कई दाग पुराने भी गए।"

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : आप गलत बोल गए। 6 महीने से पहले पांच साल भी थे।

डा. सुधांशु त्रिवेदी : सर, 6 महीने में जो कुछ हुआ है, राष्ट्रपति महोदय ने उन 6 महीने के विषय में बोला है। अब मैं इस पर आ रहा हूं कि पिछले वर्षों में क्या हुआ। राष्ट्रपति महोदय

ने अपने अभिभाषण के बिन्दु क्रमांक 59 और 60 पर एक विषय का उल्लेख किया, जो था, "प्रशासनिक सुधार और प्रशासन की सुगमता"। जब भी कोई सरकार काम करती है तो मानी हुई बात है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय यह होता है कि administratively चीज़ों को किस ढंग से बेहतर किया जा सके, प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे सुगम किया जा सके। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि इसके लिए तीन बिंदुओं की आवश्यकता होती है। एक - कार्यक्षेत्र का मनविज्ञान ज्ञान बदलने का प्रयास करना, transforming the work culture, दूसरा आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना, using the modern technology और तीसरा होता है - जमीनी स्तर पर सरकारी व्यवस्थाओं और प्राइवेट व्यवस्थाओं के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण करना, promoting a healthy competition at the grassroot level. अब आप देखिए कि जब हम प्रशासन शुरू करेंगे, तो आज तक सरकारें यह विचार करती रहीं कि कार्य को और बेहतर ढंग से संपादित करना है, कुछ और नए नियम बना दिए जाएं, परंतु मैं यह बताना चाहूंगा कि आने के साथ विगत पांच वर्षों में सरकार ने सबसे पहले यह ढूंढ़ा कि ऐसे कौन-कौन से नियम हैं, जो अप्रासंगिक हो गए हैं, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कालबाय हो गए हैं, redundant हो गए हैं, तो विगत 6 महीनों में हटाए गए 58 नियमों को मिलाकर डेढ़ हजार ऐसे नियम हैं, जो पूरे तरीके से सरकार ने समाप्त किए, जिसके द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था ज्यादा बेहतर ढंग से चल सकती है। आप सभी ने देखा कि कर्मचारियों के चयन में चाहे इंटरव्यू को समाप्त करना हो या अभी हाल ही में बजट में National Recruitment Agency को स्थापित करना हो, ताकि बेहतर, सुगम और पारदर्शी तरीके से चयन हो सके अथवा सर्वोच्च स्तर पर जहां इस वैश्विक युग में हमें उच्च स्तर की दक्षता चाहिए, व्यावसायिक दक्षता चाहिए, professional competence चाहिए, तो उसके लिए lateral entry का विषय हो। इस प्रकार के बड़े प्रशासनिक कदम विगत पांच-साढ़े पांच वर्षों में सरकार ने उठाए हैं। इसके साथ-साथ जब आधुनिक टेक्नोलॉजी की बात होती है, जैसा भूपेन्द्र जी ने कहा कि digital technology का कैसे प्रयोग किया जाए, उसके लिए आवश्यक था कि पहले उसके उपादान तो बना लिए जाएं। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 5 अगस्त, 2014 को जब प्रधान मंत्री जी ने लाल किले से अपना पहला उद्बोधन दिया था, तो उन्होंने क्या विषय उठाया था? उन्होंने जन-धन का विषय उठाया था, यानि उन्होंने वहीं से यह संकल्प लिया कि जो 50 प्रतिशत लोग बैंक से जुड़े हैं, यदि हम उसे शत प्रतिशत पहुंचाएंगे, तो वह उपादान बनेगा, वह आलम्बन बनेगा, जो सीधे कम से कम विकास के स्रोतों को सबंधित व्यक्ति तक पहुंचा सकेगा।

इस दूसरी पारी में आते हुए, हम Direct Benefit Transfer यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के द्वारा उन लोगों के हाथ में सीधे और सम्पूर्ण सरकारी लाभ पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। यह हमारी एक बड़ी उपलब्धि थी। इतना ही नहीं, जो Civil Services हैं, उनमें Common Foundation Course, सभी प्रकार की Civil Services के लिए और इसके साथ-साथ यह भी ध्यान रखा गया कि जो लोग दिव्यांग हैं, जिनके बच्चे दिव्यांग हैं, उन कर्मचारियों के शैक्षिक व्यय के ऊपर मिलने वाली सुविधा को दुगुना करने का प्रयास किया गया। दूसरी तरफ जो अक्षम अधिकारी

हैं, उन्हें व्यवस्था से बाहर किया गया, चाहे रिटायर हुए अथवा कार्रवाई की गई। अगर हम देखें, तो प्रशासनिक व्यवस्था को सुगम करने के लिए सरकार ने पांच वर्षों में बहुत बड़े स्तर पर कार्य किए और इन छः वर्षों में उनको आगे बढ़ाया। महत्वपूर्ण बात यह रही कि पिछले वर्ष दिसम्बर से हम सब आदरणीय अटल जी के जन्मदिन को Good Governance Day के रूप में मनाते हैं और 25 दिसम्बर, 2019 को Good Governance Day के दिन सरकार ने एक निर्णय लिया कि अब एक Good Governance Index होगा, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, यानी Union Territories के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण करेगा कि कौन कितना बेहतर प्रशासन चला रहा है। इसके लिए सरकार ने 10 क्षेत्रों का निर्धारण किया और 50 indicators को तय किया। वे दस क्षेत्र हैं - agriculture, commerce and industry, human resource development, public health, infrastructure, economic governance, social welfare, judiciary and public security, environment and citizen-centric governance. एक प्रकार से हमने एक व्यवस्थित स्वरूप बनाया कि केंद्र सरकार ही नहीं राज्य सरकारें भी उस व्यवस्थित ढांचे में आकर बेहतर प्रशासन दें और एक दूसरे के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण करें। इतना ही नहीं जो पेन्शनर्स हैं, जो अधिक बुजुर्ग हो जाते हैं, 80 साल से ऊपर के हैं, उनको अपना प्रमाणपत्र देने के लिए आने में असुविधा होती है, तो उसके लिए digital technology और App के माध्यम से उनको अपने life certificate को प्रदान करने की सुविधा को भी सरकार ने व्यवस्थित किया। हम सभी जानते हैं और यह विषय प्रधान मंत्री जी कई बार बता चुके हैं कि सरकारी कार्यों में जो छोटी चीज़ें हैं, GeM के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उससे अब तक 40 हजार करोड़ रुपये का गवर्नमेंट रेवेन्यू का उपयोग उसमें किया जा चुका है। अभी भूपेन्द्र जी ने उस बात को बताया है, इसीलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि financial sector में जितने reforms हुए हैं, tax के बड़े reforms से लेकर, हाल ही में जब Budget आया, तो Income Tax payers charter यानि tax payer charter की भी एक बात हुई है, जिसमें टैक्स पे करने वाले को अपने अधिकार का संरक्षण करने और व्यवस्था में पारदर्शिता को देखने का अधिकार प्राप्त होगा, यह एक और बड़ा प्रशासनिक सुधार है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब हम बड़े विकास की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो प्रशासनिक सुधार के साथ नई व्यवस्थाओं को भी देखना पड़ता है, जैसे भारत बहुत तेजी से अब विकसित महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। पिछले समय में हमने International Solar Alliance बनाया था और इस बार हमने Gas Grid की शुरुआत की है अर्थात clean energy जो पर्यावरण के अनुसार उपयोगी ऊर्जा हो, उस दिशा में आगे बढ़ने का हमने प्रयास किया है। अब इसका उल्लेख भी उन्होंने किया कि यदि हम देश के सुदूर कोने में खड़े हुए किसी ग्रामीण, गरीब, मजदूर, किसान, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले इन्सान के हाथ में शक्ति देना चाहते थे, तो भारत की सुरक्षा की शक्ति जो सैन्य बलों के हाथ में है, उनमें भी सुगम संचालन के लिए बेहतर समन्वय व्यवस्था भी करना चाहते थे, तो एक बहुत बड़ा administrative reform यह भी हुआ कि दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों में CDS है, Chief of Defence Staff, परन्तु वह हमारे यहां नहीं था और उस व्यवस्था

की शुरुआत हुई। इससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था भी एकरूपता के ढंग से आगे बढ़ सकती है।

उपसभापति जी, इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जब हमने प्रशासनिक सुधारों की बात कही, तो DBT से लेकर GST तक और GST से लेकर CDS तक कोई भी क्षेत्र हमने छोड़ा नहीं है, लेकिन मोदी जी का यह विचार है कि बाकी लोग तो कहते हैं कि मुझे अमुक वर्ग के लिए करना है, अमुक क्षेत्र के लिए करना है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत लोगों के लिए करना है, परन्तु हमें सबके लिए करना है, क्योंकि हमारा सिद्धांत "सर्वे भवन्तु सुखिन:" है। अब इन विचारों की प्रेरणा भी स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों और संविधान में जिन लोगों ने योगदान दिया, उनसे हमें मिलती है। जैसा कि अभी बताया गया कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्य तिथि का यह शताब्दी वर्ष है। उन्होंने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर देखा जाए, तो हम सबने किताबों में एक शब्द पढ़ा था, जो उनके लिए कहा जाता था कि वे भारतीय असंतोष के जनक थे। मैं कहना चाहूंगा कि यह उचित नहीं है, बल्कि उनके लिए कहना चाहिए कि वह भारतीय स्वराज्य के उद्घोषक थे। यह एक महत्वपूर्ण बात है। जब उन्होंने यह बात कही थी, तो मेरे विचार से, कॉंग्रेस पार्टी इतनी पुरानी है, उन लोगों को ध्यान होगा, तिलक जी के विचार को क्या कहा गया था, यह थोड़ा right wing fundamentalist की बात है। उस समय तक तो विचार यह था कि Executive Council में अधिक से अधिक concessions प्राप्त करने हैं। स्वराज्य का विषय एकदम नया विषय था। यह एक नया विषय लाया गया। कॉंग्रेस को 25 साल लगे उस स्वराज्य के विषय को अंगीकार करने में, जब 26 जनवरी, 1930 को लाहौर कॉंग्रेस अधिवेशन में रावी के तट पर स्वराज्य का वह प्रस्ताव पारित हुआ, तिलक जी के यह संसार छोड़ने के 10 साल बाद, मगर स्वराज्य का वह कार्य, उनकी शताब्दी पूरी होने के बाद, हम उसका वहन करेंगे और उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे।

अब मैं अगले विषय पर यह बताना चाहता हूं कि आजकल बड़ी चर्चा होती है, बड़ा right wing है, बड़ा fundamentalist है। मैं कहना चाहूंगा कि जब तिलक जी ने कहा, तो उनको थोड़ा extremist बात कही गई थी, मगर हर 20 साल में ये परिभाषाएं बदल जाती हैं। उन्होंने 1905 में कहा और 1925-30 आते-आते लोकमान्य तिलक जी के साथी गोपाल कृष्ण गोखले और गोखले जी के शिष्य महात्मा गांधी, उनके नेतृत्व में स्वराज आंदोलन एक यथार्थ हो गया, यानि जो extreme righ wing कहा जाता था, वह अब reality और moderate हो गया था। अब कॉंग्रेस में extreme right wing कौन थे, मदनमोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, यहां तक कि यह कहा जाता था जिनको so-called Hindu leaning वाले लोग कहते थे - सरदार पटेल जी, डा. राजेन्द्र प्रसाद जी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी और 20 साल गुजरे, तो आज़ादी मिल गई और ये सब सरकार के हिस्से हो गए। जिसे आप right wing कहते थे, वह अब moderate हो गये। अब right wing कौन था? जो आप हमारे संस्थापक लोगों के बारे में कहते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में कहते थे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और 20 साल गुजरे, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद स्वीकार्य हो गया। लोहिया जी ने कहा कि मैं राष्ट्रवादी, समाजवादी

हूं और दीनदयाल जी ने कहा कि मैं समाजवादी, राष्ट्रवादी हूं। अब इस right wing के प्रतीक कौन थे, 70 के दशक में, अटल बिहारी वाजपेयी जी, "हिन्दू तन मन हिन्दू जीवन रग-रग हिन्दू मेरा परिचय" और 20 साल गुजरे, 90 का दशक आया, अब अटल जी स्वीकार्य थे, अब आडवाणी जी right wing थे, और 20 साल गुजरे 2010 का दशक आया, अब आडवाणी जी स्वीकार्य थे, मोदी जी आपको नजर आते हैं। महोदय, मगर इन पूरे 100 सालों के कार्यक्रमों को देखिए, तो व्यवस्थाएं क्रमश: उस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, आप right wing कहते हैं। आपको कालचक्र की इस गति को भी समझना चाहिए।

महोदय, अब मैं एक बात और बताना चाहता हूं। मैंने बचपन में पढ़ा था कि जब तिलक जी, वर्ष 1916 के लखनऊ काँग्रेस अधिवेश में न आए, तो वर्ष 1907 में सूरत में नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था और वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों का समन्वय हुआ, परन्तु दोनों दलों में, सहज स्वीकार्य, लोकमान्य तिलक थे और स्थिति यह थी कि लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर जब उनकी ट्रेन आई, तो उनके लिए जो बग्घी लगाई गई थी, जिसमें बैठकर वे मोती नगर में सभा स्थल पर जाएंगे। मुस्लिम लीग ने अपना अधिवेशन रफायाम क्लब में किया था, परन्तु क्या हुआ कि तिलक जी आकर बग्घी की तरफ बढ़े, तो एक नवयुवक ने जाकर बग्घी से घोड़े को खोला और वह स्वयं उस बग्घी में जुत गया और देखते-देखते तमाम नवयुवक आकर जुत गए और वह जो पहला नवयुवक था, जिन्होंने बग्घी से घोड़ा खोलकर, घोड़े की जगह खुद जुतकर बग्घी को खींचना प्रारम्भ किया, वे थे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल। यह इस बात का प्रतीक है कि वे किस प्रकार से इंस्पायर करते थे।

महोदय, आजकल भी राम प्रसाद बिस्मिल जी की बातों का बड़ा उल्लेख हो रहा है। कई जगहों पर प्रदर्शनों में बड़े चित्र दिख रहे हैं और बोला जा रहा है-

"सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।

देखना है जोर कितना बाजु-ए-कातिल में है?"

मगर आज जिन मुद्दों को लेकर, जिस तरीके से और जिस प्रकार के विचार व्यक्त किए जा रहे हैं, उन्हें देखकर तो मुझे लगता है -

"सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।

ओ रे बिस्मिल काश आज आते हिन्दोस्तां।

देखते सारे प्रोटेस्टर्स क्या टशन और थिल में हैं।"

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग आज उनके बारे में विचार कर रहे हैं, उन्होंने उन विचारों को पढ़ा, लेकिन समझा नहीं। अब फिर क्या विचार शुरू हो जाता है-संविधान के अनुसार कार्य होना चाहिए। संविधान में सबको अधिकार दे रखे हैं। संविधान में सबको मौलिक

3.00 P.M.

अधिकार दे रखे हैं और उन मौलिक अधिकारों के अनुसार सारे कार्य होने चाहिए।

उपसभापति महोदय, आजकल जब संविधान के अनुसार कार्य करने की बात आती है, तो मुझे ध्यान आया कि संविधान को देखा जाए और संविधान की मूल प्रति पर भी थोड़ी दृष्टि डाली जाए। जब संविधान की मूल प्रति के उस हिस्से को देखा, जिसमें मूल अधिकारों की बात है, तो संविधान सिर्फ अक्षरों से लिखी हुई एक किताब नहीं है, बल्कि वह जीवन्त प्रेरणा का एक स्रोत है, जिसके अन्दर मूल्य होते हैं। इसीलिए जब यह संविधान बना, तो यह विचार किया गया कि केवल लिखे गए शब्दों से नहीं, अपितु इसके अंदर प्रेरणा के स्रोतों की कुछ अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए। अत: उसके अंदर कई चित्र भी डाले गए। श्री नन्द लाल बोस, जो कि प्रख्यात चित्रकार थे, उन्होंने चित्र डाले, तो मैंने देखा कि जिस हिस्से में अधिकारों का वर्णन है, अगर आप देखें, तो उसके ऊपर चित्र किस का बना है? मैं दिखाना चाहता हूं कि उसके ऊपर चित्र बना हुआ है-भगवान राम का। यह चित्र मैं दिखाना चाहता हूं। यह संविधान की मूल प्रति मेरे हाथ में है। अगर आज हम यह बात कहें और अगर आज भगवान राम का विषय किसी सरकारी पुस्तक के ऊपर भी आ जाए, तो मेरे विचार से बहुत बड़ा वितंडावाद खड़ा हो जाएगा, परन्तु संविधान निर्माताओं के विचार में सारे अधिकार मर्यादा की सीमा के अनुसार हैं। शायद इसीलिए उन्होंने उस पृष्ठ के ऊपर भगवान राम के उस चित्र को रखा। आपने अभी देखा भगवान राम का विषय, राम जन्मभूमि का विषय भी, सभी मर्यादाओं और व्यवस्थाओं को पूर्ण करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम का वह विषय पूरी मर्यादा के साथ अपने मुकाम तक पहुंचा।

महोदय, इसे देखकर एक बात मेरे मन में आई कि इस मुकदमे में पैरोकार स्वयं श्री राम लला विराजमान थे और श्री राम लला 70 साल तक कोर्ट में विराजमान रहे और उनसे मांगे गए कागज कि जन्मभूमि के कागज दिखाओ। पूरे कागज, 500 साल पुराने भी दिखाइए, क्योंकि सुबूत के आधार पर ही निर्णय होगा।

उपसभापति महोदय, कागजात सिर्फ संस्कृत और हिन्दी में नहीं, अंग्रेज़ी में नहीं, बल्कि कागज फारसी में भी दिखाने पड़े, जो फारसी के कागज थे। यह प्रमाण, हमारे विरोध पक्ष के श्री कपिल सिब्बल जी, उसमें रहे थे, उन्होंने तो वे फारसी के कागज भी देखे होंगे। कहावत है-

"हाथ कंगन को आरसी क्या,

पढ़े-लिखे को फारसी क्या?"

उन्होंने दिखाया और जो लोग काफी ऊँचे-ऊँचे हाथ उठाकर कहते थे कि कागज और सबूत के आधार पर ही राम लला जहाँ विराजमान हैं, वहाँ तय होगा, किसी यकीन पर नहीं तय होगा,

वे आज कहते हैं कि हम जहाँ विराजमान हैं, वहाँ मान लो, कागज दिखाने की जरूरत नहीं है।

उपसभापति जी, इसे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि,

"रामचन्द्र कह गए सिया से
ऐसा कलयुग आएगा कि,
राम लला तो कागज देंगे,
बाकी कोई न दिखाएगा।"

मैं इसके आगे यह कहना चाहता हूं कि आज ...**(व्यवधान)**..

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): कौआ मोती खाएगा।

डा. सुधांशु त्रिवेदी: नहीं, वह तो बहुत लंबे समय तक के लिए हो चुका। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी भूपेन्द्र यादव जी ने जिस बात का उल्लेख किया, 2003 की समिति का उल्लेख किया, उन्होंने उसका उल्लेख कर दिया कि Citizenship (Amendment) Act के लिए 2003 में Ministry of Home Affairs की जो कमेटी बनी थी, जिसकी अध्यक्षता श्री प्रणब मुखर्जी कर रहे थे, उन्होंने सदस्यों के नाम भी बता दिए, मैं उसमें सिर्फ दो प्वाइंट्स add करना चाहूंगा। उसमें एक सदस्य श्री जनेश्वर मिश्र भी थे, जिन्हें छोटे लोहिया कहा जाता था। मेरे विचार से आज कोई भी समाजवादी यह दावा नहीं कर सकता कि वह जनेश्वर मिश्र जी से बेहतर संवैधानिक, सामाजिक या राजनीतिक समझ रखता हो। उस कमेटी की रिपोर्ट के बिंदु क्रमांक 9 में एक महत्वपूर्ण बात लिखी थी। उसमें लिखा था कि बंगलादेश की minorities को refugee category में citizenship देनी है। इसमें आगे लिखा था - majority को refugee category में नहीं देनी है। अगर आप 2012 का वह असम काँग्रेस का अधिवेशन देख लें, 2012 का श्री तरुण गोगोई जी का वक्तव्य देख लें, 2003 का मनमोहन सिंह जी का सदन में दिया हुआ वक्तव्य देख लें या 2012 को कोझिकोट का कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन देख लें, तो वह सब तो ठीक है, लेकिन जब संसदीय समिति में उन सारे महत्वपूर्ण लोगों ने लिखा कि इसको देना है, इसको नहीं देना है, तब इसके बाद मैं नि:शब्द हो जाता हूं।

उपसभापति महोदय, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं लिखे हुए शब्द को देखूं या बोले हुए शब्द को देखूं? जब लिखे हुए शब्द और बोले हुए शब्द में इतना अंतर आता है, तब मुझे वही गाना याद आता है कि,

"देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान
कितना बदल गया इंसान।"

SHRI P. BHATTACHARYA: Can I say something?

श्री उपसभापति: अगर वे yield करते हैं, if he yields, then I have no problem. ...*(Interruptions)*...

डा. सुधांशु त्रिवेदी: पहले मैं अपना वक्तव्य पूरा कर लूं, उसके बाद आप जो उचित समझें।

उपसभापति जी, अब मैं ...**(व्यवधान)**...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I have a point of order. जो भी चर्चा होती है, वह नियमों पर आधारित होती है। यहाँ पर कई सदस्यों का नाम जरूर लिया गया है, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, वह चाहे पूर्व राष्ट्रपति जी का ही नाम क्यों न लिया गया हो। मैं इस पर आपत्ति की कोई बात नहीं कह रहा हूं। यहाँ पर हमारे वर्तमान सदस्यों का भी नाम लिया गया है। सदन में जब दूसरा पक्ष बोलेगा, तब वह उस बात को स्पष्ट करेगा। सदन में वह भी कहा गया, जो नहीं कहना चाहिए, सदन में विपक्षी दल के लिए आप अपनी बात रखें कि जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी, जिसका जिक्र किया जा रहा है, वह बात गलत है। मैं इस record को ठीक करना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस का stand बड़ा clear रहा था कि जो सर्वोच्च न्यायालय कहेगा, हम उसको स्वीकार करेंगे।

उपसभापति जी, आखिरी बात यह है कि जिस समिति का आपने जिक्र किया है, माननीय पि. भट्टाचार्य जी उसके सदस्य रहे हैं, इसलिए इनका अधिकार भी बनता है, कृपा करके इन्हें बोलने का अवसर दें। ऐसा मेरा आपसे भी आग्रह है, ताकि यदि आपका भी कोई स्पष्टीकरण हो, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**... इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**... कर सकते हैं।... yield करें। ...**(व्यवधान)**... यह भी परंपरा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आनन्द शर्मा, जी आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI P. BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, I have a point of order.

श्री भूपेन्द्र यादव: मैं एक मिनट में अपनी बात कह रहा हूं। मेरे तथ्यों में ऐसा नहीं था कि कॉंग्रेस पार्टी थी, लेकिन अगर कॉंग्रेस पार्टी है तो मैं उस record को करेक्ट करता हूं, परंतु जिन्होंने argument किया था वे कॉंग्रेस के नेता थे, आप इससे इंकार नहीं कर सकते हैं। शाहीन बाग में दिग्विजय सिंह जी गए, वे कॉंग्रेस के नेता थे ...**(व्यवधान)**... वे प्रतिनिधित्व के लिए गए और वह एक factual बात है, जो सबके सामने है।

डा. सुधांशु त्रिवेदी: उपसभापति महोदय ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: सुधांशु जी ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: मैं एक चीज़ जरूर कहूंगा कि भूपेन्द्र यादव जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वकील हैं, इस सदन में कई लोग हैं, हमने भी वकालत की है, वह सही है, माननीय उपसभापति महोदय आप भी हैं और इन्होंने जिनका जिक्र किया है, वे भी देश के बड़े वकीलों में से हैं। वकील किसके मुकदमे की पैरवी करे, वह वकील का अपना अधिकार है। जिस दल से आप हैं, अगर मैं कहूं कि आपके दल के, जिसका आपने नाम भी लिया, उन्होंने इंदिरा गाँधी जी के हत्यारों की भी वकालत की थी, तो वकील की बात को आपके दल से जोड़ा जाए, यह उचित नहीं होगा।

श्री उपसभापति: माननीय आनन्द जी, मैं वकील नहीं हूँ, पर वकीलों की बात बड़े ध्यान से सुनता हूँ।

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, चूँकि मेरा नाम लिया गया है, तो मैं clarification देना चाहता हूँ। कोई भी वकील अपने तथ्यों का argument कर सकता है, पर यह नहीं कर सकता है कि आप यह matter इसलिए adjourn कर दो कि बीजेपी जीत जाएगी। इसलिए वह तो political argument हुआ। आपने facts पर कब argument किया? आपने तो political argument किया, तो उसको political ही कहा जाएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज़, प्लीज़। अब माननीय प्रदीप जी को बोलने दें। ...**(व्यवधान)**... प्लीज, आपकी बात में कमिटी की बात उठी थी। माननीय प्रदीप जी, आप बोलिए।

SHRI P. BHATTACHARYA: The hon. Member, without knowing the fact, is coming out with a statement that all the Members of the Committee supported the Citizenship Amendment Bill or that this amendment was supported by all the Members of the Committee. That is not correct. I had given the amendments. We had given dissent note. ...*(Interruptions)*... Let me explain it. That is written. I have given it in writing. You can check the record. You will find out all these things. Why are you saying that all the Members agreed with this thing? You are misleading the House. How can you do this thing? I personally did that. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: माननीय प्रदीप जी, धन्यवाद। आपने कह दिया, now, let him speak and explain. ...*(Interruptions)*... You please take your seat.

डा. सुधांशु त्रिवेदी: उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा, आप रिकॉर्ड में देख लें, मैंने कहीं यह शब्द नहीं बोला है कि सभी सदस्य सहमत थे। यदि वह dissent है, तो वह उनका अधिकार है। Dissent तो तत्कालीन चेयरमैन को दिया गया होगा जिसके चेयरमैन तो प्रणब मुखर्जी साहब थे।

अब मैं अगले विषय पर आता हूँ। देखिए, जब CAA का विषय आता है, तो आजकल दो विषय और उठाए जाते हैं कि एक तो यह संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है और दूसरा

यह भारतीय संस्कृति की भावना के अनुरूप नहीं है। मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति तो वह रही है कि हमने शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा के लिए ऐसे-ऐसे उदाहरण दिए हैं, जो आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे। भारतीय पुराणों में और बौद्ध जातक कथाओं में राजा शिबि का उल्लेख आता है। एक कबूतर, जिसको बाज पकड़ रहा था, वह उनकी शरण में आ जाता है और कहता है कि मेरे प्राणों की रक्षा करिए। राजा शिबि कहते हैं कि ठीक है, मैं रक्षा करूँगा। वे बाज को कहते हैं कि यह मेरे शरणागत हो गया, अब यह तुम्हें नहीं मिलेगा, तो बाज कहता है कि मैं भी तो आपकी प्रजा हूँ, यह मेरा भोजन है, आप मुझे अपने भोजन से वंचित कैसे कर सकते हैं। फिर राजा शिबि कहते हैं कि यह भी ठीक है, तो अब मैं इस शरणागत को नहीं छोड़ूँगा, परन्तु यदि तुम्हें भोजन चाहिए, तो अपने शरीर से उतना ही माँस निकालने को तैयार हूँ। चूँकि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे, पुराणों और जातक कथाओं में ऐसी मान्यता है कि उसका weight बढ़ता चला गया और आखिर में राजा शिबि पूरे पलड़े में बैठ गए। तब भगवान ने प्रकट होकर कहा कि तुमने शरणागत की रक्षा का पूरा दायित्व निभाया, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। शायद इसीलिए अटल जी ने यह पंक्ति लिखी थी,

"मैंने छाती का रक्त पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल,
मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्थल वर विशाल,
शरणागत की रक्षा की है मैंने जीवन भी देकर,
विश्वास नहीं यदि आता, तो यह साक्षी है इतिहास हमारा।"

अब कहा जाएगा कि आप शरणागत को दे रहे हैं, तो सबको क्यों नहीं दे रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति में यदि राजा शिबि के कबूतर की कथा है, तो तक्षक नाग की भी कथा है। राजा परीक्षित को श्राप मिला था। वह यह था कि कोई साँप आकर उनको मारेगा। उन्होंने पूरी व्यवस्था कर ली थी। उसके बाद फलों के बीच में घुस कर एक छोटा सा सर्प तक्षक अन्दर पहुँचने में सफल हो गया, उसने राजा परीक्षित को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अब इस बात से सबक लेकर उनके पुत्र राजा जन्मजेय ने एक ऐसा यज्ञ किया था, जिसमें सारे के सारे नाग आकर भस्म होने लगे थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दूध भी पिलाते हैं, परंपरा है हमारे मित्र, किन्तु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले हैं। इसलिए घुसपैठिए और शरणागत, दोनों के नीर-क्षीर विवेक की क्षमता हमें भारतीय संस्कृति और परंपरा भी देती है।

अब हम आधुनिक समय में आएँ, तो कहा जाता है कि साहब, आप बराबरी का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप गंगा-जमुनी तहजीब के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह 'गंगा-जमुनी तहजीब' word कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग होता है, जब मुगल शहजादे दारा शिकोह ने अपनी किताब लिखी - मज्म उल बहरैन, जिसका मतलब होता है दो समुद्रों का मिलन, विलय। अब आप बताइए, जिसे दो समुद्रों का मिलन कहता है,

वह आदर्श नहीं, बाकी दूसरे लोग आदर्श हैं। इस देश की गंगा-जमुनी तहज़ीब तो यह थी कि बुल्लेशाह ने वह बोला था, जो किसी को भी सुनने में आज बड़ा अजीब लगेगा। उन्होंने कहा था-

'आज होली खेलूंगी, मैं कह बिस्मिल्लाह'

यह बुल्लेशाह ने बोला था। आगे की लाइन में उन्होंने जो कहा, वह अरबी भाषा का एक शब्द है,

"'अलस्तु बी रब्बिकुम' प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले
नाम नबी की रतन चढ़ी, बूंद पड़ी अल्लाह-अल्लाह
आज होली खेलूंगी, मैं कह बिस्मिल्लाह।।"

मगर इसको आपने माना क्या? अब मैं एक और उदाहरण देता हूं। चित्रकूट के घाट की घटना थी, अब्दुल रहीम खानखाना और तुलसीदास जी दोनों अच्छे मित्र थे और दोनों साथ-साथ रहते थे। जब अब्दुल रहीम खानखाना वहां की मिट्टी उठाकर अपने सिर पर लगा रहे थे, तो तुलसी ने उनसे छंद में पूछा कि आप यह मिट्टी सिर पर क्यों लगा रहे हैं? आप गंगा-जमुनी तहज़ीब की बात कहना चाहते हैं, इस प्रसंग को सुनें। तुलसी दास जी ने यह पूछा कि अरे! आप यह धूल सिर पर क्यों लगा रहे हैं?-

"धूर धरत नित सीस पै, कहु रहीम केहि काज"
तो रहीम ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा -
"जेहि रज मुनि-पतनी तरी, सोई ढूंढत महाराज ?"

मैं भगवान राम के चरणों की वह रज ढूंढ़ रहा हूं, जिससे मुनि की पत्नी तर गई थी और मेरा भी उद्धार हो जाए। उस समय कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर आज बुल्लेशाह होते तो फ़तवा जारी हो जाता और बहुत सारे लोग उनके समर्थन में खड़े हो जाते, यह मेरा पक्का मानना है। यह देश की धर्मनिरपेक्षता के ऊपर हमला है। मैं कहना चाहता हूं, यह जो गंगा-जमुनी तहज़ीब थी, इसमें आज़ादी के बाद तक भी कोई समस्या नहीं थी। यह सारी समस्या 1976 के बाद आई है, जबसे सेकुलर शब्द का प्रयोग अपने राजनैतिक हित में करने की शुरुआत हुई है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आप सबने वह सुना होगा - 'मन तड़पत हरि दर्शन को आज, यह गाना किसने गाया था? यह गाना मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया था। लिखा किसने था? श्री शकील बदायूँनी जी ने लिखा था। संगीत किसने दिया था? नौशाद जी ने दिया था। गंगा-जमुनी तहज़ीब ये थी।

डा. के. केशव राव (आंध्र प्रदेश): इनकी स्पीच बहुत इंटरेस्टिंग है।...**(व्यवधान)**..... one minute.

इनकी स्पीच बहुत इंटरेस्टिंग है। An atheist like my is still attending you, लेकिन इसके लिए एक वन फुल डे सेशन हो जाए, जिसमें आप अपनी धर्म की चर्चा करें।

डा. सुधांशु त्रिवेदी: नहीं, मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं कि गंगा-जमुनी तहज़ीब ये थी। संयोग तो यह है कि इनकी नज़र किधर जाती है? मैंने अभी तक जितने भी नाम गिनाए हैं, क्या इन लोगों की जयंती मनाते हुए कभी वे लोग नज़र आए, जो आज प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। आज वे लोग नज़र नहीं आते। आज तो वे कहते हैं कि हमने 800 साल इस देश पर हुकूमत की थी। अभी कुछ ही दिन पहले यह बयान आया था, फिर कहते हैं कि साहब, हम तो मज़लूम हैं, हमें अधिकार मिलना चाहिए। ऐसी विचित्र स्थिति आज देश में खड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है, जो सत्य से बिल्कुल परे है। आपने पूरी दुनिया में कभी यह नहीं सुना होगा कि कोई यह भी कहे कि हमने इस देश पर शताब्दियों तक हुकूमत की है और फिर यह कहे कि हमें special status मिलना चाहिए। मैं पूरी ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं। 1947 में जब यह देश आज़ाद हुआ था, तो 567 रियासतें थीं। आप यह बताइए, जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं, तो आज देश की सबसे अधिक पढ़ी-लिखी कम्युनिटी कौन सी है? पारसी है, जो 0.1% की माइनॉरिटी में है। सबसे prosperous community कौन सी है? जैन है, जिनकी 1.0% की माइनॉरिटी है। सबसे बड़ी entrepreneur community कौन सी है? सिख है, जिनकी 1.8% की माइनॉरिटी है। अगर इन सबको prosperity, education और आगे बढ़ने के सारे अवसर मिल रहे हैं, तो माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी में हैं, उनके साथ समस्या कैसे आई, यह विचार करने का विषय है। जब देश आज़ाद हुआ, तो बताइए कि क्या कोई बौद्ध रियासत थी? नहीं थी। क्या कोई क्रिश्चियन रियासत थी? नहीं थी। क्या कोई पारसी रियासत थी? नहीं थी। एक महाराजा पटियाला को छोड़ दें, तो सिख रियासतें भी नहीं थीं, मगर लाइन लगाकर मुस्लिम रियासतें थीं। नवाब पटौदी, नवाब रामपुर, नवाब भोपाल, नवाब लखनऊ, निज़ाम हैदराबाद, जूनागढ़ के नवाब, ये सब थे, फिर ऐसे हालात क्यों हो गए? जब बाकी सब माइनॉरिटीज़ पढ़ाई-लिखाई में और बाकी सारी चीज़ों में आगे हैं, तो ऐसे में एक ही वर्ग पीछे होता चला गया, ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि इसमें दोष, अदावत की और मोहब्बत की जो सियासत की गई, उसका भी है। किसी ने दिखाने की कोशिश की कि हमें तुमसे बड़ी मोहब्बत है, तो किसी ने यह दिखाने की कोशिश की कि फलां को तुमसे बड़ी अदावत है। उस सियासत ने हमें कहां पहुंचाया?

'किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा,
किसी को किसी की अदावत ने मारा,
पर इस शराफ़त अली को सेकुलर सियासत ने मारा'।।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, आज पूरे देश में जो सामने दिखाई पड़ रहा है, उस यथार्थ को देखिए। जानते हैं ज्यादा खतरनाक बात क्या हो रही है? मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि ज्यादा खतरनाक बात यह हो रही है कि अब यह बहुत उग्र स्वरूप में आगे

बढ़ने का एक प्रयोग किया जा रहा है। उसका उदाहरण मैं यह कहना चाहूँगा कि जब CAA का विरोध हुआ, तो विषय क्या था कि असम की संस्कृति की रक्षा करनी है या असम के लोगों के हितों की रक्षा करनी है, मगर सबसे पहले आन्दोलन कहाँ शुरू हुआ, जामिया में। उसके बाद अलीगढ़ में, उसके बाद नदवां में। उसके बाद हमारे दूसरे सदन के एक सांसद हैं, जो हैदराबाद के सबसे बड़े झंडाबरदार अलम्बरदार बन गये। सबसे पहले रिजॉल्यूशन कहाँ पास हुआ, केरल की असेम्बली में। इसे बहुत ही सहजता से समझा जा सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उपसभापति महोदय, एक बात और सुनिए कि उसके उपरान्त क्या हुआ। ये सारे विषय गौण हो गये। पता नहीं उसके अन्दर कौन-कौन से विषय आने लगे—कश्मीर से लेकर, धारा 370 से लेकर, देश को अलग करने से लेकर असम को परमानेंट अलग करने तक। तो यह देख कर मन में यह संदेह उत्पन्न होता है कि यह सारा का सारा जो घटनाक्रम है, हम सभी लोग बहुत जिम्मेदार लोग हैं, हमें यह समझना चाहिए कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हो रही हैं, क्या हमारी गंगा-जमनी तहजीब के हिसाब से हैं, क्या हमारे संविधान के हिसाब से हैं या जो संविधान में कमेटियों में लिखा, उसके हिसाब से हैं या फिर यह कोई एक खतरनाक प्रयोग है? हम जाने-अनजाने में उसके शिकार होते चले जा रहे हैं और देश तथा समाज को भी उसकी गिरफ्त में लाते चले जा रहे हैं। जब कोई इस प्रकार का कार्य होता है, तो—

मैं सिर्फ एक उदाहरण और fact quote करना चाहूँगा। एक बहुत बड़े पत्रकार Mark Tully हैं, जो 26 वर्ष भारत में रहे। वे BBC के संवाददाता रहे।

उपसभापति महोदय, यह पुरानी बात नहीं है। उन्होंने 22 सितम्बर, 2019 को एक आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल में उन्होंने क्या लिखा है कि "Muslims in India are the luckiest." यानी भारत में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग सर्वाधिक भाग्यशाली हैं। उन्होंने उसका एक उदाहरण दिया कि मैं 26 साल दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में रहा, मेरे यहाँ से थोड़ी दूरी पर हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और थोड़ी दूरी पर तबलीग़ी जमात का ऑफिस था। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई दूसरा देश होता तो 26-27 साल में कोई एक-दूसरे को समाप्त जरूर कर देता, परन्तु भारत के मुस्लिम इसलिए भाग्यशाली हैं क्योंकि वे अपने मजहब के अन्दर भी जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इबादत कर सकते हैं। यह कहने वाला कोई संघी या भाजपाई नहीं है, बल्कि यह कहने वाला एक वह पत्रकार है, जिसने पूरी जिन्दगी भारत में गुजारी है और उसने यह 2019 में कहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है, इस पर किसी भी प्रकार का खतरनाक खेल सभी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यह नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ हमारा हित साधन होगा और दूसरे को क्षति होगी और वह भी विशेषकर जब बगैर किसी आधार के यह बात हो रही हो। मैं फिर एक पंक्ति क्वोट करना चाहूँगा। राहत इंदौरी एक बड़े प्रसिद्ध शायर हैं, मैं उनकी एक पंक्ति क्वोट करना चाहूँगा। वह बड़ी फेमस कविता है। आप लोगों को बहुत ध्यान में होगी कि:

"अगर है खिलाफ, तो खिलाफ होने दो,
यह सब धुआँ है, कोई आसमान थोड़ी है।"

आगे है:

"लगेगी आग तो आयेंगे घर कई ज़द में,
यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है?"

यह विचार, बिल्कुल ध्यान रखिए कि हम सिर्फ अपना हित साधन करते हुए आगे निकल जायेंगे, ऐसा नहीं है।

अन्त में मैं यह कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पहले ...**(व्यवधान)**... यह अगर आपको समझ में आ जाता, तो दुनिया कुछ और होती साहब! ...**(व्यवधान)**... अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य: वह आपके लिए ही कहा था। ...**(व्यवधान)**...

डा. सुधांशु त्रिवेदी: नहीं, नहीं। सुनिए, सुनिए। ...**(व्यवधान)**... वह अगर आप कहना चाहते हैं, तो ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप चेयर को एड्रेस करें।

डा. सुधांशु त्रिवेदी: सर, अन्त में मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के प्रथम बिन्दु पर यदि हम जायें— मैं वहाँ से समाप्त करना चाहूँगा। यदि हम प्रथम बिन्दु पर जायें, तो उन्होंने क्या कहा कि 24वीं सदी के तीसरे दशक की शुरुआत हो रही है। अब मैं कहना चाहूँगा कि जब 24वीं सदी और तीसरा दशक आये, तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें, तो जब 20वीं सदी का पहला सूरज उगा था, सन् 90 में, तो उस समय इस देश में किसकी सरकार थी, अंग्रेजों की, 20वीं सदी के मध्य में यानी 1954 में जब इस देश में पहला सूरज उगा, तो इस देश में किसकी सरकार थी, कॉंग्रेस की और 2001 में जब 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण इस धरती पर पड़ी तो इस देश में किसकी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भाजपा की और दूसरे दशक में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की और तीसरा दशक शुरु हुआ, तो दोबारा और अधिक बहुमत की। इसका मतलब नियति का संकेत है कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, बीसवीं सदी कॉंग्रेस की थी और 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए आप सब लोग इन विचारों को समझिए, साथ में आइए और जो देश में प्रदर्शन चल रहा है, जो विचार चल रहा है, यह पूरे तरीके से तथ्यों पर आधारित नहीं है और जिस प्रकार से आग लगाने का प्रयास हो रहा है, उसे आप रोकने का प्रयास करिए, सत्य को ढंकने का प्रयास मत करिए। जैसे सूरज को परछांई से ढका नहीं जा सकता, उसी ढंग से सत्य को

ढका नहीं जा सकता। आप इस यथार्थ को समझिए, मिलकर साथ चलिए तो देश के लिए भी उत्तम होगा।

मैं यह पंक्ति कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा, अटल जी ने कहा था—

"भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछांई से हारा,
इसलिए अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं,
आओ मिलकर दीया जलाएं।

इसलिए देश की इस दिशा में मिलकर कार्य करें, यही कहकर मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Motion that has been moved and seconded that an Address be presented to the President in the following terms:—

"That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on January 31, 2020." Now, there are 477 Amendments to the Motion which may be moved at this stage. Amendments (Nos. 1 to 108) by Shri Vishambhar Prasad Nishad, Shrimati Chhaya Verma and Ch. Sukhram Singh Yadav. Shri Vishambhar Prasad Nishad, are you moving?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

1. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

   "किन्तु खेद है कि देश में विभिन्न मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे धरना-प्रदर्शनों के समाधान हेतु उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख नहीं है।"

2. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

   "किन्तु खेद है कि धार्मिक आधार पर निर्णयों को बंद कर सभी के साथ समान भाव से निर्णयों का उल्लेख नहीं है।"

3. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

   "किन्तु खेद है कि देश में मानवाधिकार हनन की रोकथाम हेतु उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख नहीं है।"

4. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि एनपीआर में जोड़े गए नये कॉलम्स में मांगी जाने वाली जानकारी को हटाने का उल्लेख नहीं है।"

5. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि सीएए में सभी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने हेतु संशोधन का उल्लेख नहीं है।"

6. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश के बेरोजगारी आंकड़ों को एकत्रित करने हेतु बेरोजगारी रजिस्टर बनाए जाने हेतु उल्लेख नहीं है।"

7. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश में राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) बनाए जाने हेतु उल्लेख नहीं है।"

8. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ोत्तरी को वापस लेने हेतु उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख नहीं है।"

9. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश में आवश्यक खाद्य पदार्थों की महंगाई कम करने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख नहीं है।"

10. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि भारतीय रेल को धीरे-धीरे निजी हाथों में सौंपने से रोकने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख नहीं है।"

11. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद हैं कि भारतीय रेल आईआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस में विभिन्न तबके के लिए रियायती टिकटें न देने की नीति को समाप्त करने का उल्लेख नहीं है।"

12. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि श्रम कानूनों और अधिक प्रभावी बना कर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करवाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख नहीं है।"

13. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश में संचालित किसान जन सेवा केन्द्रों से किसानों हेतु सही समय पर सूचनाओं को मुहैया करवाने हेतु खाली पड़े पदों पर नियुक्ति हेतु उल्लेख नहीं है।"

14. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश के गऊशालाओं में मर रही गायों को बचाने के लिए उनके भोजन सहित समस्त संसाधन उपलब्ध कराने हेतु उल्लेख नहीं है।"

15. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि जीएसटी के तहत राज्यों के हिस्से में प्राप्त कम राशि को पूर्व की भांति अधिक राशि जारी करने का उल्लेख नहीं है।"

16. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश में अलाभकारी होती कृषि के कारण लगातार किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को समाप्त करने हेतु उठाए जाने वाले ठोस कदमों की जानकारी नहीं है।"

17. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश में किसानों के सभी फसलों को लागत मूल्य से अधिक मूल्य दिलाए जाने वाले ठोस कदमों की जानकारी नहीं है।"

18. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अत्यधिक खेती लागत को कम करने हेतु उठाए जाने वाले ठोस कदमों का उल्लेख नहीं है।"

19. कि प्रस्ताव के अंत में निम्मलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि खेती में प्रयोग होने वाले नई प्रौद्योगिकी, कीटनाशकों, बीजों और अन्य संसाधनों को नियंत्रित मूल्य पर किसानों तक मुहैया कराने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

20. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि यूरिया व अन्य उर्वरकों की पहुंच किसानों तक आसानी और समय पर हो सके इसके लिए उठाए जाने वाले ठोस कदमों की जानकारी नहीं है।"

21. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि किसानों के आलू उत्पाद सहित सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था हेतु उल्लेख नहीं है।"

22. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि अलाभकारी होती कृषि के कारण गांवों से पलायन रोकने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

23. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश के गन्ना किसानों का दिनों दिन बढ़ते बकाया राशि के भुगतान और उस पर ब्याज देने की किसी नीति का उल्लेख नहीं है।"

24. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि किसानों को कृषि उपकरणों पर 100 फीसदी के बजाय पूर्व की भांति 50 फीसदी रकम जमा करने पर उपकरण देने की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।"

25. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि खेती योग्य भूमि का लगातार घटते रकबे की स्थिर बनाने या रकबा बढ् ाने का उल्लेख नहीं है।"

26. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि पेट्रोल व डीजल की कीमतों में आए दिन बढ़ोत्तरी से किसानों को सिंचाई हेतु डीजल के दर बढ़ोतरी के प्रभाव से मुक्त कर नियंत्रित दर पर डीजल उपलब्ध कराने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

27. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश में खेती भूमि की सिंचाई प्रणाली को और दुरूस्त हेतु उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख नहीं है।"

28. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थापित टोल प्लाजा की समाप्त करने की जानकारी नहीं है जिससे सड्कों पर जाम में सुधार आ सके।"

29. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को स्वदेश में बनाने की योजना का उल्लेख नहीं है, जिससे राफेल जैसा विवादित सौदा न हो सके।"

30. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि हर वर्ष ठंडी के मौसम में ठंडी लगने के कारण होने वाली गरीबों की मौतों की रोकथाम हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

31. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि कौशल विकास योजना के अंतर्गत देश के शहरों में फर्जी ट्रेनिंग संस्थान चला कर हो रहे घोटाले की सीबीआई जांच कराने का उल्लेख नहीं है।"

32. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश में बढ़ती आर्थिक असमानता दूर करने, जिससे गरीबी दूर हो सके की नीति का उल्लेख नहीं है।"

33. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश में गायों द्वारा किसानों की फसलों को नष्ट करने/बर्बाद करने की रोकथाम हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

34. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि दिल्ली सहित देश के महानगरों में बढ़ते प्रदूषण, वायु एवं जल को मानक के अनुरूप लाने की दिशा में उठाए जाने वाले ठोस कदमों की जानकारी नहीं है।"

35. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट पर पूरी तरह रोकथाम हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

36. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि सड़कों पर घूमने वाले लावारिस जानवरों जिनसे आए दिन अनेक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं की देखभाल हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

37. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि पढ़े-लिखे बेरोजगारों को जीवन-यापन हेतु रोजगार या बेरोजगारी भत्ता देने का उल्लेख नहीं है।"

38. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि कृषि क्षेत्र में घटते रोजगार के अवसरों को बढ़ाए जाने की जानकारी नहीं है।"

39. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश में विभिन्न चयन आयोगों द्वारा भर्तियों में अत्यधिक विलंब को दूर करके भर्तियां समय से संपन्न कराए, इसके लिए उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख नहीं है।"

40. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि यूजीसी के नेट परीक्षार्थियों द्वारा सही उत्तर पर जांचकर्ताओं द्वारा गलत उत्तर बताकर अभ्यार्थियों को कम नंबर देकर फेल करने और अभ्यर्थियों द्वारा उसकी

जानकारी नियमानुसार प्राप्त करने के बाद भी, उसे सही उत्तर पर नंबर में सुधार न करने की पद्धति में सुधार लाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

41. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत समान अधिकार, समान वेतन स्थायी कर्मचारियों के समान संविदा एवं कंट्रैक्ट कर्मचारियों को वेतन देने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

42. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश में सरकारी नौकरी पाने की आयु से ऊपर निकल चुके बेरोजगार पढ़े लिखे शिक्षित नागरिकों को रोजगार के अवसरों के संबंध में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

43. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश में वर्ष 2011 के जनगणना में बेघर लोगों को आधार नंबर उपलब्ध हो सके और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके, के संबंध में उठाए जाने वाले ठोस कदमों की जानकारी नहीं है।"

44. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि जनगणना 20 में जातीय जनसंख्या को सार्वजनिक करने का उल्लेख नहीं है।"

45. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश में अल्पसंख्यक समुदाय को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत और अधिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु उठाए जाने वाले ठोस कदमों की जानकारी नहीं है।"

46. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश में गाय को पालने के लिए खरीद कर ले जाते समय तथाकथित गौ-रक्षकों द्वारा गौ-तस्कर के नाम पर हिंसा की घटनाओं की रोकथाम हेतु उठाए जाने वाले ठोस कदमों की जानकारी नहीं है।"

47. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि पूरे देश खासकर गांवों में चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति हेतु कदमों की जानकारी नहीं है।"

48. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पूरे वर्ष काम मिले, इस दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी नहीं है।"

49. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि मनरेगा 100 दिन के बजाय 365 दिन मजदूरों को कार्य मिले जिससे शहरों की ओर गांवों से पलायन रुक सके का उल्लेख नहीं है।"

50. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि मनरेगा की राशि केन्द्र द्वारा समय से और पर्याप्त निधि जारी करने और तदुपरांत मनरेगा मजदूरों को समय से मजदूरी राशि जारी हो सके, का उल्लेख नहीं है।"

51. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि मनरेगा में निर्धारित दर सीमेंट, ईंट व मजदूरी का बाजार दर से कम होने के कारण मनरेगा के कार्य की प्रगति में आ रही बाधाओं को दूर करने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख नहीं है।"

52. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश के समस्त नागरिकों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की तरह सरकारी दरों के समान आम नागरिकों के इलाज हेतु अस्पतालों एवं जांच केन्द्र को चार्ज लेने की बाध्यता, जिससे आम नागरिक भी कम दर पर अपना इलाज करा सके, के संबंध में जानकारी नहीं है।"

53. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि सरकारी गोदामों में खाद्यान्नों की रखरखाव को और सुदृढ़ करने तथा नये गोदामों के निर्माण हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

54. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बढ़ा कर निजी स्कूलों के समान लाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

55. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि विद्यालयों से बच्चों का बीच में स्कूल छोड़ने की रोकथाम हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

56. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को अभेद बनाने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

57. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि छोटे शहरों, कस्बों तक औद्योगिक प्रगति और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने हेतु उल्लेख नहीं है।"

58. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

59. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि बैंकों में अपनी जमा राशि पर बचत बैंक खातों से विभिन्न मदों में बैंकों द्वारा कमी कम बैलेंस तो कभी अन्य मद में राशि चार्ज करने की नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साफ और बैंकों के लिए बाध्यकारी बनने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

60. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश में चल रहे पोंजी योजनाओं जिनसे नागरिकों को गुमराह कर उनकी मेहनत की धनराशि हड़प करने वाली पोंजी योजनाओं की रोकथाम और कानून के दायरे में लाने हेतु कदमों की जानकारी नहीं है।"

61. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए; अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि अत्यधिक विलंब से संचालित ट्रेनों को समय पर चलाए जाने का उल्लेख नहीं है।"

62. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि ट्रेनों में बढ़ते लूट-पाट एवं अपराधों पर लगाम लगा कर सुरक्षित यात्रियों के यात्रा हेतु उठाए जाने वाले ठोस कदमों का उल्लेख नहीं है।"

63. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि बैंकों के लगातार बढ़ रहे एनपीए को कम करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

64. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि किसानों को कृषि कार्य हेतु बैंकों द्वारा कर्ज को बढ़ावा देने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

65. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश के शिक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रिक्त पड़े विभिन्न शिक्षकों के पदों को स्थायी रूप में भरने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

66. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश में बड़े पैमाने पर रिक्त पदों पर नियुक्तियों को समय पर भरने में विलंब को दूर करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

67. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में प्राप्त लक्ष्यों की जानकारी तथा अगले पंचवर्षीय योजना की घोषणा न करने से विकास हेतु विभिन्न मदों में धनराशि की उपलब्धता और कार्यनीति हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

68. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश में वर्ष 2011 में सम्पन्न हुए जनगणना में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन का मापदण्ड महंगाई दर का समावेश कर पुन: निर्धारित कर योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

69. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश में वर्ष 2011 के जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण नीति जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाए-घटाए जाने का उल्लेख नहीं है।"

70. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश से पूरी तरह नक्सलवाद समाप्त करने की दिशा में उठाए जाने वाले ठोस कदमों की जानकारी नहीं है।"

71. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश की सीमाओं को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों, जिससे लगातार बढ़ रहे घुसपैठ पर पूर्णत: रोक लग सके का उल्लेख नहीं है।"

72. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि भारतीय समुद्र क्षेत्र में मछली पकड़ते या भूलवश जल सीमा के पार गए भारतीय मछुआरों को पड़ौसी देशों श्रीलंका और पाकिस्तान द्वारा पकड़ने की घटनाओं के शीघ्र समाधान हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

73. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश के न्याय व्यवस्था में बड़े पैमाने पर रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है जिससे मुकदमों को शीघ्र निपटाकर समय पर नागरिकों को न्याय मिल सके।"

74. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि नये जाली नोटों की रोकथाम हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

75. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि नोटबंदी से कालेधन की प्राप्ति की संतोषजनक जवाब न देने से उत्पन्न भ्रम की स्थिति को दूर करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

76. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि दिल्ली क्षेत्र में लगातार यमुना नदी के सिकुड़ते आकार और यमुना नदी के पानी में बढ़ते जहरीले तत्व से निपटने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

77. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है चीन द्वारा हड़पी गई भारतीय क्षेत्र को पुन: भारतीय परिधि में लाए जाने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

78. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश के सभी बच्चों को समान शिक्षा मिले, इस दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

79. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि कुशल कामगारों, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के देश से पलायन रोकने हेतु जानकारी नहीं है।"

80. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश में लगातार बढ़ रहे अमीरों एवं गरीबों की खाई कम करने की दिशा में किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है।"

81. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि पूरी तरह मानव तस्करी रोकने की दिशा में किसी कार्य योजना को जानकारी नहीं है।"

82. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि मशीनों का सीमित उपयोग जिससे बेरोजगारी कम हो की दिशा में किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है।"

83. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु उठाए जाने वाले सार्थक कदमों की जानकारी नहीं है।"

84. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि ई-वेस्ट के उचित निपटारे हेतु किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है।"

85. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि विलुप्त हो रहे वन्य संपदा के संरक्षण हेतु किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है।"

86. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि भ्रष्ट अफसरों को दण्डित करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

87. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की धनराशि बढ़ाकर 10 लाख करने जैसे प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।"

88. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि देश के सभी तालाबों, जलाशयों में मौजूद सिल्ट सफाई कराकर इस क्षेत्र में पानी की आवश्यकता को वर्षा जल द्वारा तालाबों एवं जलाशयों में अधिक जल एकत्रित करने की किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है।"

89. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि देश के किसानों के उत्पाद खासकर दुग्ध उत्पादों को जीएसटी से बाहर रखा जाए।"

90. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश के दिल्ली सहित महानगरों एवं राज्यों की राजधानियों में अत्यधिक बढ़ते वाहनों से ट्रैफिक व्यवस्था धराशाही न हो इसके लिए वाहनों के पंजीकरण पर कार्यनीति का उल्लेख नहीं है।"

91. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि माननीय कोर्ट की दखल के बाद 10 एवं 15 वर्ष के पुराने वाहनों जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, के निपटारे हेतु सरकार की योजना का उल्लेख नहीं है।"

92. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि बैंक खाता धारकों के खातों से साइबर अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी के जरिए राशि हड़पने की रोकथाम के लिए कोई उल्लेख नहीं है।"

93. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश में इंटरनेट के माध्यम से अश्लील साइटों की पहुंच पर रोक लगाने की दिशा में कोई उल्लेख नहीं है।"

94. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि आम आदमी को मात्र 12 हजार रुपए शौचालय निर्माण राशि को बढ़ाकर प्रयागराज में बनाए गए अर्धकुंभ की तर्ज पर 35 हजार रुपए प्रति शौचालय जारी करने का उल्लेख नहीं है।"

95. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए की कीमत में लगातार गिरावट को रोकने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।"

96. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश की बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु किसी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।"

97. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि अलाभकारी कृषि को देखते हुए सभी किसानों और वृद्धों को कम से कम 5000 रुपए पेंशन देने का उल्लेख नहीं है।"

98. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि मण्डल आयोग की सिफारिशों के प्रावधानों के अनुरूप हर 10 वर्ष बाद आरक्षण नीति के अध्ययन/मूल्यांकन के बाद उसके अनुरूप आरक्षण नीति में संशोधन कर वंचितों को आरक्षण का लाभ देने हेतु किसी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।"

99. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि चुनावों में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीनों पर उठने वाली आशंकाओं को दूर करने की दिशा में उठाए जाने वाले ठोस कदमों का उल्लेख नहीं है।"

100. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि चुनावों में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीनें, वोटिंग के समय खराब न हो सके ऐसी मशीनों के इस्तेमाल हेतु उठाए जाने वाले ठोस कदमों का उल्लेख नहीं है।"

101. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि भारत संचार निगम लिमिटेड के मोबाइल सिंग्नल कॉल ड्राप पर विराम लगाने का उल्लेख नहीं है।"

102. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश में घोषित नए खोले जाने वाले केन्द्रीय विद्यालयों के विलंब को दूर करने के संबंध में उल्लेख नहीं है।"

103. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि केन्द्र और राज्य सरकारों के सभी विभागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण पूरा करने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।"

104. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि काला धन लाने का किया गया वादा तथा 15 लाख हर हिन्दुस्तानी के खाते में देने का उल्लेख नहीं है।"

105. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश के किसानों को सूखे से बचाने के लिए उचित वर्षा जल प्रबंधन तथा अनुकूल समय की भविष्यवाणी करने के लिए फसल निगरानी की उपयोगी सूचना प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।"

106. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि पुरानी पेंशन योजना को पुन: बहाल करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।"

107. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि चयनित सांसद आदर्श ग्राम योजना हेतु भारत सरकार द्वारा विकास हेतु अलग मद में धन न आवंटित करने का उल्लेख नहीं है।"

108. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश के सभी बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी के बारे में उल्लेख नहीं है।"

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos. 109 to 111) are by Shri Vishambhar Prasad Nishad, Ch. Sukhram Singh Yadav. Shri Vishambhar Prasad Nishad, are you moving?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

109. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना की रूपरेखा का उल्लेख नहीं है।"

110. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि उत्तर प्रदेश की 17 अन्य पिछड़ी जातियों कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजाति, धीवर, बिन्द, धीमर, बाथम, तुरहा, गाड़िया, मांझी, मछुवा, भर और

राजभर को अनुसूचित जाति की सूची में पहले से विद्यमान मझवार, गोंड, बेलदार, तुरैहा, तरमाली, शिल्पकार में परिभाषित करने का उल्लेख नहीं है।"

111. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर मण्डल के टेनरियों से निकलने वाले दूषित पानी को सिंचाई योग्य गुणवत्तायुक्त बनाने वाली संस्थानों पर मानकों के उल्लंघन को रोकने की दिशा में उठाए जाने वाले ठोस कदमों का उल्लेख नहीं है।"

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment (No. 112) by Shrimati Chhaya Verma, Ch. Sukhram Singh Yadav. Shrimati Chhaya Verma- not present. चौधरी सुखराम सिंह यादव, क्या आप मूव कर रहे हैं?

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

112. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि भारत के सभी बच्चों को समान शिक्षा लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।"

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos. 113 to 137) by Shri Vishambhar Prasad Nishad. Are you moving?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

113. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि केन्द्र सरकार द्वारा वाराणसी सहित देश की विभिन्न नदियों में क्रूज चलाए जाने से पारंपरिक नौकावहन करने वाले स्थानीय नाविकों की रोजी रोटी पर आए संकट को दूर करने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख नहीं है।"

114. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश के सभी राज्यों में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा देकर कृषि की भांति लगान निर्धारित कर मत्स्य पालन के लिए अनुदान देने का उल्लेख नहीं है।"

115. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि बुंदेलखण्ड के चित्रकूट, बांदा तथा सतना क्षेत्र में केन्द्रीय पुलिस बल ट्रेनिंग सेंटर खोलने का उल्लेख नहीं है।"

116. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि बुंदेलखण्ड के सभी गरीबों एवं मजदूरों को सर्वे कराकर गरीबी के आधार पर बीपीएल कार्ड एवं निःशुल्क आवास की सुविधा मुहैया कराए जाने का उल्लेख नही है।"

117. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि ट्रेन 18203/18204 बेतवा एक्सप्रेस को कानपुर से दुर्ग के बीच प्रतिदिन चलाए जाने तथा ट्रेन 12535/12536 गरीब रथ को प्रतिदिन चलाए जाने तथा ठहराव रागौल स्टेशन पर कराने का तथा ट्रेन 12427/12428 रीवांचल एक्सप्रेस दिल्ली से कानपुर से बांदा होते हुए रीवा तक चलाए जाने का उल्लेख नहीं है।"

118. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि ट्रेन 11069/11070 तुलसी एक्सप्रेस प्रतिदिन करने तथा ट्रेन 14009/14010 चित्रकूट कानपुर एक्सप्रेस को कानपुर से बढ़ाकर लखनऊ तक चलाए जाने का उल्लेख नहीं है।"

119. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि बुंदेलखण्ड में पलायन को रोकनें हेतु लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना का उल्लेख नहीं है।"

120. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि चित्रकूट धाम व श्रंगवेरपुर धाम इलाहाबाद व महोबा चरखारी, कालींजर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मानचित्र में जोड़ने का कार्य किया जाने का उल्लेख नहीं है।"

121. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि उत्तर प्रदेश के पर्यटक चित्रकूट धाम के हवाई अड्डे से हवाई जहाज चलाए जाने का उल्लेख नहीं है।"

122. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश की नदियों की नीलामी समाप्त कराकर मछुआरे समाज को फ्री फिशिंग की सुविधा देने का उल्लेख नहीं है।"

123. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की तर्ज पर एकलव्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा का उल्लेख नहीं है।"

124. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि सेना के तीनों अंगों में बाढ़ जैसी दैवीय आपदा से निपटने हेतु जन्मजात मछुआ समुदाय के नौजवानों को भर्ती में 50 फीसदी आरक्षण प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।"

125. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि बुंदेलखण्ड में सूखा पीड़ित किसानों से ऋण वसूली समाप्त कर कर्ज माफ करने तथा कृषि, खाद, बीज व बिजली मुफ्त दिए जाने का उल्लेख नहीं है।"

126. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि बुंदेलखण्ड के सर्वांगीण विकास हेतु एक लाख करोड़ की अतिरिक्त सहायता देने का उल्लेख नहीं है।"

127. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायक आंगनवाड़ी कार्यकत्री के मानदेय को बढ़ाकर 10 हजार से अधिक देने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।"

128. कि प्रस्ताद के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मोहल्ला बिसुंदरपुर की जमीन को गंगा नदी की कटान से बचाने के लिए किसी नीति का उल्लेख नहीं है।"

129. कि प्रस्ताव के अंद में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि पूरे देश के मछुआरा समाज में आश्रय विहीन लोगों के लिए दस लाख रुपये देकर मछुआ आवास निर्मित कराने के किसी योजना का उल्लेख नहीं है।"

130. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि बुन्देलखण्ड में कई वर्षों से पड़ रहे सूखे के समाधान हेतु किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है और इस क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर किसानों की आर्थिक मदद का उल्लेख नहीं है।"

131. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास हेतु अतिरिक्त सहायता हेतु किसी कार्य-योजना की जानकारी नहीं है।"

132. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि बुंदेलखंड के नागरिकों को प्रति वर्ष सूखे के कारण आने वाली दिक्कतों के समाधान हेतु अतिरिक्त राशन, आवास, पीने योग्य पानी एवं खेती के लिए किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है।"

133. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि बुंदेलखंड के निवासियों के पलायन को रोकने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों को स्थापना की जानकारी नहीं है।"

134. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि देश में कराई जाने वाली 2021 के जनगणना में जातीय वार जनगणना कराए जाने का उल्लेख नहीं है।"

135. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि एअर इंडिया के घाटे को सरकार द्वारा पूरा करा कर उसे बेचने से बचाने का उल्लेख नहीं है।"

136 कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि निजी क्षेत्रों में ग्रुप सी और डी की नौकरियों में ठेकेदारी की बजाय सरकारी पीएसयू के माध्यम से कर्मियों की तैनाती का उल्लेख नहीं है।"

137. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किंतु खेद है कि ओबीसी से क्रीमीलेयर हटाए जाने का उल्लेख नहीं है।"

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos. 138 to 143) by Shrimati Chhaya Verma—not present.

Amendments (Nos. 144 to 147) by Shri Digvijaya Singh. Mr. Digvijaya Singh, are you moving your Amendments?

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, I move:

144. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention that the Citizenship (Amendment) Act, 2019 has led to wide spread resentment among the People and therefore should be repealed".

145. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention the fact that social tensions and economic policies of the Government have led to lower GDP and loss of employment in the country".

146. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention that because of wide scale resentment in the country against NPR and NCR, they would not be prepared throughout India".

147. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention when the former Chief Ministers of J&K, held in custody, would be released".

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos. 148 to 204) by Shri K.K. Ragesh, Shri T.K. Rangarajan. Shri K.K. Ragesh, are you moving?

SHRI K.K. RAGESH (Kerala): Sir, I move:

148. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that in J&K most of the political leaders including three former Chief Ministers and thousands of others had been detained".

149. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention growing unemployment and the jobless growth phenomenon in the country and also the failure of the Government in providing employment to the unemployed as promised".

150. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the reason for mounting miseries on the people due to economic recession".

151. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the

Government to curb the unprecedented rise in prices of all essential commodities including petrol and diesel".

152. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the lack of transparency in the selection of Judges as well as the accountability of judiciary towards the people".

153. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the failure of the Government to provide adequate compensation to the flood affected States particularly Kerala".

154. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the growing intolerance manifesting the violence and spread of communal polarization in the country".

155. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the overall rape cases in the country".

156. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the serious situation arising in the Central Institutions of Higher education as well as professional colleges".

157. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the attacks against writers and cultural activists".

158. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the failure of the Government to control the ongoing attack on students and journalists by the ultra right forces".

159. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the increasing attack and atrocities on minorities, dalits and tribals in the country".

160. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the guidelines for the Government with regard to liberalizing Foreign Direct Investment (FDI) and portfolio management".

161. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the deprivation of vast majority of poor people to get food under Public Distribution System in the country even after implementation of Food Security Act".

162. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the Government's failure to re-define poverty line thereby depriving a majority section of people from right to subsidised food as well as other basic necessities in the country".

163. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about huge increase of NPA's in PSU Banks affecting their financial health as well as loss of public faith in the financial system".

164. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the wilful corporate defaulters of Public Sector Banks".

165. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the Government's failure to pass Women Reservation Bill".

166. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to continue the independent foreign policy of the country which has withstood the test of time for generations since independence".

167. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about tackling global economic recession affecting Indian industries and loss of jobs of lakhs of workers and employees especially in our traditional and regional industries".

168. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to taken action for release of Indians languishing in jails in various countries".

169. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about lakhs of jobs lost in India during the last three years as a result of privatization of the public sector as well as disinvestment".

170. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the Government's failure to review the Centre-State relations as per the demands of the State Government".

171. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to invest enough money in public sector and social sectors including land reforms to face the ongoing economic meltdown".

172. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the innumerable cases of suicides by the farmers during last few years in various parts of the country".

173. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Central Government agencies to unearth the Chit Fund Scams in West Bengal and various other schemes in States and give relief to the affected people".

174. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to take serious steps on the disastrous impact of global slow down on lakhs of migrant workers who have lost their jobs, livelihood and earnings due to closure, lay off, wage-cuts, retrenchment, etc. across various sectors".

175. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the Government's attempt to redefine India's fundamental principle of 'per capita emissions' norm while negotiating how the burden of reducing green-house gases globally, is shared".

176. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about any special package for the special category States to enable them to narrow down regional disparities".

177. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the agrarian crisis and increasing suicide of farmers in the country due to faulty policy of the Government".

178. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about any scheme for employment for unemployed youth or for unemployment compensation".

179. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about any comprehensive legislation for the welfare of agricultural workers in the country who are becoming unemployed very fast and hence in distress".

180. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about any concrete steps to control unabated suicides being committed by the farmers and their families due to the absence of adequate fair price as well as absence of loan restructuring, insurance etc. in the country".

181. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the need to expedite land reforms in the country so as to provide land to the landless and home to the homeless".

182. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about universalisation of Integrated Child Development Scheme and increasing the wages of Anganwadi workers and helpers as well as Asha workers".

183. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to take steps for the urgent development of various under-developed remote villages".

184. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of Government to bridge the gap of demand and supply of electricity and the under utilisation of the hydro electric power potential of various rivers in Kerala".

185. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of Government to achieve viability of Air India and also the need to reject and type of privatisation of the national carrier".

186. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of Government to take effective steps to provide universal right to at least 35 kg of foodgrains at two rupees a kilo as well as 3 kg Sugar, 5 kg pulses and also 2 litre of cooking oil".

187. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the growing incidence of child abuse and also trafficking of women and children in the country".

188. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to take effective measures to check the malnutrition among the women and children in our country and also to prevent the "stunted growth" as evident in the World Hunger Index".

189. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the demand for universalisation of public distribution system and for a complete ban on speculation and futures trading in the commodity market".

190. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about making conditional the employment protection as well as unemployment insurance".

191. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the strict enforcement of all basic labour laws without any exception or exemption and stringent punishment for violation of labour laws".

192. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the universal social security for the unorganized sector workers and creation of a National Social Security Fund with adequate resources as per the recommendations of the National Social Security Board for Unorganised Workers".

193. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the failure of the Government to take effective measures to eradicate Child Labour from the country".

194. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the failure of the Government to liberalize the educational policy to give access higher education to all irrespective of their paying capacity".

195. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of Government to take effective steps to provide the life saving medicines at subsidized rate and steps taken by the Government to ensure effective Drug Policy to control the abnormal rise in the prices of medicines".

196. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the need to have stringent and better legislation particularly for women and children".

197. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the emergence of 'paid news' that has become a dangerous phenomenon in media world distorting parliamentary democracy".

198. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to develop efficient water transport in the country".

199. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the reason why the Government has raised the price of petrol and diesel even when the prices of crude oil in the international market is declining, which is leading to rise in the prices of all essential commodities".

200. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to fix statutory minimum wage at no less than ₹ 10000".

201. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address failed to assure pension for all".

202. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address that the decision of the Government does not reflect the recommendations of Justice Ranganath Misra

Commission report where it has been recommended to provide 10% reservation for Muslims and 5% for other minorities based on socially and economically backward criteria".

203. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about any policy for the India's 8 million differently abled population whose interest cannot be protected in the absence of institutional mechanism".

204. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention the ever growing Cow related violence and Mob lynching in the country".

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos. 205 to 207) by Shri K.K. Ragesh, Shri T.K. Rangarajan. Shri K.K. Ragesh, are you moving?

SHRI K.K. RAGESH (Kerala): Sir, I move:

205. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the Centre's move to privatise the profit making CPSUs including BPCL".

206. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the failure of the government to take effective measures to address the deterioration of quality of professional education in the country".

207. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the failure of the government to timely provide capital, spectrum and permission to update technologies so as to keep the PSUs such as BSNL and MTNL competitive and profitable".

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos. 208 to 233) are by Shri Madhusudan Mistry. Are you moving?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (Gujarat): Sir, I move:

208. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the Citizenship (Amendment) Act 2019 is discriminatory and it denies the Muslims to seek asylum from 3 neighbouring countries around India".

209. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the plight and socio-economic condition of Muslim communities in India and steps taken by the government to resolve them".

210. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention that many State Governments have relaxed the penalties for violating the Motor Vehicle Act and even made the driving of two wheelers without wearing helmets as a non-punishable offence".

211. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention that present policies and laws passed in last 7 months are turning some section of citizens into second class citizens".

212. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention that in new India the poor, Dalits, lower caste women, youth and minorities have become the victims of discrimination".

213. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention that hilly and desert regions are still lagging behind in development".

214. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention that in new India few industrialists are cornering the government's financial resources and are emerging as a powerful entities".

215. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention that upward ranking of the government in different fields not create the employment opportunities for the masses and unemployment is highest ever in the country".

216. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention that reforms introduced Govt. did not reduce the poverty, did not increase the employment but on the contrary increased the inflation leading to poor becoming more poor lead to India falling 10 places to 68th rank in the Global Competitiveness Index released by WEF wherein the labour rights regime was ranked more poorly at 103rd position".

217. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention that the bifurcation of the State of Jammu and Kashmir to Union Territories has taken in haste and without consulting the elected representatives of Jammu and Kashmir and people at large of the State".

218. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention that political leadership of Jammu and Kashmir detained for months, communication is still barred, the state became police state by abolishing the statehood and turning into UTs".

219. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention as to when the people living in all the cities in India will get the ownership over the land on which they are living for years".

220. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention the names of the states in which the water is depleting rapidly".

221. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that without eradication of corruption".

222. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about MGNREGA at all".

223. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that despite the youthful officers in the Aspirationsal Districts, the children of Dohad district of Gujarat remained severely malnourished and without school education due to heavy migration".

224. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the heavy migration by tribals in search of work from hilly region to urban areas where they are forced to live a life of deprivation on the streets and pavements".

225. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that MSP is given only in minor forest produce and not in major forest produce, which are owned by the state and to depriving tribals from the income from them".

226. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the tardy implementation of Scheduled Tribes and other traditional forest Dwellers Act, popularly known as Forest Rights Act".

227. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the discrimination against minorities in jobs and even in distribution of scholarship to students and grants to their institutions".

228. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the pathetic condition of landless agricultural labourers, the other toiling masses dependent on agriculture, the unemployment in lean season and people living below poverty line".

229. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the abduction and kidnapping of a dalit girl who was gangraped, killed and her body hanged on a tree in Sayra village of Modasa Taluka of Aravalli district of Gujarat.

230. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the GDP rate going down affecting the creation of job opportunities to the millions of youth in the country".

231. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the dropout rate of girl students before they complete standard 8, 12 and in other professional degree courses and colleges".

232. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the metro project in Ahmedabad, Gujarat taking years for completion".

233. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention that our relationship with the neighbourhood has become hostile and some neighbouring Governments are slipping into China's fold and our borders being encroached in North and North East India".

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment (Nos. 234 to 247) are by Shri Vaiko. Are you moving?

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): Sir, I move:

234. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to implement fully the recommendations of the Swaminathan Committee for the welfare of farming community."

235. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to provide

remunerative prices to farmers for their agriculture produce in order to save them from abject poverty and miserable conditions, leading to suicides."

236. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to abandon the Neutrino Observatory proposed to be installed at Theni District, Western Ghats, in view of adverse impact on the environment."

237. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to review and drop hydro carbon projects in the Delta region of Tamil Nadu, in order to save the fertille land from becoming barren land."

238. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to broadbase the Citizenship Amendment Act 2019 to confer citizenship to Shri Lankan Tamils who are staying in refugee and rehabilitation camps in Tamil Nadu as refugees for more than 5 years."

239. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to include all the languages listed in the Eighth Schedule of the Constitution as official languages of the Union."

240. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to amend the Constitution of India (Entry No. 97 in the Union List, Seventh Schedule) in order to transfer the residuary powers, from the Central sphere to the State sphere."

241. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to review and withdraw Citizenship (Amendment) Act, 2019 being discriminatory, communal and to stop large scale protests all over the country."

242. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to discontinue NEET in the State of Tamil Nadu in view of large scale opposition to it."

243. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to pass a resolution for constituting an international court of inquiry into the missing of thousands of Tamil persons during the ethnic war in Sri Lanka."

244. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to provide dual citizenship to Sri Lankan Tamil refugees."

245. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to give protection to the fishermen who go for fishing in Bay of Bengal and to save them from the harassment of Sri Lankan Navy."

246. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to find a solution to the Indian fishermen row on the fishing rights in the Palk Bay Strait and Gulf of Manner."

247. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to release immediately all the political leaders in Kashmir who have been taken on preventive detention."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos. 248 to 273) are by Shri Motilal Vora. Are you moving?

SHRI MOTILAL VORA (Chhattisgarh): Sir, I am not moving.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos. 274 to 279) are by Shri Binoy Viswam. Are you moving?

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I move:

274. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention that while progress has been made on few global rankings, in other key ranking scales, India legs behind, viz. in the United Nations Human Development Index, the World Happiness Report 2019, in the World Economic Forum's Global Gender Gap Index 2020 and the Press Freedom Index."

275. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention about suspension of communication facilities in Jammu & Kashmir and Ladakh which has caused irreversible damage to the economy and lives of the people of Jammu & Kashmir and Ladakh."

276. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address fails to mention that the policies of the government have had a severe impact on the livelihood of farmers and agricultural labourers across the country that has resulted in over 31 farmer suicides every day, according to the latest NCRB data."

277. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address fails to mention that the Government's financial policies and interventions have caused a disastrous effect on the Indian economy with a marginal GDP growth rate of 5% this year accompanied with one of the highest unemployment rates in decades and that Government's decision of demonetization and GST have disastrously affected the lives of each citizen and caused irreparable damage to farmers, traders, unorganized workers, businesses, etc."

278. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention about the rights of workers, especially those belonging to the unorganized sector have been jeopardized for the interest of large companies and big businesses."

279. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention about the passing of law such as the Transgender Rights Bill, 2019, while being extremely important, are against the realities of the community and contains provisions that directly affect the autonomy and rights of Transgender Persons under rather than providing them welfare."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos. 280 to 286) are by Shri Husain Dalwai. He is not present.

Amendment (Nos. 287 to 302) by Shri Tiruchi Siva. He is not present.

Amendments (Nos. 303 to 308) by Shri Narain Dass Gupta. He is not present. Amendments (Nos. 309 to 380) by Dr. T. Subbarami Reddy. Are you moving?

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I move:

309. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing Special Development Package for the State of Andhra Pradesh for the backward districts of Rayalaseema and north Coastal Andhra Pradesh."

310. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to expedite construction of national Polavaram multi-purpose project for providing water and electricity to the State of Andhra Pradesh."

311. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to take all necessary measures as enumerated in the 13th Schedule of AP Reorganisation Act for the progress and sustainable development of the successor States."

312. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any steps for expanding existing Visakhapatnam, Vijayawada and Tirupati airports to international standards."

313. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about measures to be taken to deal with waste, polluted water from drains discharged into the major rivers of the country, particularly, the Yamuna, the Ganga, the Godavari and the Krishna."

314. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any steps for eradicating poverty and unemployment and generating more job opportunities."

315. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need of balanced growth in the country."

316. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about formulating appropriate policy to reduce the increasing tension among various religious and social groups in the country."

317. That at the *end* of the Motion, following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about bringing appropriate reforms in the present education system and making it employment-oriented."

318. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing loans at cheap rate of interest to poor, deprived people, unemployed youth, labourers and marginal farmers by banks and financial institutions."

319. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about formulation of a comprehensive scheme for tackling growing unemployment and to create more employment opportunities in the rural areas."

320. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about formulation of a national level action plan for land conservation in the country."

321. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steep rise in the incidents of murder of old people, women and children and incidents of rapes and providing proper security in the metropolitan cities."

322. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about formulation of effective scheme for the welfare of landless labourers."

323. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about setting up of tribunals for preventing delay in the delivery of justice and for providing speedy justice to the common people."

324. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing telecom services on priority basis in the backward and rural areas of the country."

325. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about measures needed to arrest the steep fall in the ground water level and to encourage rain water harvesting in the country."

326. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about linking rivers, especially Godavari and Cauvery, Krishna to Pennar and Pennar to Cauvery."

327. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing necessary basic facilities to the citizens living in the slum clusters of the metropolitan cities and towns."

328. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the formulation of National Livestock policy."

329. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the development of the tourist spots of the country particular in Andhra Pradesh and Telangana in order to attract domestic and foreign tourists all the year round."

330. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the break out of the diseases like Swine flu, Hepatitis B, Encephalities, T.B., HIV and kidney and cardiac diseases and poverty related diseases and also for providing medical facilities in time to the patients."

331. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about taking measures for increasing the production of foodgrains, pulses and edible oils in proportion to the increasing population in the country."

332. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the necessity to prepare blue print for development schemes for the farmers, labourers, youths and women."

333. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be taken to upgrade the standard of the sports in the country and to provide basic training to rural youths towards excellence in sports."

334. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the increasing pendency of the cases in various courts including High Courts and Supreme Court, and to suggest measures to dispose of the cases expeditiously."

335. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about adopting modern technology for agricultural development in the country."

336. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about bringing out schemes to provide jobs to all the educated unemployed youth in the country."

337. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about adopting new technology in the sugar industry of the country for increasing the production."

338. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about putting a check on the tendency of dropping-out from the schools by a large number of students of primary and middle classes of the schools in the country."

339. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about establishment of agriculture science centers in all the districts of the country."

340. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing loan assistance by re-structuring the loans to be given to the farmers by Nationalised Banks and Cooperative Banks in view of adverse weather conditions and natural calamities."

341. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about addressing the problems being faced by the domestic industry and improving industrial production in the country."

342. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to achieve annual export targets."

343. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about resolving the border disputes among different states in the country."

344. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about resolving the water disputes among different states in the country."

345. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need for providing proper medical facilities for fishermen and their families."

346. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to formulate a national pension and welfare policy for, differently abled persons and senior citizens."

347. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about statutory plans for compensation to the victims of violence especially the victims of communal riots and rehabilitation to such victims."

348. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about an effective industrial policy to check migration from rural areas to cities."

349. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need for immediate reforms in judicial process to deliver expeditious justice."

350. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the facilities to be provided for the upliftment and empowerment of women belonging to the backward and rural areas of the country."

351. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about need to take steps to provide financial and marketing assistance to protect small and traditional

industries and persons in retail trade in the wake of entry of big multinational companies and big industrial houses."

352. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about launching a system based on computer education in the rural areas.

353. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about bringing about necessary reforms for ensuring efficiency, efficacy and accountability in administration."

354. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing sufficient funds for specific programmes to encourage women in the field of sports."

355. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about popularizing sports like Judo and Karate among women for self-defence."

356. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing easy access to the farmers in scientific research particularly in the area of bio-diversity."

357. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about financial assistance to voluntary sports clubs in cities and villages."

358. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing sports facilities to youth through Residents' Welfare Associations."

359. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about preparing a comprehensive policy and action plan to address the matters relating to youth."

360. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about improving the facilities provided to Central Reserve Police Force and other central security forces."

361. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about streamlining the public administration system across the country."

362. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about filling up the posts of thousands of officers and defence personnel lying vacant in Indian Army, Air Force and Navy."

363. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing good quality mid day meal to the children during recess in the school."

364. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about opening of various monuments and heritage sites for viewing by common public on the lines of Taj Mahal, to promote tourism."

365. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing more funds for Scientific and Industrial Research."

366. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about supplying coal according the demand to the Thermal Power Stations, steel and cement plants throughout the country."

367. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to ban the spurious medicines in the country."

368. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about making Khadi Village Industries Commission more result oriented and productive."

369. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about augmenting domestic production of crude oil to become self-reliant in the field of crude oil and to decrease the continuous import of crude oil."

370. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing adequate storage capacity in public sector of agricultural produce and about promoting creation of storage facilities in private sector.

371. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about liberalizing and effectively implementing comprehensive Crop Insurance Scheme."

372. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about setting up an animal husbandry and dairy work research centre in Andhra Pradesh for helping the farmers."

373. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about effectively implementing the technology mission in the field of horticulture."

374. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing loan facility to farmers through cooperative primary banks, rural banks and commercial banks."

375. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing housing facility to mining workers."

376. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing sufficient number of doctors, medical equipments, medicines in ESI hospitals."

377. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about introducing environment and climate change as a compulsory subject at the primary level schooling."

378. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about opening residential schools in each development block to promote girl-education at primary school level."

379. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing special assistance to para-military forces like ITBP, CRPF, BSF for purchasing vehicles, modern communication technology and weapons to keep vigil on borders and stop infiltration."

380. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing grants and technical facilities for the articles made by the Indian craftsmen and artisans through the cottage and small-scale industries of the country and encouraging the export of their goods and artifacts."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos. 381 to 426) are by Shri Elamaram Kareem. Are you moving?

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, I move:

381. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the recent amendment to the Citizenship Act undermines the secular concept of citizenship enshrined in our constitution as it discriminates between Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians who have come from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan and the Muslims."

382. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that in Assam, 19 lakh people were excluded from the NRC creating huge unrest among the people."

383. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that jobs, livelihood and working conditions of workers are under attack, peasants' suicides continue, basic democratic and human rights of common people are being attacked, right to dissent is being curtailed and a sense of terror and Insecurity is being created, particularly among dalits, minorities, adivasis, women and other oppressed sections of society."

384. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that violence against women and children has highly escalated and incidents like gang rape and killings are now happening with increasing frequency."

385. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that as per the national Crimes Research Bureau report 2017, 1.17 lakh cases related to rape including child rape were pending trial and Conviction rate, in the registered cases, was less than 5%."

386. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that India has slipped to 112th position out of the 153 in the Word Economic Forum's Global Gender Gap index in 2019 from 108th position in 2017 and 2018."

387. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that discrimination and oppression against dalits and adivasis continue in an increasing rate and large numbers of workers are also victims of feudal, patriarchal, retrograde values and unscientific practices."

388. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that automomy of all democratic institutions and institutions of higher education, of science, history, culture, of universities including prestigious universities is under severe attack."

389. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that lynching, killing, physical attacks on dalits and Muslims have increased in almost all parts of the country, as a demonstration of the arrogance and might of the 'Hindutva' groups which have become more or less a routine during almost all religious occasions to instill fear and force the minorities, particularly the poor into submission."

390. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the country is facing worst ever econmic slowdown."

391. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that there is consistent stagnation or decline in national savings rates, domestic capital formation, decline in growth of private investment, sluggish growth and in many cases decline in growth in various industrial sectors."

392. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that widespread underemployment and worsening situation of poverty led to sharp decline in effective demand and contraction of commodity market which in turn resulted in drastic cut in capacity utilisation in industries, closure and shutdown of production leading to retrenchment, lay-off and wage cut etc. aggravating impoverishment further."

393. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that as a culmination of continuing economic slowdown, industrial growth has turned negative for three consecutive months ending in Novembers 2019 and out of 23 categories of manufacturing sector, 18 faced a drastic decline and 10 units recorded a double digit decline."

394. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the growth of consumption expenditure droped to just 3.1% compared to last year and the growth of gross fixed capital formation, as percentage of GDP, dipped to mere 4% during last one year period."

395. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that at the *end* of November 2019, retail inflation rate has reached 10% in food items, of which vegetables reached as high as 36% and pulses 14% and the Government has increased the price of certain essential life saving medicines under price-regulation by 50%, increased the price of cooking gas and also railway fare, making the inflationary situation worse for the common people."

396. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the slowdown of the economy has affected the prospects of profit in normal production and business activities."

397. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that with the deepening of the economic crisis, the small and medium industrial sector and service sector, which generate large scale employment, second only to agriculture, are being destroyed."

398. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the various measures of the government like deomonetisation, GST, monopoly lending and massive foreignisation and corporatisation of small and medium trading systems which were meant to support large capital, domestic and foreign, in the background of the economic crisis is adding to deepening and intensifying of mass poverty among the workers."

399. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that demonetisation and GST have been proved to be destructive and disastrous to the small and medium industries and the lakhs of workers employed in them."

400. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the government, through their drive for privatisation, is proposing to forego regular and recurring earning to national exchequer in lieu of one time payment of sale proceeds."

401. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that by converting 44 labour laws into four codes, most of the substantive rights and benefit related provisions for the workers which were in these original 44 laws are being curtailed and through this exercise the lawful rights of the workers are being put at the mercy of the appropriate governments or on the dictates of their masters in the corporate lobby."

402. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the guidelines for the Government in regard to liberalizing Foreign Direct Investment (FDI) and in the portfolio management."

403. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the deprivation of vast majority of poor people to get food under Public Distribution System in the country even after implementation of Food Security Act."

404. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the Government's failure to re-define poverty line thus depriving a majority section of people from right to subsidised food as well as other basic necessities in the country."

405. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the willful corporate defaulters of Public Sector Banks."

406. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to continue the independent foreign policy of the country which has withstood the test of time for generation since independence."

407. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to protect Indian citizens from racial attacks in various countries."

408. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to release Indians languishing in jails in various countries."

409. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the Government's failure to review the Centre-State relations as per the demands of the State Governments."

410. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the urgent need for drastically revising or correcting the official definition of 'poverty line' which has turned totally obsolete."

411. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the need to have a policy for the India's 8 million differently abled population whose interest cannot be protected in the absence of institutional mechanism."

412. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address that the decision of the Government does not reflect the recommendations of Justice Ranganath Misra Commission report to provide 10% reservation for Muslims and 5% for other minorities based on socially and economically backward criteria."

413. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the emergence of 'paid news' that has become a dangerous phenomenon in media world distorting parliamentary democracy."

414. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address to have a stringent and better about the Need legislation particularly Safety and Security for women and children."

415. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the steps taken by the Government to ensure effective Drug Policy which will control the abnormal rise in the prices of medicines."

416. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the failure of the Government to liberalize the education policy to give access of higher education to all irrespective of their paying capacity."

417. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the failure of the Government to take effective measures to eradicate Child Labour from the country."

418. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the universal social security for the unorganized sector workers and creation of a National Social Security Fund with adequate resources as per the recommendations of the National Social Security Board for Unorganised Workers."

419. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to take effective measures to check the malnutrition among the women and children in our country and also to prevent the stunted growth as evident in the World Hunger Index."

420. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to take steps for the urgent development of various under-developed remote villages."

421. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about universalisation of Integrated Child Development Scheme and increasing the wages of Anganwadi workers and helpers as well as Asha workers."

422. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about any comprehensive legislation for the welfare of agricultural workers in the country who are becoming unemployed very fast and hence in distress.

423. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the growing Intolerance manifesting the violence and also attacks against writers and cultural activists."

424. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the Government's failure to pass Women Reservation Bill."

425. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to curb the unprecedented rise in prices of all essential commodities including petrol and diesel."

426. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about any special package for two time flood affected State of Kerala."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos. 427 to 429) are by Shri Derek O'Brien and Shri Sukhendu Sekhar Ray. Shri Sukhendu Sekhar Ray, are you moving?

SHRI SUKHENDU SHEKAR RAY (West Bengal): Sir, I move:

427. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to acknowledge the hardships of peaceful protesters including students."

428. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the drop in India's rank on the Global Press Freedom Index and the EIU's Global Democracy Index and a low rank on the Global Hunger Index."

429. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the six-month long detention of political leaders including sitting Member of Parliament from Jammu and Kashmir and former Chief Ministers of the State."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (No. 430) by Shri Derek O'Brien. He is not present. Amendment (No. 431) by Shri Sukhendu Sekhar Ray. Are you moving?

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, I move:

431. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to acknowledge the economic slowdown, the falling GDP growth rate, rising inflation and the forty-five-year high unemployment rate and skyrocketing prices of essential commodities."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments (Nos. 432 to 477) are by Shri M. Shanmugam. Are you moving?

SHRI M. SHANMUGAM (Kerala): Sir, I move:

432. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about measures to be taken to deal with waste, polluted water from drains discharged into the major rivers of the country, particularly, the Yamuna, the Ganga, the Godavari, and the Krishna."

433. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about eradicating poverty and unemployment and generating more job opportunities."

434. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about formulating appropriate policy to reduce the increasing tension among various religious and social groups in the country."

435. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about bringing appropriate reforms in the present education system and making it employment-oriented."

436. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing loans at cheap rate of interest to poor, deprived people, unemployed youth, labourers and marginal farmers by banks and financial institutions."

437. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about formulation of a comprehensive scheme for tackling growing unemployment and to create more employment opportunities in the rural areas."

438. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steep rise in the incidents of murder of old people, women and children and incidents of rapes and providing proper security in the metropolitan cities."

439. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about formulation of effective scheme for the welfare of landless labourers."

440. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about setting up of tribunals for preventing delay in the delivery of justice and for providing speedy justice to the common people."

441. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about measures needed to arrest the steep fall in the ground water level and to encourage rain water harvesting in the country."

442. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about linking rivers, especially Godavari and Cauvery, Krishna to Pennar and Pennar to Cauvery."

443. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing necessary basic facilities to the citizens living in the slum clusters of the metropolitan cities and towns."

444. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the out break of the diseases like Swine flu, Hepatitis B, Encephalities, T.B., HIV and kidney and cardiac diseases and poverty related diseases and also the steps for providing medical facilities in time to the patients."

445. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about taking measures for increasing the production of foodgrains, pulses and edible oils in proportion to the increasing population in the country."

446. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the necessity to prepare blue print for development schemes for the farmers, labourers, youths and women."

447. That at the *end* of the Motion, the following be *added*; namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be taken to upgrade the standard of the sports in the country and to provide basic training to rural youths towards excellence in sports."

448. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the increasing pendency of the cases in various courts including High Courts and Supreme Court, and to suggest measures to 'dispose of the cases expeditiously."

449. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about adopting modern technology for agricultural development in the country."

450. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about bringing out schemes to provide jobs to all the educated unemployed youths in the country."

451. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about giving relief to workers who were thrown out of employment in the automobile industry recently, though the Government has provided relief to the auto industry by way of tax concessions."

452. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about putting a check on the tendency of dropping-out from the schools by a large number of students of primary and middle classes of the schools in the country."

453. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about establishment of agriculture science centres in all the districts of the country."

454. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing loan assistance by re-structuring the loans to be given to the farmers by Nationalised Banks and Cooperative Banks in view of adverse weather conditions and natural calamities."

455. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about resolving the water disputes among different states in the country."

456. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to provide proper medical facilities for fishermen and their families."

457. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to formulate a national pension and welfare policy for differently abled persons and senior citizens."

458. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about statutory plans for compensation to the victims of violence especially the victims of communal riots and rehabilitation to such victims."

459. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need for immediate reforms in judicial process to deliver expeditious justice."

460. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not Mention about the facilities to be provided for the upliftment and empowerment of women belonging to the backward and rural areas of the country."

461. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about need to take steps to provide financial and marketing assistance to protect small and traditional industries and persons in retail trade in the wake of entry of big multinational companies and big industrial houses.".

462. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing sufficient funds for specific programme to encourage women in the field of sports."

463. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about popularizing sports like Judo and Karate among women for self-defence."

464. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about financial assistance to voluntary sports clubs in cities and villages."

465. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about preparing a comprehensive policy and action plan to address the matters relating to youths."

466. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about streamlining the public administration system across the country."

467. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing good quality mid day meal to the children during recess in the school."

468. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about treating the workers working in the mid-day meal scheme as full-time workers and providing social security scheme for them."

469. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to ban the spurious medicines in the country."

470. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing adequate storage capacity in public sector of agricultural produce and about promoting creation of storage facilities in private sector."

471. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about liberalizing and effectively implementing comprehensive Crop Insurance Scheme."

472. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about effectively implementing the technology mission in the field of horticulture."

473. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing loan facility to farmers through cooperative primary banks, rural banks and commercial banks."

474. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing housing facility to workers in all the sectors."

475. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing sufficient number of doctors, medical equipments, medicines in ESI hospitals."

476. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about extending ESI benefits to workers in the unorganized sector and to extend EPF scheme to them."

477. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about introducing environment and climate change as a compulsory subject at the primary level schooling."

SHRI KAPIL SIBAL (Uttar Pradesh): Sir, I am on a point of order under Rule 238. My learned friend, Bhupender Yadavji, apparently made a reference to me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think, उस डिस्कशन के वक्त तो आप नहीं थे। I think, it is over now. ...*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I have a right to reply. He has attributed a statement to me, allegedly made by me, and quote, which I never made. If he will verify and place before the House that in fact I made that statement; then I can move the Ethics Committee, because I have never made any such statement. I am surprised that the learned friend has attributed a motive to me. Let him place it in the House on oath saying that he verifies this and tell the source of his verification so that I move the Ethics Committee. Will my learned friend inform the House that I made that statement?

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान): सर, मैंने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं उसको confirm करता हूँ और मैं न्यूज़पेपर की रिपोर्ट यहाँ पर रखूँगा।

SHRI KAPIL SIBAL: Were you in court?

श्री भूपेन्द्र यादव: मैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट रखूँगा।

श्री कपिल सिब्बल: जब आप कोर्ट में नहीं थे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने यह स्टेटमेंट दिया है? ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, उसको मैं रखूँगा। आप deny कर दीजिएगा कि न्यूज़पेपर की रिपोर्ट गलत है। ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल: मैं अभी deny कर रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि आपने गलत बोला, आपके बयान गलत थे, motivated थे और आप जान कर ऐसी बात कर रहे हैं ताकि काँग्रेस पार्टी की छवि खराब हो, मेरी छवि खराब हो। You should apologise to the House.

श्री भूपेन्द्र यादव: कपिल सिब्बल जी, मैं आपका सम्मान करते हुए तथ्यों को स्वीकार करता हूँ और मैं सदन के सामने कहता हूँ कि मैं न्यूज़पेपर की प्रतियाँ सदन के पटल पर रख दूँगा। ...**(व्यवधान)**... दूसरा एक और विषय है, अभी पि. भट्टाचार्य जी ने ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल: यही आपके प्रधान मंत्री बोलते हैं और गलत बोलते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, यही विषय एक बार रवि शंकर जी ने उठाया था, तब भी आपने उठाया था और तब भी हमने सेम समाचार पत्र की प्रति पटल पर रखी थी, अब उसको हम दोबारा रखेंगे। ...**(व्यवधान)**... आप उस समाचार पत्र को कहिए कि उसने आपके बारे में गलत छापा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल: चेयरमैन साहब ने ऐसा रूल बना रखा है कि समाचार पत्र के आधार पर आप कुछ नहीं कह सकते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: ऐसा नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है। ...**(व्यवधान)**... यहाँ पर रवि शंकर जी ने रखा है। ...**(व्यवधान)**... मैं उनका पेपर रख दूँगा। ...**(व्यवधान)**... दूसरा विषय यह है कि मेरे पास Citizenship Amendment Act, 2003 की रिपोर्ट है, जिसका मैंने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया था। हमारे माननीय पि. भट्टाचार्य जी ने कहा कि उन्होंने उसमें dissent note दिया है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि इसमें 40 सदस्यों के नाम हैं, लेकिन इनमें कहीं पर भी पि. भट्टाचार्य जी का नाम ही नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI ANAND SHARMA: There is misunderstanding. ...*(Interruptions)*... सर, इसमें गलतफहमी हो रही है। ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, मैं इन 40 नामों को पढ़ देता हूँ, अगर इनमें पि. भट्टाचार्य जी का नाम हो, तो मैं गलत हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: दोनों दो कमेटियाँ थीं। माननीय भूपेन्द्र जी, 2003 की कमेटी अलग थी और आपने जो कहा, वह कमेटी अलग थी। दो अलग-अलग कमेटियाँ थीं, दोनों में confusion है।

...**(व्यवधान)**... आप जो कह रहे हैं, वह कमेटी हाल की थी और आपने जो रेफर किया, वह 2003 की कमेटी थी, जिसमें आप सदस्य नहीं थे। ...**(व्यवधान)**... Let us move on now.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, let me move my Amendments. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you moving Amendments (Nos. 287 to 302)?

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Yes, Sir.

Sir, I move:

287. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about including the Muslim communities in the list of religions and including Sri Lanka in the list of countries in the citizenship (Amendment) Act, 2019.

288. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the violence against peaceful protesters in various parts of the country who exercise their fundamental right to dissent against the policies of the government."

289. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps taken to address the unrest prevailing in the North Eastern region owing to the discontent with the Citizenship (Amendment) Act, 2019.

290. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the anguish of the farmers in the state of Tamil Nadu, against the removal of Environmental Impact Assessment for Hydrocarbon exploration and Petroleum production projects".

291. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the unrest prevailing in the valley of Kashmir and prolonged detention of political leaders under the Public Safety Act."

292. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the crumbling federal structure with the establishment of the National Medical Commission, and the

centralisation of education by making NEET and NEXT compulsory thereby depriving the rural and the poor students' access to medical education."

293. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the consequences arising out of the disinvestment of PSUs including profit making PSUs."

294. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the depletion of the manufacturing sector and the steps taken to address the prevailing sickness in the MSME sector."

295. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps taken for the skill development of the disabled sections of the society."

296. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about establishing an effective mechanism to settle inter-state river water disputes, as well as the issue of interlinking of rivers for the equitable sharing of river water between states."

297. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the waiving of agricultural loans of the aggrieved farmers to resolve the crisis related to farmer loans."

298. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps taken by the Government to provide relief and rehabilitation to victims of Cyclone Gaja in the State of Tamil Nadu."

299. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the concrete measures taken by the Government to create adequate employment opportunities in the country."

300. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the woes of the students, who have secured educational loans, being harassed by the lending sector.

301. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the dilution of the Transgender Persons Bill, 2014 which sought to guarantee basic rights for the transgender community."

302. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the pathetic condition, the BSNL employees are in, owing to non-payment of salaries."

The questions were proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Motion and the Amendments moved are open for discussion. ...*(Interruptions)*...

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): सर, अभी यहाँ जो बात चली, मैं उसी के संदर्भ में रूल 235 पढ़ते हुए आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

جناب جاوید علی خان : سر، ابھی یہاں جو بات چلی، میں اسی کے سندربھ میں رول 235 پڑھتے ہوئے آپ کا تھوڑا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Javedji, it is over, now.

श्री जावेद अली खान: सर, यहाँ पर अभी कहा गया कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि न्यूजपेपर नहीं पढ़ सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं, जब कि इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है,

† سر، یہاں پر ابھی کہا گیا کہ ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ نیوزپیپر نہیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں دکھا سکتے ہیں، جب کہ اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے،

"Whilst the Council is sitting, a Member shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the Council."

जब उसे पढ़ना तक यहाँ allow नहीं है, तो उसका संदर्भ लेकर कोई भी वक्तव्य देना भी ठीक नहीं है। मैं यह सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ।

† جب اسے پڑھنا تک یہاں الاؤ نہیں ہے، تو اس کا سندربھ لے کر کوئی بھی وکتوے دینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ صرف جانکاری کے لئے بتا رہا ہوں۔

†Transliteration in Urdu script.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Leader of the Opposition, Shri Ghulam Nabi Azad.

नेता विपक्ष के (श्री गुलाम नबी आज़ाद): माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, मैं अपनी तरफ से माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यहाँ अभी सत्ताधारी पार्टी की तरफ से यादव जी और त्रिवेदी जी ने बोला। मैं यादव जी को बहुत अच्छी तरह से, बड़े अर्स से जानता हूँ, लेकिन त्रिवेदी जी का ज्ञान सुनने का पहली दफा सदन में मौका मिला। कथाएं भी, poetry भी, हिस्ट्री भी, Geography भी, फिल्म भी, अरबी भी, पर्शियन भी, तो इससे तो बड़े भले आदमी लगते हैं, लेकिन पता नहीं टेलीविजन के सामने इन तमाम चीज़ों का ज्ञान नहीं देते हैं। वहाँ उलटा ज्ञान देते हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि अगर वहाँ भी अच्छा, सद्भावना का ज्ञान पूरे देश को देंगे, तो बहुत अच्छा होगा।

बहरहाल, मैं त्रिवेदी जी की ही बात पकड़ता हूँ। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार की सबसे बड़ी बात है कि जो कहते हैं, वह करते हैं, जो कहते हैं, वह करके दिखाते हैं, तो इस पर मेरा एक शेर है। उन करोड़ों लोगों से छ: साल पहले जो वादे किए गए थे, उन करोड़ों लोगों को, जिनको 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, वे करोड़ों लड़के - लड़कियाँ, जिनको नौकरी देने का वादा किया था, जिन मजदूरों के साथ वादा किया गया था, जिन किसानों के साथ दुगुनी आमदनी का वादा किया था, जिन करोड़ों लोगों के साथ यह वादा किया गया था कि महंगाई खत्म की जाएगी, बेकारी खत्म की जाएगी, बेरोजगारी खत्म की जाएगी, अमन और शांति होगी और सबका साथ, सबका विकास होगा, उन करोड़ों लोगों की तरफ से मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप सब कुछ जो कहते हैं, वह करते हैं, तो क्यों नहीं किया। मैं उनकी तरफ से कहता हूँ,

"तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना,

कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता"

इसका यह कहना है कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि अगर मैं तेरे वादे पर जिऊँगा और मैं कहूँगा कि मैं मान गया, तो यह समझ लेना कि मैं बिल्कुल झूठ कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे एतबार ही नहीं है, आप कभी सच बोल ही नहीं सकते और अगर आप सच बोलते, तो मैं खुशी से मर जाता, तो इसलिए आप selective ठीक करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप जो कहते हैं, नहीं करते हैं। जो आप करते हैं, जिनका आपने उल्लेख किया। आपने ट्रिपल तलाक की चर्चा की, आपने 370 की बात की, आपने सिटिजनशिप एक्ट की बात की, ये तमाम चीज़ें आप उन चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए कर रहे हैं, ताकि आपने छ: साल से जो वादे किए हैं, उन्हें आपको कोई याद न दिलाए। आपको कोई 15 लाख याद न दिलाए, आपको कोई दस करोड़ नौकरी का वादा याद न दिलाए, आपने किसानों के साथ जो वादे किए थे, वे याद न दिलाए, गहंगाई खत्म करने के लिए जो वादे किए थे, वे याद न दिलाए, काला

धन लाने के लिए जो वादे किए थे, वे याद न दिलाए, कोई रुपए की गिरती हुई कीमत याद न दिलाए। मनमोहन सिंह जी को माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि रुपए की कीमत का विकार पहले खत्म होगा या सरकार का, इसके बीच में होड़ लगी है, आज किसके बीच में होड़ लगी है? यह कोई याद न दिलाए, इसलिए ये तमाम चीज़ें सामने लाई जा रही हैं। अगर आप constructive चीज़ें लाते तो हम आपको झुककर सलाम करते, लेकिन आप destructive चीज़ें लाते हैं, आप तोड़ने की चीजें लाते हैं। आप देश को जोड़ने का काम नहीं करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। यह तोड़ने का काम, ताकि चौबीस घंटे -- यह शाहीन बाग वगैरह क्या है? यह तो आपकी creation है! आप ऐसे काम करेंगे, तो पूरे हिन्दुस्तान में शाहीन बाग हो ही जाएँगे। जैसे, जामिया मिलिया में हो गया कि अगर बुर्के पहनकर जाओगे और जेएनयू में जाओगे -- यह काम तो होगा ही! इस सरकार की मुसीबत यह है कि यह सरकार भी चलाना चाहती है, यह विपक्ष का रोल भी अदा करना चाहती है, सड़क पर जो दूसरे लोग रात-दिन करते हैं, वह काम भी यह खुद ही करना चाहती है। आप कितने काम कर सकेंगे? आप कोई एक काम तो responsibility से कीजिए! आप चाहे सरकार चलाने का काम हाथ में ले लीजिए, चाहे विपक्ष का काम कर लीजिए या चाहे तोड़ने का काम ले लीजिए। सच बोलने या सच के उलट जो बोलते हैं, जिसको बोलने की अनुमति पार्लियामेंट में नहीं है, वह बोलने का काम भी आप ही के ठेके है। अफवाहें फैलाने का काम भी आप ही के ठेके है। गलत कानून बनाना, जिसमें किसी से नहीं पूछना है, विपक्ष से नहीं पूछना है और लोकतंत्र को खत्म करना है, वह भी आप ही के हाथ में है। Institutions को खत्म करना है, वह काम भी आप ही ले लें, तो कितने काम आप हाथ में लेंगे? जब आप इतने काम हाथ में लेंगे, तो देश का यही हाल होगा और शाहीन बाग बनेंगे। आपने यह जो फैलाया है, इस पर मैं बाद में बताऊँगा, अभी मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ।

माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमें जो उम्मीद थी, वह यह थी कि उसमें ब्लैक मनी के बारे में कुछ चर्चा हो, जॉब्स के बारे में कोई चर्चा हो, जीडीपी कहाँ पहुँच गई, ग्रोथ कहाँ पहुँच गई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहाँ पहुँच गई और एग्रिकल्चरल ग्रोथ कहाँ पहुँच गई, इसके बारे में कोई चर्चा हो, लेकिन इन सबके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। आज महँगाई आसमान को छू रही है। सरकार ने आते ही डीज़ल और पेट्रोल की महँगाई की थी, लेकिन inflation कितना हुआ? पिछले दिसम्बर में तो इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पेट्रोल-डीज़ल तो पहले से ही महँगा था, लेकिन सब्जियाँ, दालें, onion, आदि सारी चीजें भी महँगी हो गईं। केरोसीन ऑयल, medical equipments आदि सारी चीजें बजट के बाहर हो गईं। सोना, सिल्वर, फुटवियर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, पंखे, टॉयलेट्स, स्टेनलेस स्टील, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, टायर्स, फूड प्रोसेसिंग आइटम्स, आखिर ऐसी कौन-सी चीज़ बाकी रही? ...**(व्यवधान)**... ईगो तो आसमान को छूती है। किसी एक चीज़ में भी महँगाई कम होने की बजाय आसमान छू रही है और इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया सरकार है! इसके बाद भी मुझे इस बात का खतरा था कि सेंट्रल हॉल में ये डेस्कस कहीं टूट न जाएँ। एक-एक चीज़ खत्म होती जा रही थी और बेंच उतनी ही जोर से बजाए जा रहे थे।

स्मार्ट सिटीज़ पहली दफा खत्म हुईं, लेकिन माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने यह बजट में डाल दिया, जबकि छः साल में जो पुरानी 100 स्मार्ट सिटीज़ थीं, उनमें सिर्फ 11 परसेंट रुपया अब तक खर्च हुआ है। उनमे सिर्फ 11 परसेंट रुपया खर्च हुआ और अभी पाँच और बन रहे हैं। यह उल्लेख करना जरूरी है कि ये तमाम चीजें हो रही हैं, गुमराह किया जा रहा है।

"तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ,
खिलौने देकर बहलाया गया हूँ।"

यह काम इस सरकार का है।

डिफेंस का एक मुद्दा बड़ा था, जिसके कारण वर्ष 2014 में आपकी सरकार आई। ऐसी कौन-सी पब्लिक मीटिंग थी, जिसमें माननीय प्रधान मंत्री जी ने डिफेंस की चर्चा नहीं की थी? आज उस डिफेंस के ऊपर आप सीएजी की रिपोर्ट देखिए, जो "Times of India" में छपी है। सियाचिन और लद्दाख में जो हमारे लोग हैं, उनके पास कोई चीज़ नहीं है। मैं उन चीज़ों का ज्यादा उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। मैं इनका बिल्कुल उल्लेख नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर भी उन तमाम चीज़ों का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, जिनका उल्लेख CAG ने किया है। मैं कहता तो आप कहते कि पाकिस्तानी है, लेकिन आप CAG को नहीं कह पाएंगे। CAG ने तमाम चीज़ें कही हैं कि डिफेंस के equipments की हालत क्या है, हमारी बाकी चीज़ों की हालत क्या है? आज कहां गए वे मुद्दे? आप जीत गए, सरकारें डिफेंस के नाम पर बन गईं और आज आप modernization of defence भूल गए, defence forces भूल गए, उनके कपड़े भूल गए, उनका खाना भूल गए, उनके equipments भूल गए, आप उनका modernization भूल गए। आप 24 घण्टे वोट लेने के लिए पड़ोसी देश, दुशमन देश का नाम लेते हैं, लेकिन उन दुश्मन countries की पराजय आपके भाषणों से नहीं होगी, वह फौज के सशक्तीकरण से संभव होगी, वह modernization से होगी। गालियां देने से वोट आएंगे, लेकिन गालियां देने से जंग नहीं जीती जाती। इसलिए modernization of defence forces और उनके equipments का modernization कीजिए, गालियां देने से कुछ नहीं होगा। मैं यह नहीं कहता कि गालियां मत दीजिए, लेकिन आप वह सिर्फ वोट लेने के लिए करते हैं। अगर मन से करना होता तो उसके लिए गाली नहीं है, उसके लिए फौज है, उसके लिए हथियार हैं, उसके लिए आधुनिक हथियार की जरूरत है, उसके लिए डिफेंस बजट की ज़रूरत है, जिसमें आपकी कोई रुचि नहीं है। कई न्यूज़पेपर्स ने लिखा है, अगर आप बजट के बाद परसों के न्यूजपेपर्स देखेंगे कि कई न्यूजपेपर्स ने लिखा है, कई writers ने लिखा है कि डिफेंस ने सेकण्ड सीट ले ली। आप अलग मंत्रालय बनाएं, अलग डिपार्टमेंट बनाएं या तीनों सेनाओं का अलग चीफ़ बनाएं, उससे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती।

'बेरोज़गारी', जो पूरे देश का मुद्दा है। क्या आपको मालूम है कि करोड़ों लोग अपने बच्चों को अपनी ज़मीन बेचकर, अपनी जायदाद बेचकर, अपने घर गिरवी रखकर, सड़कों पर मज़दूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आज वे बच्चे डिग्रियां हासिल करके खाली बैठे हैं, उनके सामने

अंधेरा है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं है। वह होगा भी कैसे, क्योंकि आप 10 करोड़ नौकरियां देने में असफल हुए, आप बिना सोचे-समझे नोटबंदी लाए, demonetization लाए, जिसकी वजह से लाखों उद्योग बंद हो गए, लाखों उद्योग बंद हुए तो लाखों मज़दूर भी घर पहुंच गए, उनमें से हज़ारों व्हाइट कॉलर्ड लोग भी थे, जो घर पहुंच गए। 'जीएसटी', जिसका आपने पहले विरोध किया, आपकी सरकार ने, आपके लीडर्स ने विरोध किया, बाद में आप उसे लाए, लेकिन उसे लाना नहीं आया। आप लोगों ने demonetisation के rules में डेढ़ सौ बार तब्दीली की, शायद करीब 100 बार जीएसटी के rules में भी तब्दीली की, उसकी वजह से कितने उद्योग बंद हो गए, उसके लिए आप अपनी गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं कि हमसे भूल हो गई, गलती हो गई और लोगों से हम क्षमा चाहते हैं कि हमने without application of mind ये चीज़ें की हैं, जिसकी वजह से हमने आधा देश बेकार कर दिया। आप यह भी नहीं करते हैं।

इसके बाद मैं एक ऐसे मुद्दे पर आता हूं, जिसके बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक-डेढ़ पेज लिखा गया। 5 अगस्त को तो हमने ज़िन्दगी में पहली बार ऐसा बिल पढ़ा, हम भी 40-42 साल से पार्लियामेंट में हैं। हमने यह भी पहली बार देखा कि ऐसे भी Bill आते हैं, इस तरह से भी कानून पास होते हैं। हमने यह भी पहली बार देखा कि कानून बनाने से पहले देश को कैसे गुमराह किया जाता है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में कहा कि जम्मू-कश्मीर में मिलिटेंट का कोई खतरा है, इसलिए अमरनाथ यात्रा को बंद कर दिया जाए और लोगों को वापिस बुलाया जाए और सबसे बड़ा मजाक यह था कि कहीं कोई बंदूक पकड़ी गई। उस स्टेट में हमने एक-एक दिन में एक-एक हजार बंदूकें, राइफल्स और ammunition पकड़ा है और हम उधर से पब्लिक मीटिंग करते जा रहे हैं। ऐसा कुछ बताते कि एटम बम आ रहा है। यह कहा गया कि sniper rifle पकड़ी गई है। आप इतने डरपोक हैं कि sniper rifle से पूरा हिंदुस्तान डर गया और आपने पूरी यात्रा स्थगित कर दी। बहरहाल आपने पूरी दुनिया को डरा दिया कि sniper rifle पकड़ी गई है। उस वक्त तकरीबन डेढ़ लाख के करीब टूरिस्ट्स कश्मीर के अंदर थे। मैं बाद में वहां गया और उन हाउस बोट्स में भी गया, वहां से टूरिस्ट्स जा नहीं रहा था। हाउस बोट वालों ने कहा कि आप जाइए, लेकिन पुलिस आई और उन्होंने कहा कि हम तुमको बंद कर देंगे अगर इनको जाने नहीं दिया, इनको भेज दो। तो पुलिस की हिमायत से आपने वहां से लोगों को निकाल दिया और वहां से Tourists withdraw किए, यात्री withdraw किए, यहां से वहां पर additional forces भेजी गईं। हमें लगता था कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है। आप बड़े अर्से से कह रहे थे कि PoK हमने नहीं लिया है, शायद PoK वापिस लेने की बात हो रही है। हमें लगा, ऐसा कुछ होने वाला है। रात में ही सब लीडर्स अंदर हो गए, सैकड़ों जेल में चले गए।

قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد) : مانئے ڈپٹی چیئرمین سر، میں اپنی طرف سے مانئے راشٹرپتی کے ابھیبھاشن کا دھنیواد کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ یہاں ابھی ستّہ دھاری پارٹی کیطرف سے یادو جی اور تریویدی جی نے بولا۔ میں یادو جی کو بہت اچھی طرح سے، بڑے عرصے سے جانتا ہوں، لیکن تریویدی جی کا گیان سننے کا پہلی دفعہ سدن میں موقع ملا۔ کتھائیں بھی، پوئٹری بھی، ہسٹری بھی، جغرافیہ بھی، فلم بھی، عربی بھی، پرشئن بھی، تو اس سے تو بڑے بھلے آدمی لگتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ٹیلی ویژن کے سامنے ان تمام چیزوں کا گیان نہیں دیتے ہیں۔ وہاں الٹا گیان دیتے ہیں۔ میں ان سے نویدن کروں گا کہ اگر وہاں بھی اچھا، سدبھاونا کا گیان پورے دیش کو دیں گے، تو بہت اچھا ہوگا۔

بہرحال، میں تریویدی جی کی ہی بات پکڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، وہ کرکے دکھاتے ہیں، تو اس پر میرا ایک شعر ہے۔ ان کروڑوں لوگوں کو چھہ سال پہلے جو وعدے کئے گئے تھے، ان کروڑوں لوگوں کو، جن کو پندرہ لاکھہ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ کروڑوں لڑکے لڑکیاں، جن کو نوکری دینے کا وعدہ کیا تھا، جن مزدوروں کے ساتھہ وعدہ کیا گیا تھا، جن کسانوں کے ساتھہ دوگنی آمدنی کا وعدہ کیا تھا، جن کروڑوں لوگوں کے ساتھہ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ مہنگائی ختم کی جائے گی، بیکاری ختم کی جائے گی، بیروزگاری ختم کی جائے گی، امن اور شانتی ہوگی اور سب کا ساتھہ، سب کا وکاس ہوگا، ان کروڑوں لوگوں کی طرف سے میں یہ کہنا

چاہتا ہوں کہ اگر آپ سب کچھ جو کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو کیوں نہیں کیا۔ میں ان کی طرف سے کہتا ہوں۔

تیرے وعدے پر جئے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا
کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا

اس کا یہ کہنا ہے کہ تیرے وعدے پر جئے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ اگر میں تیرے وعدے پر جیوں گا اور میں کہوں گا کہ میں مان گیا، تو یہ سمجھ لینا کہ میں بالکل جھوٹ کہہ رہا ہوں، کیوں کہ مجھے اعتبار ہی نہیں ہے، آپ کبھی سچ بول ہی نہیں سکتے اور اگر آپ سچ بولتے، تو میں خوشی سے مر جاتا، تو اس لئے آپ Selective ٹھیک کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو کہتے ہیں، نہیں کرتے ہیں۔ جو آپ کرتے ہیں، جن کا آپ نے الّیکھ کیا۔ آپ نے ٹرپل طلاق کی چرچا کی، آپ نے 370 کی بات کی، آپ نے سٹیزن شپ ایکٹ کی بات کی، یہ تمام چیزیں آپ ان چیزوں سے دھیان ہٹانے کے لئے کر رہے ہیں، تاکہ آپ نے چھہ سال سے جو وعدے کئے ہیں، انہیں آپ کو کوئی یاد نہ دلائے۔ آپ کو کوئی پندرہ لاکھہ یاد نہ دلائے،آپ کو کوئی دس کروڑ نوکری کا وعدہ یاد نہ دلائے، آپ نے کسانوں کے ساتھہ جو وعدے کئے تھے، وہ یاد نہ دلائے، مہنگائی ختم کرنے کے لئے جو وعدے کئے تھے، وہ یاد نہ دلائے، کالا دھن لانے کے لئے جو وعدے کئے تھے، وہ یاد نہ دلائے، کوئی روپیہ کی گرتی ہوئی قیمت یاد نہ دلائے۔ منموہن سنگھہ جی کو مانئے پردھان منتری جی نے کہا تھا کہ روپیہ کی قیمت کا وقار پہلے ختم ہوگا یا سرکار کا، اس کے بیچ میں ہوڑ لگی ہے، آج کس کے بیچ میں ہوڑ لگی ہے؟

یہ کوئی یاد نہ دلائے، اس لئے یہ تمام چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں۔ اگر آپ کنسٹرکٹو چیزیں لاتے تو ہم آپ کو جھک کر سلام کرتے، لیکن آپ ڈسٹرکٹو چیزیں لاتے ہیں، آپ توڑنے کی چیزیں لاتے ہیں۔ آپ دیش کو جوڑنے کا کام نہیں کرتے ہیں، توڑنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ توڑنے کا کام، تاکہ چوبیس گھنٹے – یہ شاہین باغ وغیرہ کیا ہے؟ یہ تو آپ کی کریئیشن ہے! آپ ایسے کام کریں گے، تو پورے ہندوستان میں شاہین باغ ہو ہی جائیں گے۔ جیسے، جامعہ ملّیہ میں ہو گیا کہ اگر برقعہ پہن کر جاؤگے اور جے۔این۔یو۔ میں جاؤگے – یہ کام تو ہوگا ہی۔ اس سرکار کی مصیبت یہ ہے کہ سرکار بھی چلانا چاہتی ہے، یہ وپکش کارول بھی ادا کرنا چاہتی ہے، سڑک پر جو دوسرے لوگ رات دن کرتے ہیں، وہ کام بھی یہ خود ہی کرنا چاہتی ہے۔ آپ کتنے کام کر سکیں گے؟ آپ کوئی ایک کام تو ذمہ داری سے کیجئے۔ آپ چاہے سرکار چلانے کا کام ہاتھ میں لے لیجئے، چاہے وپکش کا کام کر لیجئے یا چاہے توڑنے کا کام لے لیجئے۔ سچ بولنے یا سچ کے الٹ جو بولتے ہیں، جس کو بولنے کی اجازت پارلیمنٹ میں نہیں ہے، وہ بولنے کا کام بھی آپ ہی کے ٹھیکے ہے۔ افوہیں پھیلانے کا کام بھی آپ ہی کے ٹھیکے ہے۔ غلط قانون بنانا، جس میں کسی سے نہیں پوچھنا ہے، وپکش سے نہیں پوچھنا ہے اور لوک تنتر کو ختم کرنا ہے، وہ بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ انسٹی ٹیوشنس کو ختم کرنا ہے، وہ کام بھی آپ ہی لے لیں، تو کتنے کام آپ ہاتھ میں لیں گے؟ جب آپ اتنے کام ہاتھ میں لیں گے، تو دیش کا یہی حال ہوگا اور شاہین باغ بنیں گے۔ آپ نے یہ جو پھیلایا ہے، اس پر میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔

مائنے راشٹر پتی کے ابھیبھاشن میں ہمیں جو امید تھی، وہ یہ تھی کہ اس میں بلیک منی کے بارے میں کچھ چرچا ہو، جابس کے

بارے میں کچھ چرچا ہو، جی۔ڈی۔پی۔ کہاں پہنچ گئی، گروتھ کہاں پہنچ گئی، انڈسٹریل گروتھ کہاں پہنچ گئی اور ایگریکلچر گروتھ کہاں پہنچ گئی، اس کے بارے میں کوئی چرچا ہو، لیکن ان سب کے بارے میں کوئی چرچا نہیں ہوئی۔ آج مہنگائی آسمان چھو رہی ہے۔ سرکار نے آتے ہی ڈیزل اور پیٹرول کی مہنگائی کی تھی، لیکن انفلیشن کتنا ہوا؟ پچھلے دسمبر میں تو اس نے ریکارڈ توڑ دیا۔ پیٹرول ڈیزل تو پہلے سے ہی مہنگا تھا، لیکن سبزیاں، دالیں، پیاز وغیرہ ساری چیزیں بھی مہنگی ہو گئیں۔ کیروسن آئل، میڈیکل اکوپمینٹس وغیرہ ساری چیزیں بجٹ کے باہرہوگئیں۔ سونا، سلور، فٹ ویئر، الیکٹرونک آئٹمس، اے۔سی۔ ٹی۔وی۔، ریفریجریٹرس، پنکھے، ٹائلیٹس، اسٹینلیس اسٹیل، آٹوموبائل پارٹس، ٹائرس، فوڈ پروسیسنگ آئٹمس، آخر ایسی کون سی چیز باقی رہی؟ ... (مداخلت) ... ایگو تو آسمان کو چھوتا ہے۔ کسی ایک چیز میں بھی مہنگائی کم ہونے کی بجائے آسمان چھو رہی ہے اور اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑھیا سرکار ہے۔ اس کے بعد بھی مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ سینٹرل ہال میں یہ ڈیسکس کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ ایک ایک چیز ختم ہوتی جا رہی تھی اور بینچ اتنی ہی زور سے بجائے جا رہے تھے۔ اسمارٹ سٹیز پہلی دفعہ ختم ہوئیں، لیکن مانّئے فائنینس منسٹر نے یہ بجٹ میں ڈال دیا، جبکہ چھ سال میں جو پرانی سو اسمارٹ سٹیز تھیں، ان میں صرف گیارہ فیصد روپیہ اب تک خرچ ہوا ہے۔

ان میں صرف گیارہ فیصد روپیہ خرچ ہوا اور ابھی پانچ اور بن رہے ہیں۔ یہ الّیکھہ کرنا ضروری ہے کہ تمام چیزیں ہی رہی ہیں، گمراہ کیا جا رہا ہے۔

تمنّاؤں میں الجھایا گیا ہوں
کھلونے دیکر بہلایا گیا ہوں

یہ کام اس سرکار کا ہے۔

ڈفینس کا ایک مدّعا بڑا تھا، جس کی وجہ سے سال 2014 میں آپ کی سرکار آئی۔ ایسی کون سی پبلک میٹنگ تھی، جس میں مانّنے پردھان منتری جی نے ڈفینس کی چرچا نہیں کی تھی؟ آج اس ڈفینس کے اوپر آپ سی۔اے۔جی۔ کی رپورٹ دیکھئے، جو "ٹائمس آف انڈیا" میں چھپی ہے۔ سیاچین اور لدّاخ میں جو ہمارے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ میں ان چیزوں کا زیادہ الّیکھہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان کا بالکل الّیکھہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔

لیکن پھر بھی ان تمام چیزوں کا الّھیکہ نہیں کرنا چاہوں گا، جن کا الّیکھہ سی۔اے۔جی۔ نے کیا ہے۔ میں کہتا تو آپ کہتے کہ پاکستانی ہے، لیکن آپ سی۔اے۔جی۔ کو نہیں کہہ پائیں گے۔ سی۔اے۔جی۔ نے تمام چیزیں کہی ہیں کہ ڈفینس کے اکوپمینٹس کی حالت کیا ہے، ہماری باقی چیزوں کی حالت کیا ہے؟ آج کہاں گئےوہ مدّعے؟ آپ جیت گئے، سرکاریں ڈیفینس کے نام پر بن گئیں اور آج آپ ماڈرنائیزیشن آف ڈفینس بھول گئے، ڈفینس فورسیز بھول گئے، ان کے کپڑے بھول گئے، ان کا کھانا بھول گئے، ان کے اکوپمینٹس بھول گئے، آپ ان کا ماڈرنائیزیشن بھول گئے۔ آپ چوبیس

گھنٹے ووٹ لینے کے لئے پڑوسی دیش، دشمن دیش کا نام لیتے ہیں، لیکن ان دشمن کنٹریز کی پراجے آپ کے بھاشنوں سے نہیں ہوگی، وہ فوج کے سشکتی کرن سے ممکن ہوگی، وہ ماڈرنائیزیشن سے ہوگی۔ گالیاں دینے سے ووٹ آئیں گے، لیکن گالیاں دینے سے جنگ نہیں جیتی جاتی۔ اس لئے ماڈرنائیزیشن آف ڈفینس فورسیز اور ان کے اکوپمینٹس کا ماڈرنائیزیشن کیجئے، گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گالیاں مت دیجئے، لیکن آپ وہ صرف ووٹ لینے کے لئے کرتے ہیں۔ اگر من سے کرنا ہوتا تو اس کے لئے گالی نہیں، اس کے لئے فوج ہے، اس لئے ہتھیار ہیں، اس کے لئے جدید ہتھیار کی ضرورت ہے، اس کے لئے ڈفینس بجٹ کی ضرورت ہے، جس میں آپ کی روچی نہیں ہے۔ کئی نیوز پیپرس نے لکھا ہے، اگر آپ بجٹ کے بعد پرسوں کے نیوز پیپرس دیکھیں گے کہ کئی نیوز پیپرس نے لکھا ہے، کئی رائٹرس نے لکھا ہے کہ ڈفینس نے سیکنڈ سیٹ لے لی۔ آپ الگ منترالیہ بنائیں، الگ ڈیپارٹمینٹ بنائیں یا تینوں سیناؤں کا الگ چیف بنائیں، اس سے لڑائی نہیں لڑی جا سکتی۔

'بیروزگاری'، جو پورے دیش کا مدّعا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کروڑوں لوگ اپنے بچوں کو اپنی زمین بیچ کر، اپنی جائیداد بیچ کر، اپنے گھر گروی رکھہ کر، سڑکوں پر مزدوری کرکے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ آج وہ بچے ڈگریاں حاصل کرکے خالی بیٹھے ہیں، ان کے سامنے اندھیرا ہے، اس کے لئے کوئی کوشش نہیں ہے۔ وہ ہوگی بھی کیسے، کیوں کہ آپ دس کروڑ نوکریاں دینے میں ناکام ہوئے، آپ بنا سوچے سمجھے نوٹ بندی لائے، ڈی-مونیٹائزیشن لائے، جس کی وجہ سے لاکھوں ادھیوگ بند ہو

گئے، لاکھوں ادھیوگ بند ہوئے تو لاکھوں مزدور بھی گھر پہنچ گئے، ان میں سے ہزاروں وہائٹ کالرڈ لوگ بھی ہے، جو گھر پہنچ گئے۔ 'جی۔ایس۔ٹی۔'، جس کا آپ نے پہلے ورودھ کیا، آپ کی سرکار نے، آپ کے لیڈرس نے ورودھ کیا، بعد میں آپ اسے لائے، لیکن اسے لانا نہیں آیا۔ آپ لوگوں نے ڈی-مونیٹائزیشن کے رولس میں ڈیڑھ سو بار تبدیلی کی، شاید قریب سو بار جی۔ایس۔ٹی۔ کے رولس میں تبدیلی کی، اس کی وجہ سے کتنے ادھیوگ بند ہو گئے، اس کے لئے آپ اپنی غلطی ماننے کے لئے بھی تیار نہیں ہے کہ ہم سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی اور لوگوں سے ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہم نے وداؤٹ اپلی کیشن آف مائنڈ یہ چیزیں کی ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے آدھا دیش بیکار کر دیا۔ آپ یہ بھی نہیں کرتے ہیں۔

اس کے بعد میں ایسے مدّعے پر آتا ہوں، جس کے بارے میں راشٹرپتی کے ابھیبھاشن میں ایک ڈیڑھ پیج لکھا گیا۔ پانچ اگست کو تو ہم نے زندگی میں پہلی بار ایسا بل پڑھا، ہم بھی چالیس-بیالیس سال سے پارلیمنٹ میں ہیں۔ ہم نے یہ بھی پہلی بار دیکھا کہ ایسے بھی بل آتے ہیں، اس طرح سے بھی قانون پاس ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی پہلی بار دیکھا کہ قانون بنانے سے پہلے دیش کو کیسے گمراہ کیا جاتا ہے۔

جولائی کے آخری ہفتے میں کہا کہ جموں کشمیر میں ملیٹینٹ کا کوئی خطرہ ہے، اس لئے امرناتھ یاترا کو بند کر دیا جائے اور لوگوں کو واپس بلایا جائے اور سب سے بڑا مذاق یہ تھا کہ کہیں کوئی بندوق پکڑی گئی۔ اس اسٹیٹ میں ہم نے ایک ایک دن میں ایک ایک ہزار بندوقیں، رائفلس اور

ایمیونیشن پکڑا ہے اور ہم ادھر سے پبلک میٹنگ کرتے جا رہے ہیں۔ ایسا کچھ بتاتے کہ ایٹم بم آرہا ہے۔ یہ کہا گیا کہ اسنیپر رائفل پکڑی گئی ہے۔ آپ اتنے ڈرپوک ہیں کہ اسنیپر رائفل سے پورا ہندوستان ڈر گیا اور آپ نے پوری یاترا استھگت کر دی۔ بہرحال آپ نے پوری دنیا کو ڈرا دیا کہ اسنیپر رائفل پکڑی گئی ہے۔ اس وقت تقریبا ڈیڑھ لاکھ کے قریب ٹورسٹس کشمیر کے اندر تھے۔ میں بعد میں وہاں گیا اور ان ہاؤس بوٹس میں بھی گیا، وہاں سے ٹورسٹس جا رہا نہیں رہا تھا۔ ہاؤس بوٹ والوں نے کہا کہ آپ جائیے، لیکن پولیس آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم تم کو بند کر دیں گے اگر ان کو جانے نہیں دیا، ان کو بھیج دو۔ تو پولیس کی حمایت سے آپ نے وہاں سے لوگوں کو نکال دیا اور وہاں سے ٹورسٹ وڈرا گئے، یاتری وڈرا گئے، یہاں سے وہاں پر ایڈیشنل فورسیز بھیجی۔ ہمیں لگتا تھا کہ شاید کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ آپ بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ پی۔اوکے۔ ہم نے نہیں لیا ہے، شاید پی۔اوکے۔ واپس لینے کی بات ہو رہی ہے۔ ہمیں لگا ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ رات میں ہی سب لیڈرس اندر ہو گئے، سینکڑوں جیل میں چلے گئے۔

† بیاوکے۔ واپس لینے کی بات ہو رہی ہے۔ ہمیں لگا ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ رات میں ہی سب لیڈرس اندر ہو گئے، سینکڑوں جیل میں چلے گئے۔

श्री जावेद अली खान : आप तो दिल्ली में थे, वरना आप भी।

† **جناب جاوید علی خان** : آپ تو دہلی میں تھے، ورنہ آپ بھی۔

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मैं दिल्ली में था और उस समय पार्लियामेंट चल रही थी, वरना हम भी अभी किसी जेल में पड़े रहते। इस तरह से भी कानून लाया जाता है, हमने यह पहली दफ़ा देखा है। हम भी पंजाब के लिए कानून लाए, हम भी असम के लिए कानून लाए, हम मिजोरम के लिए भी कानून लाए, लेकिन इस तरीके से कानून लाया गया। फिर यहां सदन में भी बिल की कोई चर्चा नहीं। यहां 10 per cent representation backwards को देने के लिए एक दूसरा बिल लगा हुआ था और हम उसके लिए तैयारी करके आए थे। यहां पर बिल की चर्चा नहीं हुई, कोई discussion नहीं हुआ, Business Advisory Committee में नहीं आया, टाइम decide नहीं हुआ, lay नहीं हुआ, बिल criculate नहीं हुआ और जम्मू-कश्मीर Abrogation of Article 370 and downgrading of the State into two Union Territories का कानून यहां पेश हो रहा है। मैं समझता हूं और मैं जानता हूं कि इन छह सालों में हिंदुस्तान के एक-एक इंस्टीट्यूशन को एक-एक करके आपने खत्म किया और यह आखिरी इंस्टीट्यूशन था, जिसको आपने पांच अगस्त को खत्म कर दिया। आपने Parliamentary system, Parliamentary procedures and Parliamentary democracy को पांच अगस्त को खत्म किया। ये तमाम नींव जो पार्लियामेंट के कायदे-कानून होते हैं, उन सबको छोड़कर आपने जबरदस्ती यह कानून पास कर दिया। यह कभी नहीं हुआ था। हम अपनी पार्टीज़ को व्हिप नहीं दे पाए थे और दूसरी पोलिटिकल पार्टिज़ भी व्हिप नहीं दे पाईं, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था। क्योंकि जो बिल उस वक्त लिखा गया था, उसमें 10 परसेंट रिजर्वेशन थी और उसमें हम सरकार के साथ सहमत थे। इसी को आप सब का साथ कहते हैं। यही है सब का साथ, यही है सब का विकास और विश्वास ! 5 फरवरी, 2015 को जब मुफ्ती साहब और बीजेपी के लीडर्स के बीच यहां बातचीत चल रही थी, तो मैंने उसी वक्त बताया था, माननीय प्रधान मंत्री जी बैठे थे, स्वर्गीय अरुण जेटली जी भी बैठे थे, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि आप नॉर्थ-ईस्ट और जम्मू-कश्मीर में इतनी रुचि मत लीजिए, यह आपके बस का काम नहीं है। जम्मू-कश्मीर में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार मत बनाओ। आप जम्मू-कश्मीर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर नहीं जानते हो। आप नॉर्थ-ईस्ट के कल्चर को नहीं जानते हैं। यहां पर MoS, Home Affairs श्री रिजिजु जी बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके 22 या 26 ट्राइबल्स के अलग-अलग ग्रुप्स हैं, तो उन्होंने उठकर बताया, हां, हैं। आज जम्मू-कश्मीर में क्या हुआ? आप वहां सरकार बनाने के लिए घुस गए, लेकिन आपसे सरकार नहीं चली। आपने withdraw कर दिया, आप फिर सत्ता में रहना चाहते थे, फिर Governor Rule लाए, उससे भी आपकी भूख खत्म नहीं हुई, तो आपने स्टेट को ही खत्म कर दिया और अपने हाथ में ही ले लिया।

†Transliteration in Urdu script.

आपने नॉर्थ-ईस्ट का भी वही हाल किया। आप वहां पर NRC लाए तो क्या हुआ - पूरा नॉर्थ-ईस्ट जल गया। अब जो आपने जोड़ा है - किसी को inner-line, किसी को outer-line करके, किसी न किसी के साथ तोड़-फोड़ करके आपने अपने साथ रखा है, वरना नॉर्थ-ईस्ट में कोई आपके साथ नहीं है, आपकी सोच के साथ नहीं है, आपकी विचारधारा के साथ नहीं है, आप जबर्दस्ती जोड़-तोड़कर उनको अपने साथ लगा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के संबंध में दोनों सदनों में हम पर जिस प्रकार के आरोप लगाए गए - आज मैं इस सदन के माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि हम पर जो आरोप लगाए गए या जिस बुनियाद पर आर्टिकल 370 और downgrading of the States करके दो Union Territories बनायी थीं, उन्हें मैं पढ़ता हूं और उनका जवाब देता हूं। सरकार की तरफ से यह बताया गया था कि वहां पर unemployment थी, गरीबी थी। मैं RBI की Handbook पढ़ता हूं। 2019 में जम्मू-कश्मीर का unemployment rate 5.3 था और इंडिया का 6.1 था - वह ऑल इंडिया से नीचे है। इसी प्रकार से poverty ratio है, यह भी RBI का ही है, 2011-12 में जम्मू-कश्मीर में poverty ratio 10.4 था, जबकि ऑल इंडिया का 21.9 था। दूसरा बहाना बताया गया, जिसके बारे में अभी भी आप अपने भाषणों में बोलते हैं - अभी भी दिल्ली में यह बोला गया - आप इस बात को लिखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे इसके लिए एक महीने बड़ी research करनी पड़ी - 'Denied education to children -- Right to Education for children between 614 years of age has not been extended to J"&K.' यह एक सरकार को dismiss करने का और Union Territory बनाने का मौका बना, लेकिन मैं इस सदन को और सरकार को बताना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में 1954 से, जब बक्शी गुलाम मोहम्मद थे, तब से free and compulsory elementary education up to 14 and free education up to university है। मैं भी वहां पर free education के अंतर्गत university student रहा हूं। तो वहां पर university तक free education है और 1954 से free and compulsory elementary education है। आज आप हमें बताते हैं कि आपने 2011 का कानून नहीं बनाया है! आपमें से कई लोग तो 1954 में पैदा भी नहीं हुए थे, जब से वहां पर यह कानून है। यह आरोप हम पर इस सदन में और उस सदन में पढ़ा गया - comparison किया गया। आप देखिए, मैं हमारी education के संबंध में comparison देना चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर में 2015-16 में 11वीं और 12वीं क्लास में 58.6 students थे, जबकि गुजरात, जो मॉडल स्टेट था, उसमें 43 परसेंट थे। ऑल इंडिया में 56 परसेंट थे, तो हम ऑल इंडिया से भी 2 परसेंट ऊपर हैं। Girls' aged 15 years and above, जिन्होंने 8 साल की schooling की है, जम्मू-कश्मीर में 87 परसेंट और गुजरात में 75 परसेंट। Girls who attended school, aged below 15 years, जे एंड के में 27.4 परसेंट और गुजरात में 26 परसेंट था। Schoolong 10 or mor years, जे एंड के में 37.2 परसेंट और गुजरात में 35 परसेंट था।

हम पर दूसरा इलज़ाम लगा कि जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 की वजह से जमीन नहीं खरीदी जा सकती थी, इसलिए उद्योग नहीं लगे थे। मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में जब तक हमने सरकार छोड़ी, चार साल पहले, केंद्र और स्टेट में, 37 industrial estates थे और

4.00 P.M.

जम्मू-कश्मीर में तकरीबन 30 हजार छोटे-बड़े उद्योग थे। हमारे यहां जमीन 90 साल की लीज़ पर देना 60's से शुरू हुआ और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, Chenab Textile Industry, जो बिड़ला की है, कठुआ में लगी है, जिसमें तकरीबन 10 हजार का employment है, वह देश का एक बड़ा उद्योग है। वह इंडस्ट्री mid-60's में लगी है, 90 साल के लिए। हमारी 60's से लेकर अभी 2016 तक इंडस्ट्री लगाने के लिए 90 साल की लीज़ दी जाती थी, लेकिन आपकी सरकार 2015 में जो बनी, coalition government बनी, जिसमें आपके Deputy Chief Minister थे, उन्होंने 2016 में इस लीज की अवधि को 90 साल से घटाकर 40 साल कर दिया और आप हमें बताते हैं कि दफा 370 की वजह से उद्योग नहीं लगते थे।

आपने कहा, यह चौथा -पांचवां सवाल था, शादी के लिए minimum age for girls prescribed नहीं थी। शायद कानून न बना हो, लेकिन मैं भूल गया, मुझे इससे पहले देना चाहिए था, मैं इन तीनों को पटल पर रख रहा हूं, Government of India's Report, 2015-16, मैं जितने भी ये आंकड़े पढ़ रहा हूं और comparison बता रहा हूं, चाहे गुजरात हो, ऑल इंडिया हो या कश्मीर हो, इसे मैं पटल पर रख देता हूं। पांचवां आरोप था कि लड़कियों और लड़कों की शादी के लिए age prescribed नहीं थी। माना prescribed नहीं थी, माना पूरे हिंदुस्तान में prescribed है, माना गुजरात में भी prescribed है, लेकिन इस रिपोर्ट पर मुकाबला तो करे ज़रा Government of India! Girls married before 18 years of age, जम्मू-कश्मीर में 8.7 और गुजरात में 24.9 and all-India 26.8 है, तो प्रोग्रेसिव हम हैं कानून बनाए बगैर ही या आप हैं? हमारे यहां 18 साल से कम उम्र में विवाह का आंकड़ा 8.7 है, national level का 26.8 है, गुजरात का 24.9 है, जो कि almost 25 है। Girls aged between 15 and 19 who were either pregnant or became mothers, जो 15 और 19 साल के बीच में या तो गर्भवती हैं या मां बन गई हैं, जम्मू-कश्मीर में सिर्फ 2.9, गुजरात में 6.5 और ऑल इंडिया पर 7.9 है। यह हम पर आरोप था। वकील साहब, मैं पहले इसे आपको भेज दूंगा। हम पर छठा आरोप था, जो कि tribals, dalits को political reservation के संबंध में था।

मैं इस सदन के द्वारा बताना चाहता हूं कि हमारी एस.सी. की सर्विसेज में और MLAs में रिजर्वेशन बहुत अर्स से है। शैड्यूल्ड कास्ट की पोलिटिकल रिजर्वेशन भी है और लेजिस्लेशन में भी रिजर्वेशन है। जब तक हमारी सरकार रही, उसमें एस.सी./एस.टी. के 6 मंत्री रहे, हमारी कॉंग्रेस पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर 6 साल तक रहा और 6 साल तक वह स्पीकर रहा। इसलिए हमारी रिजर्वेशन एस.सी. के लिए सर्विसेज़ में भी है और विधान सभा में भी है। एस.टी. की रिजर्वेशन हमारी सर्विसेज़ में 10 परसेंट है और लेजिस्लेचर में नहीं थी, लेकिन उनकी लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन 8 परसेंट बनती थी, तो हमारी आउटगोइंग असेम्बली में 12 एस.टी. MLAs थे। हम उनको रिजर्वेशन उनकी संख्या से ज्यादा देते थे, लेकिन सर्विसेज़ में उनकी रिजर्वेशन थी।

फिर एक और क्वेश्चन आया कि यहां जो फॉरेस्ट एक्ट बना है, उसे हमारी गवर्नमेंट ने ट्रायबल्स के लिए बनाया था। जो नॉन ट्रायबल्स हैं, जो दूसरे हैं, वे फॉरेस्ट प्रोड्यूस का फायदा उठा सकते हैं, यह नहीं बनाया। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां तो यह महाराजा के ज़माने में बना, जिसमें कहा गया था कि वे फॉरेस्ट का फायदा उठा सकते हैं, अपने घर बनाने के लिए लकड़ी भी काट सकते हैं और घास चराई भी करा सकते हैं। उसके बाद 1987 में दोबारा कानून बना और मेरे वक्त में तीसरा कानून बना और आपकी सरकार आते ही उन सबको निकाल दिया। आपका आरोप था कि हम कानून नहीं बनाते, हमने तीन-तीन कानून बनाये और आपने उन सब को बगैर कानून के निकाल दिया। अभी एक और बात बताई गई, after the President's Rule, the people of Jammu & Kashmir are being provided better facilities of LPG, electricity, toilets, roads, etc. President's Rule तो 2018 में हुआ और यह 2016 की रिपोर्ट है। अब मैं इसी रिपोर्ट के हिसाब से पढ़ता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी हाउसहोल्ड जम्मू और कश्मीर -97.4 परसेंट, गुजरात - 96 परसेंट, हमसे डेढ़ परसेंट नीचे और ऑल इंडिया- 88 परसेंट है। Clean fuel for cooking and household use - Jammu & Kashmir 57.4 per cent, Gujarat 52.6 per cent, Sanitation, toilets, जिसकी आप बात करते हैं। वहां भी हम 52.5 परसेंट हैं, नेशनल लेवल 48.4 परसेंट है। इसके अलावा कहा गया कि हैल्थ की कोई सुविधा नहीं है। आर्टिकल 370 की वजह से वहां हैल्थ में कुछ नहीं होता था, स्टेट होने की वजह से हैल्थ में कुछ नहीं होता था। अगर हैल्थ में कुछ नहीं होता था, तो sex ratio में, जब हम सब चाहते हैं कि लड़कियों की संख्या बढ़ाई जाए, तो जम्मू और कश्मीर में एक हजार लड़कों के मुकाबले में 972 लड़कियां हैं और गुजरात में सिर्फ 950 लड़कियां हैं।

एनीमिक, जो गर्भवती नहीं हैं, जो 15 से 50 साल की औरतें हैं, वे जम्मू और कश्मीर में 49.5 परसेंट हैं और गुजरात में 55 परसेंट हैं। इसका मतलब है कि वहां पर 5 परसेंट एनीमिक ज्यादा हैं और देश भर में, नेशनल लेवल पर 53 परसेंट हैं, तो हम नेशनल ऐवरेज से भी ठीक हैं और गुजरात से भी ठीक हैं। जो गर्भवती औरतें हैं, जो 15 से 49 वर्ष की हैं, वे हमारी सिर्फ 47 परसेंट हैं और गुजरात में 51 परसेंट हैं। आपने women empowerment के बारे में कहा है कि women को कोई अखितियार नहीं था, हमने women को मुक्त किया, बड़ी आज़ादी दी। मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि married women have experienced spousal violence, सिर्फ 9.4 परसेंट और गुजरात में 20.1 परसेंट और नेशनल लेवल पर 31 परसेंट है, तो यह नेशनल लेवल से और गुजरात से कम है। महोदय, मैं बीच-बीच में स्किप भी करता जा रहा हूं। पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। सर, अब मैं women owning house or land के बारे में बताना चाहता हूं और घर या जमीन उसके नाम पर है या नहीं। जम्मू-कश्मीर में 35.3 और गुजरात में सिर्फ 27.2 प्रतिशत ऐसी महिलाएं हैं। औरतों के bank account उनके अपने नाम पर हैं और वे खुद चलाती हैं या नहीं इस बारे में बताना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में 60 परसेंट, गुजरात में सिर्फ 48

परसेंट और नेशनल लैवल का 53 परसेंट औसत है। जिन औरतों के पास मोबाइल फोन है और वे खुद चलाती हैं उनका प्रतिशत जम्मू-कश्मीर में 54.2, गुजरात में सिर्फ 47 और नेशनल लैवल पर सिर्फ 45 परसेंट है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि women aged between 15 and 25 years who used hygienic methods, a protection during the menstrual period, यह भी हैल्थ मिनिस्ट्री में जरूरी है।

*[*THE VICE-CHAIRMAN, (SHRI T.K. RANGARAJAN), *in the Chair]*

मैं बताना चाहता हूं कि it is 66.5 per cent in Jammu & Kashmir and national average is only 57.6 per cent, and even in Gujarat, it is only 60 per cent, 6 points less than Jammu & Kashmir. Men married before the age of 21 years, यानी 21 साल की उम्र से पहले कानूनन कितने लोग शादी करते हैं- जम्मू-कश्मीर में सिर्फ 10.5 परसेंट और गुजरात में 28.4 परसेंट तथा नेशनल लैवल पर 20 परसेंट। अब मैं बताना चाहता हूं कि 15 से 49 साल की उम्र तक के कितने आदमी anemic हैं, सिर्फ 20 परसेंट और नेशनल लैवल और गुजरात में इससे ज्यादा हैं। अब मैं बच्चों के बारे में बताना चाहता हूं। आप कहते हैं कि बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई। Infant mortality rate, शिशु मृत्युदर एक साल के अंदर 1000 में से कितने बच्चे मरते हैं। यह बात हेल्थ मिनिस्ट्री, देश और दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस बारे में जो सबसे बड़े पैरामीटर्स माने जाते हैं, तो उस देश के बच्चों से माने जाते हैं कि उस देश का स्वास्थ्य कैसा है। 1000 बच्चों में से जम्मू-कश्मीर में केवल 32 बच्चे मरते हैं और गुजरात में 34 बच्चे तथा नैशनल एवरेज 41 बच्चों का है। इसका मतलब है कि जम्मू-कश्मीर is the best. पांच साल में 1000 में से कितने बच्चे मरते हैं, यदि इसे देखा जाए, तो जम्मू-कश्मीर में 38, गुजरात में 43 और नैशनल लैवल पर 50. एक साल और दो साल के बीच, बच्चे को पूरे टीके कितने लगते हैं, यदि इसका प्रतिशत देखा जाए, तो जम्मू-कश्मीर में 75.1 परसेंट, गुजरात में 50 परसेंट और नेशनल लैवल 62 परसेंट है। Children who received the health checkup within the two days of birth - Jammu and Kashmir, 20.3%, Gujarat, 15.8% and nation level is 24%. चिल्ड्रन एक और दो साल के बीच में, जिन्हें बीसीजी के टीके लगाते हैं, उनका प्रतिशत 95.5 परसेंट जम्मू-कश्मीर में और गुजरात में केवल 80 परसेंट। मेरे पास इसमें बहुत आंकड़े और हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं जा रहा हूं।

महोदय, इन बुक्स के अनुसार केन्द्र सरकार 114 parameters पर सर्वे करती है। उसमें हैल्थ है, उसमें न्यूट्रिशन है, उसमें सेनिटेशन है, उसमें खाना है। इन 114 पैरामीटर्स में से जम्मू कश्मीर 80 पैरामीटर्स पर नेशनल एवरेज से ज्यादा है, जबकि Gujarat, it is only on 56 more than the national average. तो क्या मैं नहीं कहूं कि Gujarat is the fittest case of Governor's rule.

महोदय, ये चीजें हमारे प्रदेश में ज्यादा हैं और गुजरात में कम, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। क्योंकि एक बहाना बनाया गया कि आपकी जम्मू-कश्मीर स्टेट हमने इसलिए तोड़ी और दफा 370 आपने इसलिए खत्म किया, क्योंकि हमें दो स्टेट की गवर्निंग करनी नहीं आती। अगर हम

114 पैरामीटर्स में से 80 पैरामीटर्स पर नेशनल एवरेज से ज्यादा हैं, तो कितनी स्टेट्स को आज डिसमिस किया जाना चाहिए और यूनियन टैरीटरीज़ बनाया जाना चाहिए। आपकी अपनी स्टेट, माननीय प्रधान मंत्री जी की स्टेट नेशनल एवरेज से सिर्फ 52 प्वाइंट्स में ऊपर है, जम्मू-कश्मीर 80 प्वाइंट्स में ऊपर है, so, that is the fittest State to be made a Union Territory. इसलिए मैं यह सिद्ध करना चाहता था कि - यद्यपि मैंने टाइम लिया, लेकिन मैं यह सिद्ध करना चाहता था कि बहाने से, झूठ से, फरेब से, धोखे से इस देश को गुमराह कर दिया कि जम्मू-कश्मीर में कुछ नहीं होता। जिन लोगों ने - वे आज यहाँ नहीं हैं, वे चाहें फारुख अब्दुल्ला हों, उमर अब्दुल्ला हों या महबूबा जी हों, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद था, लेकिन वे वहाँ सरकार चला रहे थे। हमने अपनी जिंदगी पर खेलकर ये आंकड़े बनाए हैं - ये आंकड़े हवा में नहीं बने हैं, मैं ये जो आंकड़े पढ़ रहा हूँ, ये आंकड़े बनाने में उन सब लोगों ने, हम सब लोगों ने मेहनत की है, लेकिन फिर भी बदनाम किया जाता है कि ये चोर है, इनको जेल में बंद रखो। ...**(व्यवधान)**... नहीं, आप इस तरह से धोखा नहीं दे सकते हैं ...**(व्यवधान)**... देश को धोखा नहीं दे सकते हैं। ...**(व्यवधान)**...

†جناب غلام نبی آزاد : میں دہلی میں تھا اور اس وقت پارلیمنٹ چل رہی تھی، ورنہ ہم بھی ابھی کسی جیل میں پڑے رہتے۔ اس طرح سے بھی قانون لایا جاتا ہے، ہم نے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ ہم بھی پنجاب کے لئے قانون لائے، ہم بھی آسام کے لئے قانون لائے، ہم میزورم کے لئے بھی قانون لائے، لیکن اس طریقے سے قانون لایا گیا! پھر یہاں سدن میں بھی بل کی کوئی چرچا نہیں۔ یہاں دس فیصد ریزرویشن، بیک-ورڈس کو دینے کے لئے ایک دوسرا بل لگا ہوا تھا اور ہم اس کے لئے تیاری کرکے آئے تھے۔ یہاں پر بل کی چرچا نہیں ہوئی، کوئی ڈسکشن نہیں ہوا، بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں بھی نہیں آئی، ٹائم مقرر نہیں ہوا، لے نہیں ہوا، بل سرکلیٹ نہیں ہوا اور جموں کشمیر Abrogation of Article 370 and downgrading of the State into two Union Territories کا قانون یہاں بحث ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اس چھہ سالوں میں ہندوستان کے ایک ایک انسٹی ٹیوشنس کو ایک ایک کرکے آپ نے ختم کیا اور یہ آخری انسٹی ٹیوشن تھا، جس کو آپ نے پانچ اگست کو ختم کر دیا۔ آپ نے پارلیمنٹری سسٹم، پارلیمنٹری پروسیجر اینڈ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو پانچ اگست کو ختم کیا۔ یہ تمام برباد جو پارلیمنٹ کے قاعدے قانون ہوتے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر آپ نے زبردستی یہ قانون پاس کر دیا۔ یہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہم اپنی پارٹی کو وہپ نہیں دے پائے تھے اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی وہپ نہیں دے پائیں، کیوں کہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ کیوں کہ جو بل اس وقت لکھا گیا تھا، اس میں دس فیصد رزرویشن تھی اور اس میں ہم سرکار کے ساتھ

†Transliteration in Urdu script.

سہمت تھے۔ اسی کو آپ سب کا ساتھ کہتے ہیں۔ یہی ہے سب کا ساتھ، یہی ہے سب کا وکاس اور وشواس۔ پانچ فروری، 2015 کو جب مفتی صاحب اور بی جے پی۔ کے لیڈرس کے بیچ یہاں بات چیت چل رہی تھی، تو میں نے اسی وقت بتایا تھا، مانّئے پردھان منتری جی بیٹھے تھے، مرحوم ارون جیٹلی جی بھی بیٹھے تھے، تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ آپ نارتھ ایسٹ اور جموں کشمیر میں اتنی دلچسپی مت لیجئے، یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے۔ جموں کشمیر میں بی جے پی۔ کے ساتھ مل کر سرکار مت بناؤ۔ آپ جموں کشمیر کی ہسٹری، جغرافیہ اور کلچر نہیں جانتے ہو۔

آپ نارتھ ایسٹ کے کلچر کو نہیں جانتے ہیں۔ یہاں پر MoS, Home Affairs شری رجیجو بیٹھے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے 22 یا 26 ٹرائبلس کے الگ الگ گروپس ہیں، تو انہوں نے اٹھ کر بتایا ہاں، ہیں۔ آج جموں وکشمیر میں کیا ہوا؟ آپ وہاں سرکار بنانے کے لیے گھس گئے، لیکن آپ سے سرکار نہیں چلی۔ آپ نے withdraw کردیا، آپ پھر ستّہ میں رہنا چاہتے تھے، پھر گورنر رول لائے، اس سے بھی آپ کی بھوک ختم نہیں ہوئی، تو آپ نے اسٹیٹ کو ہی ختم کردیا اور اپنے ہاتھ میں ہی لے لیا۔ آپ نے نارتھ ایسٹ کا بھی وہی حال کیا۔ آپ وہاں پر این آر سی لائے تو کیا ہوا، پورا نارتھ ایسٹ جل گیا۔ اب جو آپ نے جوڑا ہے۔ کسی کو inner-line ، کسی کو outer-line کرکے، کسی نہ کسی کے ساتھ توڑ پھوڑ کرکے آپ نے اپنے ساتھ رکھا ہے، ورنہ نارتھ ایسٹ میں کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی سوچ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی وِچاردھارا کے ساتھ نہیں ہے، آپ زبردستی جوڑ توڑ کر ان کو اپنے ساتھ لگا رہے ہیں۔ جموں وکشمیر کے سمبندھ میں دونوں سدنوں میں ہم پر جس طرح کے الزام لگائے گئے، آج میں اس سدن کے مادھیم سے پورے سدن کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پر جو آروپ لگائے گئے ہیں جس بنیاد پر آرٹیکل 370 اور downgrading of the States کرکے دو Union

Territories بنائی تھی، انہی میں پڑھتا ہوں اور ان کا جواب دیتا ہوں۔ سرکار کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ وہاں پر بے روزگاری تھی، غریبی تھی۔ میں آر بی آئی کی رپورٹ بک پڑھتا ہوں، 2019 میں جموں وکشمیر کا unemployment rate 5.3 تھا اور انڈیا کا 6.1 تھا۔ وہ آل انڈیا سے نیچے ہے۔ اسی طرح سے poverty ratio ہے، یہ بھی آر بی آئی کا ہی ہے، 2011-12 میں جموں وکشمیر میں poverty ratio 10.4 تھا، جب کہ آل انڈیا کا 21.9 تھا۔ دوسرا بہانہ بنایا گیا جس کے بارے میں ابھی بھی آپ اپنے بھاشنوں میں بولتے ہیں۔ ابھی بھی دہلی میں یہ بولا گیا آپ اس بات کو لکھیئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے اس کے لئے ایک مہینے بڑی ریسرچ کرنی پڑی۔ 'Denied education to children -- Right to Education for children between 6-14 years of age has been extended to J&K.' یہ ایک سرکار کو dismiss کرنے کا اور Union Territory بنانے کے موقع بنا، لیکن میں اس سدن کو اور سرکار کو بتانا چاہتا ہوں کہ جموں وکشمیر میں 1954 سے، جب بخشی غلام محمد تھے، تب سے free and compulsory elementary education up to 14 and free education up to university ہے۔ میں بھی وہاں مفت تعلیم کے تحت یونیورسٹی اسٹوڈینٹ رہا ہوں۔ تو وہاں پر یونیورسٹی تک مفت تعلیم ہے اور 1954 سے free and compulsory elementary education up to 14 ہے آج آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے 2011 کا قانون نہیں بنایا ہے، آپ میں سے کئی لوگ تو 1954 میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب سے وہاں پر یہ قانون ہے۔ یہ آرٹیکل ہم پر اس سدن میں اور اس سدن میں پڑھا گیا، comparison کیا گیا آپ دیکھیئے، میں ہماری اپوزیشن کے سمبندھ میں comparison دینا چاہتا ہوں۔ جموں

وکشمیر میں 16-2015 میں گیارہویں اور بارہویں کلاس میں students 58.6 تھے، جب کہ گجرات، جو ماڈل اسٹیٹ تھا، اس میں 43 پرسینٹ تھے۔

آل انڈیا میں 56 فیصد تھے، تو ہم آل انڈیا سے بھی دو فیصد اوپر ہیں۔ Girls' aged 15 years and above, جنہوں نے آٹھ سال کی اسکولنگ کی ہے، جموں کشمیر میں 87 فیصد اور گجرات میں 75 فیصد۔ Girls who attended school, aged below 15 years, جے اینڈ کے میں 27.4 فیصد اور گجرات میں 26 فیصد تھا۔ Schooling 10 or more years, جے اینڈ کے میں 37.2 فیصد اور گجرات میں 35 فیصد تھا۔

ہم پر دوسرا الزام لگا کہ جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 کی وجہ سے زمین نہیں خریدی جا سکتی تھی، اس لئے ادھیوگ نہیں لگے تھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر میں جب تک ہم نے سرکار چھوڑی، چار سال پہلے، کینیدر اور اسٹیٹ میں، 37 انڈسٹریل اسٹیٹس تھے اور جموں کشمیر میں تقریبا تیس ہزار چھوٹے چھوٹے ادھیوگ تھے۔ ہمارے یہاں زمین نوے سال کی لیز پر دینا سکسٹیز سے شروع ہوا اور ایک بہت بڑی انڈسٹری، چناب ٹیکسٹائل انڈسٹری، جو بڑلا کی ہے، کٹھوا میں لگی ہے، جس میں تقریبا دس ہزار کا ایمپلائمینٹ ہے، وہ دیش کا ایک بہت بڑا ادھیوگ ہے وہ انڈسٹری مڈ-سکسٹیز میں لگی ہے، نوّے سال کے لئے۔ ہماری سکسٹیز سے لے کر ابھی 2016 تک انڈسٹری لگانے کے لئے نوّے سال کی لیز دی جاتی تھی، لیکن آپ کی سرکار 2015 میں جو بنی، کولیشن گوورنمینٹ بنی، جس میں آپ کے ڈپٹی چیف منسٹر تھے، انہوں نے 2016 میں اس لیز کی مدّت کو نوّے سال سے گھٹا کر چالیس سال کر دی اور آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ دفعہ 370 کی وجہ سے ادھیوگ نہیں لگتے تھے۔

آپ نے کہا، یہ چوتھا-پانچواں سوال تھا، شادی کے لئے minimum age for girls prescribed نہیں تھی۔ شاید قانون نہ بنا ہو، لیکن میں بھول گیا، مجھے اس سے پہلے دینا چاہئے تھا، میں ان نتیجوں کو پٹل پر رکھ رہا ہوں گوورنمنٹ آف انڈیا رپورٹ 2015-16 ، میں جتنے بھی یہ آنکڑے پڑھ رہا ہوں اور کمپیریزن کر بتا رہا ہوں، چاہے گجرات ہوں، آل انڈیا ہو یا کشمیر ہو، اسے میں پٹل پر رکھ دیتا ہوں۔ پانچواں آروپ تھا کہ لڑکیوں اور لڑکوں کی شادی کے لئے age prescribed نہیں تھی۔ مانا prescribed نہیں تھی، مانا پورے ہندوستان میں prescribed ہے، مانا گجرات میں بھی prescribed ہے، لیکن اس رپورٹ پر مقابلہ تو کریں ذرا۔ Government of India! Girls married before 18 years of age, جموں کشمیر میں 8-7 اور گجرات میں 24-9 اینڈ آل انڈیا 26-8 ہے، تو پروگریسو ہم ہیں، قانون بنائے بغیر ہیں یا آپ ہیں؟ ہمارے یہاں اٹھارہ سال سے کم عمر میں شادی کا آنکڑا 8-7 ہے، نیشنل لیول کا 26-8 ہے، گجرات کا 24-9 ہے، جو کہ almost 25 ہے۔ Girls aged between 15 and 19 who were either pregnant or became mothers, جو 15 اور 19 سال کے بیچ میں یا تو حاملہ ہیں یا ماں بن گئی ہیں، جموں کشمیر میں صرف 2-9، گجرات میں 6-5 اور آل انڈیا پر 7-9 ہے۔ یہ ہم پر آروپ تھا۔ وکیل صاحب، میں پہلے اسے آپ کو بھیج دوں گا۔ ہم پر چھٹا آروپ تھا، جو کہ ٹرائبلس، دلتس کو پولیٹیکل رزرویشن کے سمبندھ میں تھا۔

میں اس سدن کے ذریعہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ایس سی کی سروسز میں اور ایم ایل ایز میں ریزرویشن بہت عرصے سے ہے۔ شیڈیولڈ کاسٹ کی پالیٹیکل ریزرویشن بھی ہے اور لیجسلیشن میں بھی ریزرویشن ہے۔ جب تک ہماری سرکار رہی، اس میں ایس

سی، ایس ٹی کے چھ منتری رہے، ہماری کانگریس پارٹی کا ڈپٹی چیف منسٹر چھ سال تک رہا اور چھ سال تک وہ اسپیکر رہا۔ اس لئے ہماری ریزرویشن ایس سی کے لئے سروسز میں بھی ہے اور ودھان سبھا میں بھی ہے۔ ایس ٹی کی ریزرویشن ہماری سروسز میں بھی ہے اور ودھان سبھا میں بھی ہے۔ ایس ٹی کی ریزرویشن ہماری سروسز میں دس فیصد ہے اور لجسلیچر میں نہیں تھی، لیکن ان کی لجسلیچر میں ریزرویشن آٹھ فیصد بنتی تھی، تو ہماری آؤٹ گوئنگ اسمبلی میں بارہ ایس ٹی ایم ایل اے تھے۔ ہم ان کو ریزرویشن ان کی تعداد سے زیادہ دیتے تھے، لیکن سروسز میں ان کی ریزرویشن تھی۔

پھر ایک اور سوال آیا کہ یہاں جو فاریسٹ ایکٹ بنا ہے، اسے ہماری گورنمنٹ نے ٹرائبلس کے لئے بنایا تھا۔ جو نان ٹرائبلس ہیں، جو دوسرے ہیں، وہ فاریسٹ پروڈیوس کا فائدہ اٹھاسکتے ہیں، یہ نہیں بنایا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں تو یہ مہاراج کے زمانے میں بنا، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ فاریسٹ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے گھر بنانے کے لئے لکڑی بھی کاٹ سکتے ہیں اور گھاس چرائی بھی کراسکتے ہیں۔ اس کے بعد 1987 میں دوبارہ قانون بنا اور میرے وقت میں تیسرا قانون بنا اور آپ کی سرکار آتے ہی ان سب کو نکال دیا آپ نے ہمیں کہا کہ ہم قانون نہیں بناتے، ہم نے تین تین قانون بنائے اور آپ نے ان سب کو بغیر قانون کے نکال دیا یہ آروپ تھا۔ ابھی ایک اور بات بتائی گئی، after the President's Rule, the people of Jammu & Kashmir are being provided better facilities of LPG, electricity, toilets, roads, etc. ۔ یہ تو 2018 میں ہوا اور یہ 2016 کی رپورٹ ہے۔ اب میں اسی رپورٹ کے حساب سے پڑھتا ہوں کہ الیکٹریسٹی ہاؤس ہولڈ جموں وکشمیر 97.4 پرسینٹ، گجرات 96 پرسینٹ، ہم سے ڈیڑھ پرسینٹ نیچے اور آل انڈیا 88 پرسینٹ ہے۔ Clean fuel for

cooking and household use - Jammu & Kashmir 57.4 per cent, Gujarat 52.5 per cent, Sanitation, toilets, جس کی آپ بات کرتے ہیں۔ وہاں بھی ہم 52.6 پرسنٹ ہیں، نیشنل لیول 48.4 پرسنٹ ہے۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ ہیلتھ کی کوئی سہولیت نہیں ہے۔ آرٹیکل 370 کی وجہ سے وہاں ہیلتھ میں کچھ نہیں ہوتا تھا، اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ہیلتھ میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہیلتھ میں کچھ نہیں ہوتا تھا، تو Sex ratio میں، جب ہم سب چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعداد بڑھائی جائے، تو جموں وکشمیر میں ایک ہزار لڑکوں کے مقابلے میں 972 لڑکیاں ہیں اور گجرات میں صرف 950 لڑکیاں ہیں۔

ایلڈرلی، جو گربھوتی نہیں ہیں، جو پندرہ سے پچاس سال کی عورتیں ہیں، وہ جموں اور کشمیر میں 49.5 پرسنٹ ہیں اور گجرات میں 55 پرسنٹ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر پانچ پرسنٹ ایلڈرلی زیادہ ہیں اور دیش بھر میں، نیشنل لیول پر 53 پرسنٹ ہیں، تو ہم نیشنل ایوریج سے بھی ٹھیک ہیں اور گجرات سے بھی ٹھیک ہیں۔ جو گربھوتی عورتیں ہیں، جو 15 سے 49 سال کی ہیں، وہ ہماری صرف 47 پرسنٹ ہیں اور گجرات میں 51 پرسنٹ ہیں۔ آپ نے women empowerment کے بارے میں کہا ہے کہ women کو کوئی اختیار نہیں تھا، ہم نے women کو مُکت کیا، بڑی آزادی دی۔ میں وہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ married women have experienced spousal violence, صرف 9.4 پرسنٹ اور گجرات میں 20.1 پرسنٹ اور نیشنل لیول پر 31 پرسنٹ ہے، تو یہ نیشنل لیول سے اور گجرات سے کم ہے۔

مہودے، میں بیچ بیچ میں اسکپ بھی کرتا جا رہا ہوں۔ پورا نہیں پڑھ رہا ہوں۔ سر، اب میں women owning house or land کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اور گھر کی زمین اس کے نام پر ہے یا نہیں۔ جموں کشمیر میں 35.3 اور گجرات میں صرف 27.2 فیصد ایسی عورتیں ہیں۔ عورتوں کے بینک اکاؤنٹ ان کے اپنے نام پر ہیں اور وہ خود چلاتی ہیں یا نہیں اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر میں ساٹھ فیصد، گجرات میں صرف 48 فیصد اور نیشنل لیول کا 53 فیصد اوسط ہے۔ جن عورتوں کے پاس موبائل فون ہے اور وہ خود چلاتی ہیں ان کا فیصد جموں کشمیر میں 54.2، گجرات میں صرف 47 اور نیشنل لیول پر صرف 45 فیصد ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ women aged between 15 and 25 years who used hygienic methods, a protection during the menstrual period, وہ بھی ساٹھ منسٹری میں ضروری ہے۔

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN) *in the Chair.*)]

it is 66.5 per cent in Jammu & Kashmir and میں بتانا چاہتا ہوں کہ national average is only 57.6 per cent, and even in Gujarat, it is only 60 per cent, 6 points less than Jammu & Kashmir. Men married before the age of 21 years, بھی اکیس سال کی عمر سے پہلے قانونا کتنے لوگ شادی کرتے ہیں – جموں کشمیر میں صرف 10.5 فیصد اور گجرات میں 28.4 فیصد اور نیشنل لیول پر یہیں فیصد۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ 15 سے 49 سال کی عمر تک کے کتنے آدمی anemic

ہیں، صرف بیس فیصد اور نیشنل لیول اور گجرات میں اس سے زیادہ ہیں۔ اب میں بچوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی Infant mortality rate, بچوں کی شرح اموات ایک سال کے اند ایک ہزار میں سے کتنے بچے مرتے ہیں۔ یہ بات ہیلتھ منسٹری، دیش اور دنیا کے لئے بہت اہم ہے اور اس بارے میں جو سب سے بڑے پیرا میٹرس مانے جاتے ہیں، تو اس دیش کے بچوں سے مانے جاتے ہیں کہ اس دیش کا سواستھ کیسا ہے۔ ایک ہزار بچوں میں سے جموں کشمیر میں صرف 32 بچے مرتے ہیں اور گجرات میں 34 بچے اور نیشنل ایوریج 41 بچوں کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جموں کشمیر از دی بیسٹ۔ پانچ سال میں ایک ہزار میں سے کتنے بچے مرتے ہیں، اگر اسے دیکھا جائے، تو جموں کشمیر میں 38، گجرات میں 43 اور نیشنل لیول پر 50۔ ایک سال اور دو سال کے بیچ، بچے کو پورے ٹیکے کتنے لگتے ہیں، اگر اس کا فیصد دیکھا جائے، تو جموں کشمیر میں 75-1 فیصد، گجرات میں 50 فیصد اور نیشنل لیول 62 فیصد ہے۔ Children who received the health checkup within the two days of birth - Jammu & Kashmir, 20.3%, Gujarat, 15.8% and national level is 24%. چلڈرن ایک اور دو سال کے بیچ میں، جنہیں بی۔سی۔جی۔ کے ٹیکے لگاتے ہیں، ان کا فیصد 95-5 فیصد جموں کشمیر میں اور گجرات میں صرف 80 فیصد۔ میرے پاس اس میں بہت آنکڑے اور ہیں، لیکن میں ان میں نہیں جا رہا ہوں۔

مہودے، میں اس بکس کے مطابق کیندر سرکار 114 پیرامیٹرس پر سروے کرتی ہے۔ اس میں ہیلتھ ہے، اس میں نیوٹریشن ہے، اس میں سینیٹیشن ہے، اس میں کھانا ہے۔ ان 114 پیرامیٹرس میں سے جموں کشمیر 80 پیرامیٹرس پر نیشنل ایوریج سے زیادہ ہے،

جبکہ Gujarat, it is only on 52, more than the national average. تو کیا میں نہیں

کہوں کہ Gujarat is the fittest case for Governor's rule.

مہودے، یہ چیزیں ہمارے پردیش میں زیادہ ہے اور گجرات میں کم، اس لئے میں ایسا کہہ رہا ہوں۔ کیوں کہ ایک بہانا بنایا گیا ہے کہ آپ کی جموں کشمیر اسٹیٹ ہم نے اس لئے توڑی اور دفعہ 370 آپ نے اس لئے ختم کیا، کیوں کہ ہمیں دو اسٹیٹ کی گورننگ کرنی نہیں آتی۔ اگر ہم 114 پیرامیٹرس میں سے 80 پیرامیٹرس پر نیشنل ایوریج سے زیادہ ہے، تو کتنی اسٹیٹس کو آج ڈسمس کیا جانا چاہئے اور یونین ٹیریٹری بنایا جانا چاہئے۔

آپ کی اپنی اسٹیٹ، مانئیے پردھان منتری جی کی اسٹیٹ نیشنل ایوریج سے صرف باون پوائنٹس میں اوپر ہے، جموں وکشمیر اسی پوائنٹس میں اوپر ہے، so, that is the fittest State to be made a Union Territory. اس لئے میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اگر میں نے ٹائم لیا، لیکن میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ بہانے سے جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے، اس دیش کو گمراہ کردیا کہ جموں وکشمیر میں کچھ نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے وہ آج یہاں نہیں ہیں وہ چاہے فاروق عبداللہ ہوں، عمر عبداللہ ہوں یا محبوبہ جی ہوں، جموں وکشمیر میں آتنک واد تھا، لیکن وہ وہاں سرکار چلا رہے تھے۔ ہم نے اپنے زندگی پر کھیل کر یہ آنکڑے بنائے ہیں۔ یہ آنکڑے ہوا میں نہیں بنے ہیں، میں یہ جو آنکڑے پڑھ رہا ہوں، یہ آنکڑے بنانے میں ان سب لوگوں نے، ہم سب لوگوں نے محنت کی ہے، لیکن پھر بھی بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ چور ہیں، ان کو جیل میں بند رکھو۔ ...(مداخلت)... نہیں، آپ اس طرح سے دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں...(مداخلت)... دیش کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں...(مداخلت)...

श्री जुगलसिंह माथुरजी लोखंडवाला (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष जी...

श्री मोहम्मद अली खान (आंध्र प्रदेश): तुम लोग देश को तोड़ते हो। ...**(व्यवधान)**... तुम लोग देश को तोड़ते हो। ...**(व्यवधान)**... तुम लोग देश को तोड़ते हो। ...**(व्यवधान)**... तुम आतंकवादी हो ...**(व्यवधान)**... तुम लोग आतंकवादी हो ...**(व्यवधान)**... तुम लोग देश को तोड़ते हो। ...**(व्यवधान)**...

† **جناب محمد علی خان :** تم لوگ دیش کو توڑتے ہو ...(مداخلت)... تم لوگ دیش کو توڑتے ہو ...(مداخلت)... تم لوگ دیش کو توڑتے ہو ...(مداخلت)... تم لوگ آتنک وادی ہو تم لوگ دیش کو توڑتے ہو ...(مداخلت)... تم لوگ دیش کو توڑتے ہو تم لوگ دیش کو توڑتے ہو ...(مداخلت)...

श्री जुगलसिंह माथुरजी लोखंडवाला: आप लोग आतंकवादी हैं। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Please take your seat. ...*(Interruptions)*... Allow the Leader of the Opposition to speak. ...*(Interruptions)*...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मेरे कहने का यह मतलब था ...(**व्यवधान**)... मेरे कहने का मतलब था कि ये उपलब्धियाँ तभी हुईं। ...(**व्यवधान**)...

† **جناب غلام نبی آزاد:** میرے کہنے کا یہ مطلب تھا...(مداخلت)... میرے کہنے کا مطلب تھا کہ یہ اُپلبدھیاں تبھی ہوئیں...(مداخلت)...

एक माननीय सदस्य: काँग्रेस ने जम्मू-कश्मीर को आगे बढ़ाया। ...(**व्यवधान**)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मेरे कहने का मतलब है कि ये उपलब्धियाँ तभी हुईं और मुझे अफसोस है कि आज जिन लोगों ने, जिन सरकारों ने, जिन लीडर्स ने वहाँ आतंकवाद का मुकाबला किया, 50-60 हजार से ज्यादा लोग, नौजवान, मर्द, औरतें, जो आतंकवाद का शिकार हो गए, आज उनकी सराहना करने की बजाय उन्हें सलाखों के पीछे रखा जा रहा है। इसलिए थ्योरी के तौर पर उन लीडर्स को रिहा कर देना चाहिए और political activities शुरू करनी चाहिए। वहाँ नुकसान हुआ। वहाँ जम्मू का भी नुकसान हुआ, कश्मीर का भी नुक़सान हुआ, लद्दाख का भी नुकसान हुआ। इस तरह से तीनों हिस्सों का नुक़सान हुआ, देश का नुक़सान हुआ। वहाँ हमारी economy का नुक़सान हुआ, fruits का नुक़सान हुआ, agriculture का नुक़सान हुआ, handicrafts का नुक़सान हुआ, tourism का नुक़सान हुआ। जम्मू में सैंकड़ों उद्योग बंद हो गए, जम्मू की इंडस्ट्री बैठ गई, जम्मू का ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया, जम्मू में employment zero हो गई, जम्मू के restaurents, hotels वगैरह सब बैठ गए, जम्मू की दुकानें, जो कश्मीर की वजह से चलती थीं, क्योंकि कश्मीर के लोग जम्मू से सामान लेते थे, वे सब दुकानें बैठ गईं। आपको शायद ख्याल होगा कि खाली कश्मीर को नुक़सान हुआ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू को भी उतना ही नुक़सान हुआ, जितना कश्मीर के लोगों को नुक़सान हुआ है।

---

†Transliteration in Urdu script.

उपसभापति महोदय, एक हिस्सा, जो बॉर्डर का हिस्सा है, जो चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर का हिस्सा है, वहाँ अच्छी सरकार वही होती है, जो वहाँ के लोगों के साथ मिलकर चले और खराब सरकार वह होती है, जो वहाँ के लोगों के साथ लड़े। इसका मतलब है कि वे देश को कमजोर कर रहे हैं। देश में यकीनन आर्मी का रोल होता है, security forces का रोल होता है, लेकिन बॉर्डर स्टेट्स में लोगों का भी उतना ही रोल होता है, क्योंकि brunt वही लोग bear करते हैं। दुश्मन मुल्क से जब गोलियाँ चलती हैं, हथगोले चलते हैं, तो सबसे पहले लोगों के घरों पर गिरते हैं, फिर वह चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो या लद्दाख हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख, ईसाई हो। वहाँ हमारे सभी भाइयों का नुक़सान हुआ है। हमारे जम्मू के भाइयों का भी नुकसान हुआ है और कश्मीर के लोगों का भी नुक़सान हुआ है। जब भी ज्यादा आतंकवाद बढ़ता है और escalation हो जाता है, तो सबसे ज्यादा गोलियाँ, कठुआ, सांबा और जम्मू के लोगों पर गिरती हैं। इसलिए यह कहना कि जम्मू-कश्मीर में कुछ नहीं हुआ, उस पर मुझे पूरा विश्वास है कि यह सरकार अब अपनी गलती को मान जाएगी और स्टेट में तुरंत इसको बदल देगी। वह तुरंत इस UT system को खत्म करके स्टेट का बिल इसी सेशन में लाए और तमाम political parties के नेताओं को छोड़ दे, ताकि political activities शुरू हो जाएँ।

आखिर में मैं एक मिनट और लूँगा। पूरा देश दो महीने से सड़कों पर है, CAA को लेकर, NRC को लेकर, NPR को लेकर। मैंने कभी नहीं देखा है कि इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश में 90-90 साल, 80-80 साल के बूढ़े, औरतें-मर्द, 3 साल, 2 साल, एक साल, 3 महीने का बच्चा अपनी माँ की गोद में ठंड में बाहर 24 घंटे बैठे हों। लेकिन यह सरकार ऐसी सरकार है कि सरकार के किसी एक मंत्री ने यह स्टेटमेंट नहीं दिया कि आपकी problem क्या है, हम आपके पास जाएँ, हम आपको समझाएँ या आप हमें समझाएँ। सरकार war path पर है। आपके बयान कैसे हैं ! मंत्रियों के बयान कैसे हैं! मेरे मित्र, अच्छे साथी यादव जी ने गाँधी जी को बहुत इस्तेमाल किया। आपको गाँधी जी को इस्तेमाल करना है, जहाँ विपक्ष को डराना हो, लेकिन आपने गाँधी जी की हालत क्या की? आपके एमपीज़ ने गाँधी जी की क्या हालत की? मुझे शर्म आनी चाहिए कि वह एमपी हमारे colleague ही हैं। क्या इस सदन में वह दिन भी आ गया, चाहे यह सदन हो या वह सदन हो, कि भोपाल की एमपी, जिसने गाँधी जी का कत्ल किया, उस कातिल को हीरो मानती हैं और गाँधी जी को ज़ीरो मानती हैं। वे यहाँ आपकी मिनिस्टर हैं और अभी भी एमपी हैं। उन्होंने गॉधी जी के बारे में क्या-क्या कहा, मैं गाँधी जी के लिए वे गंदे शब्द अपने जुबान पर ला नहीं सकता और आप गाँधी जी के हितैषी हैं। आप गॉधी जी को 24 घंटे इस्तेमाल करने के लिए मानते हैं। आपमें हिम्मत नहीं है कि आप उन दो एमपीज़ को suspend करें, dismiss करें, पार्टी से निकाल दें। आपमें हिम्मत नहीं है। जो मंत्री गालियाँ देते हैं, उनको suspend करने के लिए नोटिस देने की हिम्मत भी आपको नहीं है। कभी तो कुछ दिखाइए। जब आप यह नहीं करते हैं, तब आप पर शक होता है कि यह सब कुछ आपकी वजह से होता है, आप सब ही इसके पीछे होते हैं।

मैं माननीय राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूँ। उनकी मजबूरी है, सरकार जो बना कर दे, उसे हर राष्ट्रपति को पढ़ना पड़ता है। आपकी सरकार ने बना कर दिया, लेकिन उन तमाम चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया, जो आपने वादे किए थे। आपने उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया। आप जो भी चीज़ लाएँगे, विवादित चीज़ लाएँगे, ताकि लोगों का ध्यान उन तमाम मुद्दों से हट जाए, जिन पर आपने वादे किए थे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी के भाषण का धन्यवाद करता हूँ।

† **جناب غلام نبی آزاد**: میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اُپلبدھیاں تبھی ہوتیں اور مجھے افسوس ہے کہ آج جن لوگوں نے، جن سرکاروں نے، جن لیڈرس نے وہاں آتنک واد کا مقابلہ کیا، 60-50 ہزار سے زیادہ لوگ، نوجوان، مرد، عورتیں، جو آتنک واد کا شکار ہوگئے، آج ان کی سراہنا کرنے کی بجائے انہیں سلاخوں کے پیچھے رکھا جارہا ہے۔ اس لئے تھیوری کے طور پر ان لیڈرس کو رہا کردینا چاہیئے اور پالیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کرنی چاہیئے۔ وہاں نقصان ہوا۔ وہاں جموں کا بھی نقصان ہوا، کشمیر کا بھی نقصان ہوا، لداخ کا بھی نقصان ہوا۔ اس طرح سے تینوں حصوں کا نقصان ہوا، دیش کا نقصان ہوا۔ وہاں ہماری اکانامی کا نقصان ہوا۔ فروٹس کو نقصان ہوا، سیاحت کا نقصان ہوا۔ جموں میں سیکڑوں صنعتیں بند ہوگئیں، جموں کی انڈسٹری بیٹھ گئی، جموں کا ٹرانسپورٹ ختم ہوگیا، جموں میں ایمپلائنمنٹ زیرو ہوگئی، جموں کے ریسٹورینٹ، ہوٹل وغیرہ سب بیٹھ گئے، جموں کی دکانیں، جو کشمیری کی وجہ سے چلتی تھیں، کیوں کہ کشمیر کے لوگ جموں سے سامان لیتے تھے، وہ سب دکانیں بیٹھ گئیں۔ آپ کو شاید خیال ہوگا کہ خالی کشمیر کو نقصان ہوا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جموں کو بھی اتنا ہی نقصان ہوا، جتنا کشمیر کے لوگوں کو نقصان ہوا ہے۔

اُپ سبھاپتی مہودے، ایک حصہ، جو بارڈر کا حصہ ہے، جو چین اور پاکستان کے بارڈر کا حصہ ہے، وہاں اچھی سرکار وہی ہوتی ہے، جو وہاں کےلوگوں کے ساتھ ملکر چلے اور خراب سرکار وہ ہوتی ہے، جو وہاں کے لوگوں کے ساتھ لڑے۔ اس کا مطلب

†Transliteration in Urdu script.

ہے کہ وہ دیش کو کمزور کررہے ہیں۔ دیش میں یقیناً آرمی کا رول ہوتا ہے، سیکورٹی فورسیز کا رول ہوتا ہے، لیکن بارڈر اسٹیٹس میں لوگوں کا بھی اتنا ہی رول ہوتا ہے، کیوں کہ brunt وہی لوگ bear کرتے ہیں۔ دشمن ملک سے جب گولیاں چلتی ہے، ہتھ گولے چلتے ہیں، تو سب سے پہلے لوگوں کے گھروں پر گرتے ہیں، پھر وہ چاہے جموں ہو، کشمیر ہو یا لداخ ہو، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو یا سکھ، عیسائی ہو۔ وہاں ہمارے سبھی بھائیوں کا نقصان ہواہے۔ ہمارے جموں کے بھائیوں کا بھی نقصان ہوا ہے اور کشمیر کے لوگوں کا بھی نقصان ہوا ہے۔ جب بھی زیادہ آتنک واد بڑھتا ہے اور ایسکلیشن ہوجاتا ہے، تو سب سے زیادہ گولیاں، کٹھوعہ، سامبا اور جموں کے لوگوں پر گرتی ہیں۔ اس لئے یہ کہنا کہ جموں وکشمیر میں کچھ نہیں ہوا، اس پر مجھے پورا وشواس ہے کہ یہ سرکار اب اپنی غلطی کو مان جائے گی اور اسٹیٹ میں فوراً اس کو بدل دیگی۔ وہ فوراً اس یونٹی سسٹم کو ختم کرکے اسٹیٹ کا بل اسی سیشن میں لائے اور تمام پالیٹکل پارٹیز کے نیتاؤں کو چھوڑ دے، تاکہ پالیٹکل ایکٹیویٹیز شروع ہوجائے۔

آخر میں، میں ایک منٹ اور لونگا۔ پورا دیش دو مہینے سے سڑکوں پر ہے، سی اے اے کو لیکر، این آر سی کو لیکر، این پی آر کو لیکر۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر پورے دیش میں نوّے نوّے سال، اسی اسی سال کے بوڑھے، عورتیں، مرد، تین سال، دوسال، ایک سال اور تین مہینے کا بچہ اپنی ماں کی گود میں ٹھنڈ میں باہر چوبیس گھنٹے بیٹھے ہوں۔ لیکن یہ سرکار ایسی سرکار ہے کہ سرکار کے کسی ایک منتری نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ آپ کی پرابلم کیا ہے، ہم آپ کے پاس جائیں، ہم آپ کو سمجھائیں یا آپ ہمیں سمجھائیں۔ سرکار war path پر ہے۔ آپ کے بیان کیسے ہیں، منتریوں کے بیان کیسے ہیں، میرے دوست، اچھے ساتھی یادو جی نے گاندھی جی کو بہت استعمال کیا، آپ کو گاندھی جی کو استعمال کرنا ہے، جہاں وپکش کو ڈرانا ہو، لیکن آپ نے گاندھی جی کی حالت کیا کی؟ آپ کے ایم پی نے گاندھی جی کی

† کیا حالت کی؟ مجھے شرم آنی چاہیئے کہ وہ ایم پی ہمارے colleague ہی ہیں۔ کیا اس سدن میں وہ دن بھی آگیا، چاہے یہ سدن ہو یا وہ سدن ہو، کہ بھوپال کی ایم پی جس نے گاندھی جی کا قتل کیا، وہ قاتل کو ہیرو مانتی ہیں اور گاندھی جی کو زیرو مانتی ہیں۔ وہ یہاں آپ کی منسٹر ہیں اور ابھی بھی ایم پی ہیں۔ انہوں نے گاندھی جی کے بارے میں کیا کیا کہا، میں گاندھی جی کے لیے وہ گندے شبد اپنی زبان پر لا نہیں سکتا اور آپ گاندھی جی کے ہتیشی ہیں۔ آپ گاندھی جی کو چوبیس گھنٹے استعمال کرنے کے لیے مانتے ہیں۔ آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ ان دو ایم پیز کو suspend کریں، ڈِس مِس کریں، پارٹی سے نکال دیں۔ آپ میں ہمت نہیں ہے۔ جو منتری گالیاں دیتے ہیں، ان کو suspend کرنے کے لیے نوٹس دینے کی ہمت بھی آپ کو نہیں ہے۔ کبھی تو کچھ دکھایئے۔ جب آپ یہ نہیں کرتے ہیں، تب آپ پر شک ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ سب ہی اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔

میں مانیئے راشٹرپتی جی کا دھنیواد کرتا ہوں۔ ان کی مجبوری ہے، سرکار جو بنا کر دے، اسے ہر راشٹرپتی کو پڑھنا پڑتا ہے۔ آپ کی سرکار نے بناکر دیا، لیکن ان تمام چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیا، جو آپ نے وعدے کیے تھے۔ آپ نے ان میں سے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا۔ آپ جو بھی چیز لائیں گے، متنازع چیز لائیں گے، تاکہ لوگوں کا دھیان ان تمام مدعوں سے ہٹ جائے، جن پر آپ نے وعدے کیئے تھے۔

انہیں شبدوں کے ساتھ میں راشٹرپتی جی کے بھاشن کا دھنیواد کرتا ہوں۔

(ختم شد)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGRAJAN): Thank you Ghulam Nabiji. Next speaker is Shri Sukhendu Sekhar Ray.

श्री सुखेन्दु शेखर राय (पश्चिमी बंगाल): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पहले चेयर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी की तरफ से जो संशोधन लाए गए, उनमें से कुछ संशोधनों को स्वीकार

†Transliteration in Urdu script.

किया गया है। हालाँकि हमारी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस 1998 में foundation के बाद आज तक कभी भी महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण के ऊपर कोई amendment नहीं लाई, लेकिन इस बार हम क्यों लाए, क्योंकि हम लाचार हैं। इस भाषण में बहुत सारी चीजें कही गईं और बहुत सारी चीजें नहीं भी कही गईं। मैं मित्र भूपेन्द्र यादव जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने संविधान का पाठ किया, ध्यान से सुना, बहुत अच्छा बोला। हमारे दूसरे साथी, सुधांशु जी ने राजा शिबि से शुरू करके उपनिषद्, पुराण, वगैरह-वगैरह बहुत सारी धर्म कथाओं को सुनाया। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति जी के भाषण पर नजर डालते हैं, तो पहले ही उन्होंने हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा की। हालांकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जी जो कुछ भी कहते हैं, वह सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। राष्ट्रपति जी वह रिपोर्ट खुद नहीं बनाते हैं। राष्ट्रपति जी ने हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत सारे आंकड़े दिए। हमारे नेता विरोधी दल, श्री गुलाम नबी आज़ाद ने भी कुछ बातें कहीं, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन हमें अफसोस है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि हिन्दुस्तान में, Reserve Bank of India के इतिहास में पहली बार उन्हें अपने ही फोरकास्ट को तीन दफ़ा चेंज करना पड़ा। आरबीआई ने पिछले साल फरवरी महीने में domestic growth rate का जो फोरकास्ट किया था, वह था 7.4%, फिर दो महीने के अंदर, अप्रैल महीने में उन्होंने उसको घटाकर 7.2% किया और फिर नवम्बर महीने में घटाकर 6.4% किया और फिर दिसम्बर महीने में उसको 5.0% कर दिया। रिज़र्व बैंक के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं घटी। International Monetary Fund has slashed India's 2019 growth rate forecast to 4.8 per cent from 6.1 per cent it projected in October last. Both the United Nations and the World Bank have cut India's Financial Year 2020 growth forecast to 5.7 and 5.0 per cent respectively. तो हमारी आर्थिक स्थिति की यह असलियत है, जिसका राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है और बजट में भी इसको छुपाया गया है।

Sir, this five per cent growth rate projection is the lowest in the past one year. Inflation rate is the highest in the last three year. Industrial growth rate is the lowest in the past 14 years. Demand for electricity consumption is the lowest in the last 12 years. Private investment is the lowest in the last 16 years and the unemployment index is alarmingly high in the last 45 years. और इसके बारे में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक शब्द भी नहीं है।

सर, अभी 15 दिन पहले Davos में Oxfam Report निकली थी, उसमें क्या बताया गया था? हालांकि सरकार तो मानेगी नहीं, लेकिन यह Internationally acclaimed organisation है। उसमें बताया गया है, "India's richest one per cent hold more than four times the wealth held by 953 million people of India, who make up for the bottom 70 per cent of the country's population while the total wealth of all Indian billionaires is more than full

year Budget of our country." पिछले financial year में हमारे बजट में जितना allocation था, उससे भी ज्यादा पैसा इन billionaires के पास है। ये कितने billionaires हैं, मैं आपको उसके फिगर्स भी देना चाहता हूं। हमारे पिछले financial year में budget allocation 24,42,200 लाख करोड़ रुपये था। इससे भी ज्यादा धन सिर्फ 63 Indian billionaires के पास है। यह हमारे भारत की आर्थिक स्थिति का चेहरा है कि हमारे बजट से भी ज्यादा पैसा सिर्फ 63 आदमियों के पास है। अब यह सवाल पैदा होता है कि क्या इन billionaires का हिन्दुस्तान में रहना जरूरी है? अगर रिफॉर्म्स का यह चेहरा है, तो मेरे ख्याल से रिफॉर्म्स को भी रिफॉर्म करने की जरूरत है? हमें यह करना ही पड़ेगा। सर, पिछले एक साल से यहां से कमाई करके 5,000 billionaires इंडिया से भागकर बाहर चले गए और वहां कारोबार कर रहे हैं। वे यहां कारोबार नहीं करना चाहते हैं।

As per the Report, it would take a female domestic workers, हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बहुत सारी नारेबाज़ी करते हैं और कहानियां सुनाते रहते हैं। किसी technology company के CEO की एक साल की जो तनख्वाह है, अगर उतनी तनख्वाह कोई female domestic worker कमाना चाहती है, तो उस female domestic worker को कितना समय लगेगा? उसको उतना पैसा कमाने में 22,277 साल लगेंगे। क्या चित्र है! It further said that women and girls put in 3.26 billion hours of unpaid care work each and every day. आपकी जो महिलाएँ और छोटे-छोटे बच्चे 3.26 billion hours काम करते हैं, ये unpaid हैं। इनको कोई पैसा नहीं मिलता है। अगर आप उसका हिसाब करते हैं कि उस समय में कितनी कमाई होनी चाहिए थी, तो वह है- 93,000 करोड़। तो जिससे देश को 93,000 करोड़ आमदनी होती है, उस domestic worker को एक पैसा भी नहीं मिलता है। इस बारे में भी राष्ट्रपति जी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब सरकार बोलेगी, तभी तो राष्ट्रपति जी बोलेंगे। Statistics जो कभी-कभी देते हैं, आजकल तो ज्यादा देते ही नहीं हैं, NSSO की जुबान बन्द कर दी गयी है। उसमें भी jugglery है, बहुत सारी juggleries हैं। ऐसा चित्र दिखाते हैं कि इतना उजला भारत, 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत', ऐसे कितने नारे हैं, भगवान जाने, जो ये लोग दिखाते हैं, बोलते हैं। अभी असलियत क्या है? हमने देखा कि जब नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जी राष्ट्रीय कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चेयरमैन बनाया गया था। यह उनकी दूरदृष्टि थी कि हम जब स्वाधीन होंगे, आज़ाद होंगे, तब प्लानिंग कमीशन हमारे देश की प्लानिंग करेगा, हमारा ठीक से आर्थिक सुधार करेगा। प्लानिंग कमीशन का विलय कर दिया गया और नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग में जो लोग बैठे हैं, वे फर्जी चित्र बनाते हैं, Development and Planning का फर्जी चित्र बनाते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसका भी विलय कर देना चाहिए। This white elephant must go.

सर, जब पिछली सरकार थी, तब बहुत से इलज़ाम लगाये गये कि आकाश बेच रहे हो, पाताल बेच रहे हो, लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो? आपने बोला था कि हम देश को बेचने

नहीं देंगे, लेकिन आप यह क्या कर रहे हैं? आप सब कुछ बेच रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... इनको हम थोड़ा-बहुत दिखाते हैं। आप क्या-क्या बेच रहे हैं, मैं थोड़ा-बहुत आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले तो LIC की चर्चा करनी चाहिए। पहले LIC की चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि LIC आपका एक ऐसा प्रतिष्ठान है, जिसकी unrealised loan amount up to September 2019, ₹ 30,000 crore है। LIC का 30,000 करोड़ कुछ कम्पनीज़ ने खा लिया। ये कम्पनीज़ कौन सी हैं- Deccan Chronicle, Essar Port, Gammon, IL&FS, Bhushan Power, Videocon Industries, Alok Industries, Amtrak Auto, ABG Shipyard, Unitech, GVK Power ad GTL. इन सब कम्पनीज़ ने LIC के 30,000 करोड़ रुपये खा लिये। यह जो 30,000 करोड़ चला गया, उसमें से 25000 करोड़ Insurance business fund से disburse किया गया था और insurance कराने वाले लोग जो premium देते हैं, उसके भाग से 2,500 करोड़ उस फंड से चला गया, 5,000 करोड़ पेंशन फंड से गया और 500 करोड़ ULIP fund से गया। यह किसका पैसा है? देश की जनता का पैसा है। उन कम्पनीज़ के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी, आज तक सरकार ने न तो इस सदन को और न ही उस सदन को कुछ बताया, देश की जनता को कुछ नहीं बताया। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। हमें अफसोस है। हम अपना खेद जताते हैं।

LIC had to experience this unprecedented situation. The LIC had to purchase shares of loss-making bank, the IDBI, amounting to ₹21,024 crore under the instructions of the Finance Ministry. आईडीबीआई जो कि लॉस मेकिंग बैंक है, उसके 21,024 करोड़ रुपये के शेयर्स आपको खरीदने पड़े, आपको मजबूर किया गया और एक-एक शेयर किलने पैसे में खरीदना पड़ा, एक-एक शेयर 60-61 रुपये में खरीदा। चंद महीनों में उस शेयर का भाव गिरकर 27 रुपये पर आ गया, जबकि उसकी खरीद 60-61 रुपये में की गई थी और दो-तीन महीने में वह शेयर डाउन होकर 27 रुपये पर आ गया। एलआईसी को बर्बाद करने का यह तरीका शुरू हो गया है।

अब मैं इस पर आता हू कि लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। The Government must inform this House as to why LIC was compelled to provide such huge amount of money to a perennial loss-making bank. The Government must reply. Now, the Government has decided to sell shares of both LIC and IDBI. अब एलआईसी और आईडीबीआई के शेयर्स बेचेंगे। इसे हम विक्रेता सरकार कहते हैं। जैसे बोलते हैं - खेलो सरकार, अब कहते हैं - बेचो सरकार। जैसे खेलो इंडिया, अब उसकी जगह बेचो इंडिया हो गया। This विक्रेता सरकार has set a disinvestment target. उसी में वह बोल रहे हैं कि हमारा डिसइन्वेस्टमेन्ट टारगेट कितना है, यह 2.8 लाख करोड़ है और इस 2.8 लाख करोड़ डिसइन्वेस्टमेन्ट का जो टारगेट है, यह 90 हजार करोड़ रुपये आएगा। एलआईसी और आईडीबीआई का शेयर बेचने के बाद हमारे पास 90 हजार करोड़ रुपये आएंगे। इसलिए एलआईसी का शेयर बाजार में छोड़ दिया गया। अब जितने हर्षद मेहता जैसे लोग हैं, वे इसका पूरा फायदा उठाएंगे। मैं एलआईसी के बारे में क्यों

बोल रहा हूं? ये हमारे देश के करोड़ों लोगों का जीवन बीमा करते हैं, जबकि जीवन बीमा कॉरपोरेशन का खुद का बीमा नहीं है, इनका खुद इंश्योरेंस नहीं है। यह कल रहेगा या नहीं रहेगा, ये कुछ बता नहीं सकते हैं। जिसका खुद का अपना इंश्योरेंस नहीं है, हमारे इंश्योरेंस को बर्बाद करने के लिए सरकार ने यह नीति अपनाई है।

सर, 1956 में एलआईसी किसने बनाया था, इसे पंडित नेहरू ने बनाया था। आजकल नेहरू जी की बहुत आलोचना हो रही है। एलआईसी में उस समय सरकार ने पांच करोड़ रुपये कैपिटल दी थी। 1956 में पांच करोड़ रुपये की कैपिटल से इसे शुरू किया था और आज के हालात कैसे हैं? During the current fiscal, an amount of ₹2,610 crore has been paid by LIC to the Government as dividend. यह इतना मजबूत संगठन, संस्था है। Sir, on a single day, that is, on 30th January, 2020, LIC has mopped around ₹1,816 crore as new business premium. And it is ironical that without inviting suggestions from the policyholders and the employees' organisation, the Government has decided to kill this golden goose. सोने की चिड़िया अंडा दे रही थी, उसको सरकार मार रही है। किसके लिए, जबाव दे? महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में गांधी जी के बारे में कुछ रेफरेन्स लाए गए, बहुत सारे अच्छे रेफरेन्स लाए गए। पैराग्राफ 35 में बोला गया, "In the environment prevailing in the aftermath of partition, the Father of the Nation, Mahatma Gandhi, had said that Hindus and Sikhs of Pakistan, who do not wish to live there, can come to India."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Please wait. Who is the Cabinet Minister here?

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): Sir, two are sitting here.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Okay.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, possibly, you do not know them. Anyway, Sir, I am addressing you. It is mentioned in the President's Address, "Mahatma Gandhi had said that Hindus and Sikhs of Pakistan, who do not wish to live there, can come to India. It is the duty of the Government of India to ensure a normal life for them. Many national leaders and political parties have from time to time supported this idea of Pujya Bapu." सुनने में बहुत अच्छा लगा पूज्य बापू, कितने पूज्य हैं, यह सत्ताधारी दल के सांसद बोल रहे हैं कि गांधी जी ने आजादी के समय जो लड़ाई लड़ी थी, वह नाटक था। ...**(व्यवधान)**... और राष्ट्रपति जी पूज्य बापू जी बोल रहे हैं, हम किसकी बात समझें?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Which para are you speaking from?

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, it is paragraph 35. This quote of Gandhiji has also been distorted. इसमें कोई reference नहीं दिया गया है कि गाँधी जी ने यह कब कहा, कहाँ कहा, किस दिन कहा, इसके संबंध में कुछ reference नहीं है, लेकिन मेरे पास है। मेरे पास 'Collected Works of Mahatma Gandhi' है, उससे पता चलता है कि 25 जुलाई, 1947 में प्रेयर मीटिंग में महात्मा गाँधी बोल रहे हैं, "There are Muslims, Parsis, Christians and other religious groups here. The assumption of the Hindus that India now has become the land of the Hindus is erroneous. India belongs to all who live here." हमारे संविधान का जो आर्टिकल 1 है, Article 1 also says that India, that is Bharat, shall be a Union of States. इसको भारत बोला गया, संविधान में कहीं भी हिन्दुस्तान की बात नहीं है। कोई भी संविधान खोल कर हिन्दुस्तानी या हिन्दू राष्ट्र दिखा दे। उसके बाद फिर 26 सितम्बर, 1947 को महात्मा गाँधी जी प्रेयर मीटिंग में बोल रहे हैं, जिसको यहाँ पैराग्राफ 35 में कुछ उल्टे ढंग से क्वोट किया गया और मेरे विचार से इसको हटाना चाहिए, क्योंकि यह misquote है। इसको हटाना चाहिए। 26 सितम्बर, 1947 में महात्मा गाँधी जी प्रेयर मीटिंग में जो बोल रहे हैं, उसको मैं यहाँ क्वोट कर रहा हूँ। "If we regard all the Muslims as fifth-columnists, will not the Hindus and the Sikhs in Pakistan be also considered fifth-columnists? That would not do. The Hindus and the Sikhs staying there can come here by all means if they do not wish to continue staying there. In that case, it is the first duty of the Indian Government to give them jobs and make their lives comfortable." अब कुछ दिन पहले मंत्री लोग भी बोले कि हिन्दुस्तान क्या धर्मशाला है? नहीं, धर्मशाला तो नहीं है, लेकिन गौशाला भी नहीं है। हिन्दुस्तान गौशाला भी नहीं है और अभी अचानक रुख बदल गया है और गाँधी जी को misquote करके बहुत कुछ दबाने के लिए, छिपाने के लिए इस तरह से बताया जा रहा है। लोग इस तरह से क्यों बोल रहे हैं?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Which document are you quoting from?

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: The Collected Works of Mahatma Gandhi.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Yes, you can proceed.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, it is 'The Collected Works of Mahatma Gandhi.' If you want, tomorrow, I would give you three volumes. I would submit three volumes.

सर, इस तरह से बातें क्यों कही जा रही हैं, क्यों छुपाई जा रही है? गाँधी जी अचानक पूज्य बापू हो गए। जो लोग समझते हैं कि गाँधी जी नाटक करते थे, उनके लिए अचानक बापू जी पूज्य हो गए, क्योंकि सीएए ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): I am sorry. I have asked because you are questioning the President's Speech.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: You are right, Sir. I admit. I bow down to you.

सर, सिटिज़न अमेंडमेंट एक्ट के पीछे सरकार का जो हिडन एजेंडा है, उस हिडन एजेंडा को छिपाने के लिए ये सारे cover up हो रहे हैं और वह भी गाँधी जी के नाम पर। यह हिडन एजेंडा क्या है? Religious persecution भी है और religious polarization भी है। इनका ये दो हिडन एजेंडाज़ हैं - एक, religious persecution और दूसरा, religious polirization. इस मकसद को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। इसको छुपाने के लिए गाँधी जी का सहारा लेकर उनकी बातों को distort किया गया, इसलिए मेरे विचार से पैराग्राफ 35 को हटाया जाए।

सर, सीएए के पास होने के बाद, जैसा कि हमारे नेता विरोधी दल, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बोला कि सारे देश में एक आंदोलन शुरू हो गया, कहीं-कहीं हंगामा भी हुआ, आगजनी हुई। जो आगजनी हुई, हंगामा हुआ, हम कड़े से कड़े शब्दों से उसकी निन्दा करते हैं। हमारे राज्य में भी थोड़ा-बहुत हुआ और उसके लिए हमने हजार से ज्यादा आदमियों को हिरासत में लिया और हमारी नेता, सुश्री ममता बनर्जी ने पैदल चलकर सारे बंगाल का परिभ्रमण किया। Mile after mile, day after day, night after night, she walked towards the entire West Bengal to preach to the people that whatever you want to do, please to in a peaceful and democratic manner. She has shown the path as to how to mobilize public opinion in a democratic manner. उन्होंने ऐलान न किया कि जब तक हमारे बदन में खून बहता है, तब तक हम बंगाल में सीएए, एनआरसी, एनपीआर लागू नहीं होने देंगे और सिर्फ बंगाल ही नहीं, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना वगैरह बहुत सारे राज्यों ने ऐसा रुख अपनाया, अधिवेशन में ऐसा प्रस्ताव पास किया और मुख्यमंत्रियों ने भी ऐलान किया कि हमारे राज्य में हम सीएए या एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। उनके जो साथी लोग हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते, बिहार के आदरणीय चीफ मिनिस्टर, ओडिशा के आदरणीय चीफ मिनिस्टर, हमने अखबार में देखा है, सच है या झूठ है, यह मुझे नहीं मालूम, अगर सच है, तो ठीक है। हम उनको सलाम करते हैं कि वे लोग भी बोले, सत्ताधारी पार्टनर होते हुए भी उन्होंने बोला कि हमारे राज्य में हम यह सब एनआरसी का हंगामा नहीं चाहते, तो यह परिस्थिति है। इसको खासकर हमारा जो युवा है, जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, सिर्फ जामिया में नहीं, सिर्फ अलीगढ़ में नहीं, सिर्फ जेएनयू में नहीं, सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी में नहीं, बल्कि सारे हिन्दुस्तान के कण-कण में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हर जगह विद्यार्थी सड़कों पर उतरे, उन्होंने मोर्चा खोले और सीएए के खिलाफ प्रतिवाद और प्रतिरोध की शपथ ली। क्या हम इन लाखों-करोड़ों जनता, युवा, छात्र सबको अस्वीकार करें? क्या ये हमारे देश के नागरिक नहीं हैं? हम इनकी बात सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्यों सुनना नहीं चाहते हैं? अगर आप people's Government हैं, अगर आप democratic Government हैं, तो आपको जनता की बात सुननी ही पड़ेगी। बताया

गया कि यह कानून नागरिकता छीनने के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि नागरिकता देने के लिए लाया गया है। यह बहुत अच्छी बात है। क्या हम 65 सालों से नागरिक नहीं थे, अब हमें नागरिकता दी जाएगी? क्योंकि सिटिजनशिप एक्ट 1955 में पास हुआ था, 65 साल बीत चुके हैं, तो हम 65 साल से नागरिक नहीं थे, वे लोग हमें अब नागरिकता देंगे? सत्ता में हैं, तो हमें नागरिकता देंगे। इसके लिए एनआरसी करना पड़ेगा, एनपीआर भी करना पड़ेगा। मेरे पिताजी ने कहाँ जन्म लिया था, कब जन्म लिया था, मेरी माता जी ने कहाँ जन्म लिया था, कब जन्म लिया था, सब बोलना पड़ेगा, सब तथ्य देना पड़ेगा, लेकिन क्यों देना पड़ेगा? हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास वोटर्स कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, बैंक की पासबुक है, insurance के कागजात हैं, फिर भी हमको प्रमाणित करना पड़ेगा कि हम हिन्दुस्तान के नागरिक हैं या नहीं। क्या किसी विदेशी को राशन कार्ड मिलता है, क्या किसी विदेशी को पासपोर्ट मिलता है, क्या हमारे यहाँ किसी विदेशी को आधार कार्ड या पैन कार्ड मिलता है, क्या वोटर्स कार्ड मिलता है, तो इस देश में यह क्या हो रहा है? यह सरकार, दशानन सरकार है। ये लोग दस मुँह से दस बातें कहते हैं। जब देखा कि स्थिति बहुत नाजुक है, हमारे युवा, हमारे विद्यार्थी लोग सड़क पर उतर गए हैं, सिर्फ कॉंग्रेस नहीं, सिर्फ टीएमसी नहीं, एसपी, बीएसपी, डीएमके वगैरह विरोधी दल नहीं, बल्कि आम जनता खफा हो गई है, तो दशानन सरकार के दस मुँह से दस बातें निकलने लगीं कि कन्फ्यूज़ कर दो। 10 तरह की बातें करने लगो, ताकि एक confusion create किया जाए। फिर क्या बोला गया? फिर बोला गया, एनआरसी? एनआरसी पर तो सरकार में कभी चर्चा ही नहीं हुई। क्या हम लोग कान से नहीं सुनते हैं? क्या हम लोग आँख से नहीं देख पाते हैं? इसी सदन में बताया गया कि अभी तो यह सीएए लागू हो रहा है, थोड़ा रुकिए, सारे हिन्दुस्तान में हम एनआरसी लागू करेंगे, चुन-चुनकर लाएँगे। देश की हर जगह पर आम सभाओं में सत्ताधारी दल के मंत्रियों और नेताओं ने हज़ारों बार, सैंकड़ों बार चिल्ला-चिल्लाकर बताया और अब ये बोल रहे हैं कि सरकार में इस पर चर्चा ही नहीं हुई! जब इस पर चर्चा ही नहीं हुई, तो फिर आपने क्यों बोला? आज सुबह, लोक सभा में एक सवाल के जवाब में आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि till now, there is no decision on NRC. Till now! आज नहीं तो कल होगा। इसका मतलब, आज नहीं है, लेकिन कल हो सकता है। यहाँ हमने सुना कि यह होगा ही और देखते रहना। हम मायके चले जाएँगे, तुम देखते रहना! इस तरह, सभी लोगों ने एक ही सुर लगाया। जब ऊपर से बोल दिया गया कि इस पर कभी चर्चा नहीं हुई, तो सब बोलने लगे कि चर्चा नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई। "मिले सुर मेरा तुम्हारा।" यह भैरवी राग है। जो राग सुबह गाया जाता है, उसे भैरवी कहते हैं, लेकिन अभी तो afternoon है, अभी हम भैरवी नहीं गा सकते। हम अभी वृन्दावनी सारंग गा सकते हैं, हम पटदीप या भीमपलासी जैसे afternoon के दूसरे राग गा सकते हैं। ये राग इनको मालूम है कि नहीं, यह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये तो सब जानते हैं। ये राग-रागिनी सब जानते हैं, इसलिए ये सब लोग मिलकर हम सबको राग-रागिनी सुनाने लगे कि हम लोग नादान हैं, कुछ नहीं समझते हैं, राग-रागिनी क्या होती है, यह हमको मालूम नहीं है। आपको राग-रागिनी सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम अभी सत्ता में हैं। इस तरह,

बहुत सारी राग-रागिनी सत्ताधारी नेताओं ने सुनायी। ठीक है। अभी भी यह सुनायी जा रही है, लेकिन हमारे पास वीडियो है। कौन क्या बोला, सबका वीडियो हमारे पास है, बहुत सारे लोगों के पास है। यहाँ तक कि बीजेपी के ट्विटर एकाउंट से जो ट्वीट इरेज़ किया गया था, वह भी मेरे पास है। अगर कोई सुनना चाहता है, आप लोगों में हिम्मत है और यदि कोई कहता है कि हाँ, उसे पेश करो, यहाँ सुनाओ, तो हम उसको सदन में सबको सुनाएँगे कि कौन क्या बोला। ...**(व्यवधान)**... मैनिफेस्टो तो है ही, वह कभी-कभी देखते हैं।

सर, इस लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने के लिए ये लोग धारा 144, अश्रु गैस, लाठी और गोली को अपनाए हुए हैं। अभी भूपेन्द्र जी नहीं हैं, वे सुबह संविधान को सुना रहे थे। संविधान में आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 21 है। हमारे माने हुए वकील, हमारी कानूनी बिरादरी के नेता, अभिषेक मनु सिंघवी जी अभी भी यहाँ बैठे हैं। वे इन सबको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। भूपेन्द्र जी ने कुछ प्रयास किए, लेकिन आर्टिकल 14, 19 और 21 की बात को उन्होंने एक बार भी नहीं उठाया, क्योंकि अगर उनको उठाया, तो मुश्किल है। खैर! धारा 144, अश्रु गैस, लाठी और गोली -- हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार एक केन्द्रीय मंत्री आम सभा में बोल रहा है, गोली मारो। ...**(व्यवधान)**... किसको गोली मारो? गोली मारो, गोली मारो। मंत्री बोल रहा है, गोली मारो और जनता वह बोल रही है, जो अभी ये बोल रहे थे। वह गाली मैं नहीं बक सकता, क्योंकि यह सदन है। मैं बाहर भी वह गाली नहीं बक सकता हूँ। आपने संविधान की शपथ ली कि हम हिन्दुस्तान के संविधान और कानून की रक्षा करेंगे, इसका हम पालन करेंगे। अभी तक यह मंत्री मंत्रिमंडल में कैसे हैं, यह सवाल मैं उठाना चाहता हूँ। जो सरकार संविधान को मान्यता नहीं देती है, उस सरकार को अगर हम असंवैधानिक बोलेंगे तो क्या यह भूल होगी? सबने शपथ ली, हमने भी शपथ ली। हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मंत्री आम सभा में इस तरह से बोले, पिछले 70-75 साल में इतनी सारी पार्टीज़ आयीं। यह चल रहा है कि गोली मारो, इसको गोली मारो, उसको गोली मारो। अब तो किसी राज्य का मुख्य मंत्री भी बोलने लगा है, मुख्य मंत्री भी बोलने लगा है कि गोली मारो। सरकार अब बेनकाब हो चुकी है। संविधान की जो आत्मा है। The soul of the Constitution is the Preamble. उस Preamble पर हर रोज़ कुठाराघात किया जा रहा है।

सर, बोलते हैं कि ये लोग आज़ादी का नारा लगा रहे हैं, ये लोग आज़ादी-आज़ादी के slogans दे रहे हैं। हाँ, वे slogans दे रहे हैं। वे क्यों दे रहे हैं, आज़ादी का मतलब क्या है? नेहरू जी ने जब कराची में राष्ट्रीय काँग्रेस के अधिवेशन में भाषण दिया, तब उन्होंने बोला What is meant by freedom? फ्रीडम का मतलब क्या है? Freedom from political bondage, freedom from economic slavery, freedom from cultural stagnation, मतलब, राजनीतिक बंधन से आज़ादी, आर्थिक दासता से आज़ादी और सांस्कृतिक गतिरोध से आज़ादी। अगर आज देश में ऐसा माहौल पैदा हो गया कि हम सांस्कृतिक गतिरोध में फंस गए हैं, आर्थिक दासता में फंस गए हैं या राजनीतिक बंधन, जो एजेंडा हमने बताया है, hidden agenda बताया है, उस राजनीतिक

hidden एजेंडा में हम फंस गए हैं, उससे मुक्त होने के लिए अगर हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यूथ, हमारे मज़दूर, अगर वे सब आज़ादी चाहते हैं तो इसमें दोष क्या है? आप आज़ादी के स्लोगन का मतलब ही नहीं समझते हैं। आप इस देश का अंदर से विभाजन करना चाहते हैं, आपके टुकड़े-टुकड़े गैंग देश का विभाजन करने के लिए इसमें लगे हुए हैं। इसलिए लोकतंत्र का कंठ रुंध हो रहा है। सर, धर्म के नाम पर एक भयानक राजनीतिक राह पर ज़बरदस्ती सबको चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप इतना नेहरू जी-नेहरू जी बोलते हैं। मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बहुत सारे नेताओं के नाम देखे, मैं उन सब पर श्रद्धा करता हूं, जिनके नाम हैं, उन सब पर श्रद्धा करता हूं। नेहरू जी का नाम नहीं है, जिन्होंने हमारे देश को करीब 20 साल से अधिक समय तक नेतृत्व दिया, देश को बनाया और नेहरू जी सलाखों के पीछे 3,262 दिन थे। आप किसी दूसरे नेता का नाम बताइए, जो 3,262 दिन तक सलाखों के पीछे रहा, भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ, सिर्फ उस समय without any break नेहरू जी, 1,040 दिन तक सलाखों के पीछे रहे। क्या उनका नाम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं रहेगा?...**(व्यवधान)**...

श्री विनय दीनू तेंदुलकर (गोवा): नाम लिया है।

श्री सुखेन्दु शेखर राय: वह हम जानते हैं कि कहां लिया और क्यों लिया। हम जानते हैं। जहां पर बहुत सारे नेताओं का नाम लिया गया, वहां नेहरू जी का नाम नहीं लिया गया। आप ठीक से देख लीजिए।...**(व्यवधान)**... ठीक है, जब आपका समय आएगा, तब आप बोलना। आपकी पार्टी के बारे में मैं क्या बताऊं? आपने खुद स्वयं का नाम और निशान 4 बार बदल दिया। पहले आप हिन्दू महासभा के नाम से आए, फिर जनसंघ के नाम से आए, फिर जनता पार्टी में विलय किया, फिर आप भाजपा के नाम से आए। न जाने आगे आप किस रूप में और किस चेहरे में सामने आएंगे। हमें नहीं मालूम है। आप खुद अपना नामो-निशान मिटा देते हैं। आज जो परिस्थिति तैयार हुई है, मुझे लगता है कि यह ताज भी नहीं रहेगा और यह तख्त भी नहीं रहेगा। सर, अपना-अपना विचार है। अभी मैं चर्चा करते-करते एक बात बोलना भूल गया। अभी चार मिनट टाइम बचा हुआ है और मैं चार मिनट में ही अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैंने कहा था कि यह सरकार विक्रेता सरकार है। यह रेलगाड़ी बेच रही है, स्टेशन बेच रही है, हवाई अड्डा बेच रही है, एयर इंडिया बेच रही है, भारत पेट्रोलियम बेच रही है, यह port trust की जमीन बेच रही है और अलग से 28 पीएसयूज को बेच रही है। इसकी मृतघोषणा हो गई है, लेकिन शमशान ले जाने के लिए अभी थोड़ा वक्त बाकी है। यह हंसी-मजाक की बात नहीं है, यह serious बात है। All these PSUs are the property of the people. The Government is only the custodian. The Government has no right to sell out people's property without discussion with the stakeholders *i.e.*, people. हमारे संविधान में We, the people of India. यह सरकार निर्णय ले रही है कि जब मन चाहे हम इसको बेच देंगे, उसको बेच देंगे। क्या यह उसकी जमींदारी है? इसको बेचने के लिए क्या आपको मेंडेट मिला था? आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। हमारी

5.00 P.M.

नई पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़कर जाएंगे? जो हिंदुस्तान की जनता है, उसने अपने खून और पसीने से इन संस्थाओं को तैयार किया था, जिनको एक-एक करके आप बेच रहे हैं। जहां अभी गुलाम नबी जी बैठते हैं, वे वहां बैठते थे, लेकिन वे गुजर गए हैं, मैं उनकी बहुत श्रद्धा करता हूं, सब करते हैं। बाकी सब लोग हर रोज़ यहां वेल में आते थे, एक session तो पूरा washout हो गया। उनकी मांग थी कि हम multibrand में एफ.डी.आई. नहीं आने देंगे। अगर टेक्नीकली पूछेंगे, तो अभी भी नहीं आया है, लेकिन Walmart ने Flipkart खरीदा और Flipkart खरीद कर वह पीछे के दरवाजे से multi brand retail का जो online business है, उसके ऊपर कब्जा कर रहा है और जब कब्जा हो जाएगा, तो जो हमारे लाखों-करोड़ों retailers हैं, वे बरबाद हो जाएंगे - जैसे कि अमरीका और यूरोप में हुआ है।

सर, अंत में जो 28 भगोड़े अपराधी हैं, मेरे पास नाम हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। यदि मैं नाम बताऊंगा तो कुछ लोग नाराज होंगे, क्योंकि वे पाकिस्तानी, मुसलमान, माओवादी या टुकड़े-टुकड़े गैंग के सदस्य नहीं हैं। वे एक विशेष राज्य के आदिवासी हैं। मैं नहीं बताना चाहूंगा। सर, आप जनता की आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिए। आप हर बात पर - पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, पाकिस्तान के दलाल, यह बोलना छोड़िए। कौन किसका दलाल है, वह तो सब समझ गए हैं, जनता समझ गई है। मैं मेरा भाषण समाप्त करना चाहता हूं। एक मिनट का समय बाकी है। एक शायर हैं, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ आजकल उनके बारे में आलोचना हो रही है। चर्चा नहीं, आलोचना हो रही है। He is being criticized. वे पाकिस्तानी थे, लेकिन पाकिस्तानी होते हुए भी वे चार साल पाकिस्तान की सलाखों के पीछे थे, क्योंकि वे Marxists थे, Progressive writer थे, आप जैसे Marxists थे। सर, उनके एक गीत की दो लाइन, हमारे समय की '1942 A Love Story' बहुत मशहूर फिल्म थी, जिसको बहुत सारे लोगों ने देखा भी और गाना भी सुना। आर.डी.बर्मन का आखिरी hit song उसमें था। जिसकी दो कलियां मैं सुनाना चाहता हूं, हालांकि मैं गायक नहीं हूं -

"यह सफर बहुत है कठिन, मगर न उदास हो मेरे हमसफर।
दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है।
लम्बी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है।"

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Now, Shri A. Navaneethakrishnan. There are two speakers from your party and you have 32 minutes. So, try to finish in sixteen minutes. I know you are a very good speaker.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): No; no, Sir. We will be giving one more name. I will restrict myself to five to six minutes..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Whatever name you give, that will go to the hon. Chairman for approval.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to thank His Excellency, the President of India, for his Address which he has been pleased to deliver to both the Houses of Parliament, assembled together in the Central Hall on January 31st, 2020.

I also thank the Central Government and His Excellency the President for quoting Thiruvalluvar. The Thirukural quoted very clearly shows that the Central Government is committed to protect the agricultural as well as the farming community. So, by quoting the Thirukkural, the hon. President and the Government have indicated that the agricultural and farming community will be protected at any cost.

*(*MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair)*

Of course, there is an error in transliteration. That is why I was a bit confused and was not able to identify the exact Thirukkural. Of course, my senior colleague, Shri A.K. Selvaraj, helped me in finding out the exact Thirukkural, quoted by the hon. President. It is very special in Tamil language. It is not available in any other language. Therefore, I may be permitted to read and quote the Thirukkural. I quote, *"Urruvar Ulgattaark Aaniya tattraad, Erru-vaare Ellaam Porutt"*.

Sir, this is the Thirukkural, which was quoted by the hon. President. But, in the transliteration, there is an error. But, of course, the meaning was rightly conveyed by the hon. President in his Address. I quote the meaning, "Like a linchpin of an axle, a farmer holds together the entire world. He bears the burden of those people who cannot cultivate land." So, on behalf of the people of entire world, those who are not cultivated, the farmer is holding the entire world. So, such a beautiful Thirukkural has been quoted by the hon. President. And, thereby, the Central Government has made it very clear its policy to protect the agricultural and the farming community. There is no doubt about it.

Also, at the outset, I would like to thank the Central Government as well as the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi for sanctioning eleven medical colleges for the State of Tamil Nadu in a single calendar year, namely, in 2019. I think, now, each and every district of Tamil Nadu is going to have a medical college. So, obviously, the

students of Tamil Nadu will be benefitted by this. Of course, I would later on be coming to the NEET also. But, I thank the Central Government for sanctioning eleven medical colleges.

Now, the Government of Tamil Nadu, Amma's Government, headed by Shri Edappadi K. Palaniswami, has been ranked by the Central Government as number one in Good Governance Index. That ranking is on the basis of the real time data. So, there is not any favouritism or anything else; it is a verifiable data. On the basis of that, the Central Government has ranked as number one the Government headed by Thiru Edappadi K. Palanisami, Amma's Government. I am very happy and thank the Central Government for that. But, at the same time, I would like to urge the Central Government to resolve the Cauvery Delta problem. There is a proposal for extraction of hydrocarbon by private companies as well as by the ONGC. The recent notification issued by the Central Government states that prior environmental clearance and public hearings are not at all required. The matter had been sent to the Central Government. The Central Government was very much concerned about it. They agreed to consider the grievance of the people of Tamil Nadu. I am raising this issue because according to the people of Tamil Nadu, the entire Cauvery Delta will be destroyed if that project is allowed to go on. Also, a few safeguards which are available in the form of prior environmental clearance as well as the public hearing have now been dispensed with. The Central Government has been kind enough to give a hearing to the State Government. They are going to give the hearing, and, definitely, they would resolve the issue. I thank the Central Government.

Further, regarding the NEET, I would say that though they have given 11 medical colleges—~~t~~there is no doubt about it ~~in~~ a single calendar year, at the same time, I would like to point out that NEET is used only by the rich students. Earlier, in Tamil Nadu, when there was no NEET, students from the poor strata of the society got the benefit of reservation. Of course, we are following the reservation. But now, with the introduction of reservation in NEET, only the rich students are able to get the seats. To get the NEET training, a candidate has to spend a minimum of five lakhs. So, this aspect also has to be taken note of by the Central Government. Already, two Bills have been passed by the Tamil Nadu Legislative Assembly unanimously. So, if a Bill is passed by the Legislative Assembly unanimously, then, the concept of cooperative federalism requires that it is given due weightage by the Central Government. The Bills are pending with the Central Government. So, I urge the Central Government very

humbly that NEET need not be imposed on the students of Tamil Nadu. During those days, in Amma's period, at least from five villages, one student from the village of that locality used to join a medical college. That is not happening now. So, the ground reality must be taken note of by the Central Government. Further, I must thank the Central Government again, subject to correction, on 96 Heads, the Tamil Nadu Government has been ranked as number one. As and when, then and there, the Central Government is giving the awards to the Tamil Nadu Government headed by Thiru Edappadi K. Palanisami. It shows our good governance. All the credit goes to our political party AIADMK and the Ministry headed by Edappadi K. Palanisami, and, ultimately to hon. Amma, whether it is law and order, agriculture, handlooms or any other thing like providing medical service to the rural mass, in all Heads, our State Government has been ranked as number one. So, now, we are having good practices in place. Even the other day, I pointed out that our growth rate, GDP, is 8.6 per cent. So, we are number one in all. Why I am telling all this before this august House is because in Tamil Nadu, we are following good practices and good practices are in place. The Central Government is also supporting the Tamil Nadu Government wherever it is required except in case of NEET. Though exemption was given for one year, subsequently, that exemption was not extended to.

So my humble submission would be, I wholeheartedly welcome the speech delivered by His Excellency, the President, and we also support the Central Government. At the same time, I humbly urge the Central Government to look into our genuine grievances. I further urge the Central Government to do agriculture which is chemical free. I again say, subject to correction, an amount of ₹ 75,000 crores is given as fertilizer subsidy. That may be utilized for strengthening the organic or natural farming. So, the Government must find out ways and means to support the natural and organic chemical-free farming.

I thank the Government, I thank hon. Amma, I thank our hon. Chief Minister for giving me this opportunity. Thank you, Sir.

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जैसा हम सब लोग जानते ही हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी जो अभिभाषण करते हैं, वह सरकार के किए गए कामों का रिपोर्ट कार्ड होता है और आने वाले दिनों में सरकार किस रास्ते पर चलेगी, उसका उसमें जिक्र होता है। हमारी पार्टी के नेता प्रो. राम गोपाल यादव जी को इस विषय पर बोलना था,

लेकिन वे कल अपनी बात रखेंगे, इसलिए मैं आज आपको समय के लिए ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, मैं अपने आप ही सीमित समय में रहूंगा।

†**جناب جاوید علی خان(اتّر پردیش)** : مانّنے اپ سبھا پتی جی، آپ نے مجھے مہا مہم راشٹرپتی جی کے ابھیبھاشن پر بولنے کا موقع دیا، اس کے لئے آپ کا دھنیواد. جیسا ہم سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ مہامہم راشٹرپتی جی جو ابھیبھاشن کرتے ہیں، وہ سرکار کے کئے گئے کاموں کا رپورٹ کارڈ ہوتا ہے اور آنے والے دنوں میں سرکار کس راستے پر چلے گی، اس کا اس میں ذکر ہوتا ہے۔ ہماری پارٹی کے نیتا پروفیسر رام گوپال یادو جی کو اس موضوع پر بولنا تھا، لیکن وہ کل اپنی بات رکھیں گے، اس لئے میں آپ کو وقت کے لئے زیادہ پریشان نہیں کروں گا، میں اپنے آپ ہی مقررہ وقت میں رہوں گا۔

श्री उपसभापति: आपने खुद ही समय दिया है। आप हमेशा समय सीमा में रहते हैं।

श्री जावेद अली खान: माननीय उपसभापति जी, यह जो हमारी सरकार है, यह जो लिखत-पढ़त में कहती है और इसके नेता, मंत्री यहां तक कि प्रधान मंत्री जी, सार्वजनिक मंचों पर जो कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है, कई अवसरों पर ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं। आज हमारे देश के अंदर जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जो मुद्दा है, वह CAA और NRC का मुद्दा है। मेरे ही प्रश्न के जवाब में और इत्तिफ़ाक़ से आप ही चेयर पर बैठे हुए थे, मैंने एक प्रश्न पूछा, वह पूरक प्रश्न था, गृह मंत्रालय का सवाल-जवाब चल रहा था। मैंने पूछा कि क्या असम से बाहर कहीं NRC लागू करने का सरकार का कोई विचार है, तो उस वक्त गृह राज्य मंत्री सब प्रश्नों के जवाब दे रहे थे और जो मुख्य प्रश्न था, उसका भी जवाब गृह राज्य मंत्री जी दे रहे थे, लेकिन हमारे केबिनेट मंत्री, भारत के गृह मंत्री यहां सदन में मौजूद थे, उन्होंने हाथ से उन्हें रोका और इस सवाल पर कि NRC देश के अंदर लागू करने का विचार है या नहीं है? उन्होंने खुद खड़े होकर, बड़ी ताल ठोककर कहा कि इंच-इंच जमीन पर NRC लागू होगा और घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। जब कुछ दिनों के बाद चर्चा ज्यादा हुई, तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा, NRC का कोई जिक्र ही नहीं है, कई वक्ताओं ने भी इस मामले का जिक्र किया।

माननीय उपसभापति जी, आप मेरी शंका का समाधान कीजिए कि इस सदन के पटल पर बोली गई बात को ज्यादा महत्व देना चाहिए या रामलीला मैदान के मंच पर बोली जाने वाली बात को ज्यादा महत्व देना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर आप मेरी शंका का समाधान करेंगे, तो निश्चित रूप से यह कहेंगे कि जो बात सदन में कही जाती है, उसका ज्यादा महत्व होता है, बाहर के मंचों पर कही जाने वाली बात को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।

सर, क्या स्थिति हो गई है? एक आंदोलन पूरे देश के अंदर चल रहा है। उस आंदोलन के विरोध में सभी वर्गों के, सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग हैं, किसी के कम हैं, किसी के

†Transliteration in Urdu script.

ज्यादा हैं। महोदय, लेकिन उस आन्दोलन को एक खास धर्म के मानने वालों का आन्दोलन और उसमें भी सिर्फ एक खास लिंग के लोगों का आन्दोलन, यानी महिलाओं का आन्दोलन बताकर पेश किया जा रहा है।

महोदय, हमारा संवैधानिक अधिकार है। देश के नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है कि हम किसी भी फैसले का, चाहे कोई भी ले, किसी भी स्तर पर हो, हम उससे अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। उसके खिलाफ अपने पक्ष में लोगों को मोबिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आज कुछ पार्टियों का लैवल उस आन्दोलन पर जबर्दस्ती लगाया जा रहा है।

महोदय, मैं अपने भाषण में इस आन्दोलन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि इस देश के अंदर यह जो आन्दोलन शुरू हुआ है, एक ऐसी संस्था से हुआ है, जामिया मिलिया इस्लामिया, जहां का मैं बरसों तक विद्यार्थी रहा हूं। जब वहां यह आन्दोलन शुरू हुआ और जब वहां के छात्रों के ऊपर, पुलिस ने जो बर्बरता की, हमारे ही साथियों ने कुछ ऐसी-ऐसी बातें कह दीं, जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थीं। एक सदस्य ने तो यहां तक कह दिया कि यह आतंकवादियों का अड्डा है। ऐसे विश्वविद्यालयों पर ताला ठोक देना चाहिए। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि जो लोग जामिया मिलिया इस्लामिया के इतिहास को नहीं जानते, जिन लोगों ने कभी उससे वास्ता नहीं रखा या आज़ादी के आन्दोलन को थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा है, वही लोग ऐसी बात कर सकते हैं।

महोदय, महात्मा गांधी जी के आह्वान पर वर्ष 1920 में, जब सरकारी सहायता से चलने वाले विश्वविद्यालयों का बहिष्कार करके देशी शिक्षा संस्थाएं बनाने का आह्वान किया गया था, उस समय जामिया मिलिया इस्लामिया वजूद में आई थी। अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी से अलग हुए थे और जामिया मिलिया इस्लामिया, उन स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने बनाई थी, जो आज़ादी के आन्दोलन में पेश-पेश थे। इसलिए जामिया के लोग आज़ादी के महत्व को भी जानते हैं, जामिया के लोग आन्दोलन के महत्व को भी जानते हैं, जामिया के लोग अंग्रेजों से भी लड़ना जानते हैं और जामिया के लोग देशी अंग्रेजों से भी लड़ना जानते हैं, यह बात मैं कहना चाहता हूं।

महोदय, आज जिस तरीके से इस विषय को उठाया गया है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार CAA के माध्यम से करना क्या चाहती है? CAA के माध्यम से ऐसा बताया जा रहा है, जैसे इतना बड़ा काम कर दिया गया हो कि किसी को भारत की नागरिकता मिलती ही नहीं थी और उन्हें नागरिकता देना शुरू कर दिया गया हो, लेकिन यह स्थिति नहीं है। सिर्फ एक काम इन्होंने किया है, जिसे हम कुछ परिस्थितियों में सही भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश के अंदर, जो धार्मिक अल्पसंख्यक वहां की सरकार की नीतियों से या वहां के समाज द्वारा प्रताड़ित थे, उन्हें यह नागरिकता, जो पहले 11 साल में मिलती थी, अब उसे मात्र पांच साल में देंगे। उसकी अवधि घटाकर 11 साल से पांच साल की है। इन्होंने यह एक काम किया है, जिसे हम सही भी कह सकते हैं, लेकिन सही काम करने के लिए, हम हिन्दुओं को देंगे, हम सिखों को देंगे, हम बौद्धों को देंगे, हम जैनों को देंगे, हम पारसियों को देंगे और

हम ईसाइयों को देंगे, यह कहने की कौन सी जरूरत थी? जब इस बिल पर सदन में बहस हुई थी, उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को आप नागरिकता की 11 साल की शर्त को पांच साल करने की बात करते हैं, तो वह बात क्लासिफिकेशन के दायरे में भी आती है, वह रीज़नेबल भी हो जाती है और हमारे संविधान के अनुरूप भी हो जाती है। मगर इन्हें तो मज़ा इसी में आता है कि भारतीय समाज को हिन्दू-मुस्लिम के नाम पर मथा जाता रहे और उस मंथन में से ये सत्ता का अमृत निकालना चाहते हैं, इसलिए ये हिन्दू-मुस्लिम का सवाल लाए हैं।

महोदय, आज मुझे गांधी जी की बहुत याद आ रही है। मैं तो घबरा गया था कि सारे कोटेशन्स गांधी जी के, जो उनके प्रार्थना प्रवचनों में दिए गए हैं, जब हमारे श्री सुखेन्दु शेखर राय बोल रहे थे, तो एक के बाद एक वे गांधी जी को क्वोट करते जा रहे थे। मैं भी कुछ लाया हूं।

ज्यादातर वही थे, लेकिन एक बच गया, मैं उसे पढ़ना चाहता हूं कि गाँधी जी ने क्या कहा था? यह प्रार्थना प्रवचन 10 जुलाई, 1947 का है। धार्मिक अल्पसंख्यक, जो पाकिस्तान में उस वक्त तक होने वाले थे, यानी हम उन्हें हिंदू सिख भी कह सकते हैं, उन लोगों के बारे में गाँधी जी क्या कहते हैं? उन लोगों के बारे में गाँधी जी ने कहा था, "परंतु यदि सिंध या और जगहों से लोग डर के मारे अपने घर-बार छोड़कर यहाँ आ जाते हैं, तो क्या हम उनको भगा दें? यदि हम ऐसा करें, तो अपने को हिंदुस्तानी किस मुँह से कहेंगे? हम कैसे जय हिंद का नारा लगाएंगे? नेता जी किसके लिए लड़े थे? हम सब हिंदुस्तानी हैं। चाहे दिल्ली का हो या गुजरात का, वे लोग हमारे मेहमान बनकर रहें। हम यह कहते हुए उनका स्वागत करें कि आइए, यह भी आपका मुल्क है और वह भी आपका मुल्क है। गाँधी जी का यह प्रवचन, गाँधी जी का यह वाक्य सीएए का मुख्य आधार बताया गया है। लेकिन जब मैं इसी पैराग्राफ का अगला वाक्य पढ़ता हूं, तो वे क्या कहते हैं, उनका कितना बड़ा नज़रिया था? "इस तरह से उन्हें रखना चाहिए। और यदि राष्ट्रीय मुसलमानों को भी पाकिस्तान छोड़कर आना पड़ा, तो वे भी यहीं रहेंगे। हम हिंदुस्तानी की हैसियत से सब एक ही हैं। यदि यह नहीं बन सकता, तो हिंदुस्तान नहीं बन सकता।" गाँधी जी का उन हिंदुओं के बारे में, उन मुसलमानों के बारे में यह दृष्टिकोण था, जो उस वक्त पाकिस्तान में रहते थे। लेकिन आज यह मांग नहीं है। पूरे आंदोलन की यह मांग नहीं है कि पाकिस्तान के मुसलमानों को यहाँ नागरिकता दीजिए या बंगलादेश और अफगानिस्तान के मुसलमानों को यहाँ नागरिकता दीजिए। आज की मांग सिर्फ यह है - क्योंकि आपका यह संशोधन नागरिकता कानून में संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, यह हिंदू-मुस्लिम करता है, यह अपने नागरिकों को या देश में जो लोग रह रहे हैं, उन नागरिकों के बीच में धर्म के आधार पर भेद करता है, तो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में, धर्म निरपेक्ष देश में धर्म के नाम पर भेद करना ...(**समय की घंटी**)... संविधान की भावना नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कल हमारे प्रो. राम गोपाल यादव जी इस विषय पर बोलेंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

†**جناب جاوید علی خان :** مانّئے اپ سبھا پتی جی، یہ جو ہماری سرکار ہے، یہ جو لکھت-پڑت میں کہتی ہے اور اس کے نیتا، منتری یہاں تک کہ پردھان منتری جی، عوامی منچوں پر جو کہتے ہیں، اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، کئی موقعوں پر ایسی مثالیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ آج ہمارے دیش کے اندر جو سب سے زیادہ چرچا کا موضوع بنا ہوا ہے، جو مدّعا ہے، وہ سی۔اے۔اے۔ اور این۔آر۔سی۔ کا مدّعا ہے۔ میرے ہی سوال کے جواب میں، اور اتّفاق سے آپ ہی چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ایک سوال پوچھا، وہ پورک پرشن تھا، گرہ منترالیہ کا سوال-جواب چل رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا آسام سے باہر کہیں این۔آر۔سی۔ لاگو کرنے کا سرکار کو کوئی وچار ہے، تو اس وقت گرہ راجیہ منتری سب سوالوں کے جواب دے رہے تھے اور جو مکھیہ پرشن تھا، اس کا بھی جواب گرہ راجیہ منتری جی دے رہے تھے، لیکن ہمارے کیبنیٹ منتری، بھارت کے گرہ منتری یہاں سدن میں موجود تھے، انہوں نے ہاتھ سے انہیں روکا اور اس سوال پر کہ این۔آر۔سی۔ دیش کے اندر لاگو کرنے کا وچار ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے خود کھڑے ہو کر، بڑی تال ٹھوک کر کہا کہ انچ انچ زمین پر این۔آر۔سی۔ لاگو ہوگا اور گھس پیٹھیوں کو باہر کیا جائے گا۔ جب کچھ دنوں کے بعد چرچا زیادہ ہوئی، تو مانّئے پردھان منتری جی نے کہا، این۔آر۔سی۔ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کئی وکتاؤں نے بھی اس معاملے کا ذکر کیا۔

مانّئے اپ سبھا پتی جی، آپ میری شنکا کا سمادھان کیجئے کہ اس سدن کے پٹل پر بولی گئی بات کو زیادہ اہمیت دینی چاہئے یا رام لیلا میدان کے منچ پر بولی جانے والی بات کو زیادہ اہمیت دینی چاہئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میری شنکا کا سمادھان کریں گے، تو نشچت روپ سے یہ کہیں گے کہ جو بات سدن میں کہی جاتی ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، باہر کے منچوں پر کہی جانے والی بات کو اتنی گمبھیرتا سے نہیں لینا چاہئے۔

سر، کیا حالت ہو گئی ہے؟ ایک آندولن پورے دیش کے اندر چل رہا ہے۔ ان آندولن کے ورودھ میں سبھی ورگوں کے، سبھی دھرموں کے، سبھی جاتیوں کے لوگ ہیں، کسی کے کم ہیں، کسی کے زیادہ ہیں۔

مہودے، لیکن اس آندولن کو ایک خاص دھرم کے ماننے والوں کا آندولن اور اس میں بھی صرف ایک خاص لنگ کے لوگوں کا آندولن، یعنی مہیلاؤں کا آندولن بتا کر پیش کیا جا رہا ہے۔

مہودے، ہمارا سنودھانک ادھیکار ہے۔ دیش کے ناگرکوں کا سنودھانک ادھیکار ہے کہ ہم کسی بھی فیصلے کا، چاہئے کوئی بھی لے، کسی بھی استر پر ہو، ہم اس سے اپنی غیر رضا مندی ظاہر کرسکتے ہیں۔ اس کے خلاف اپنے پکش میں لوگوں کو موبلائزیشن کر سکتے ہیں، لیکن آج کچھ پارٹیوں کا لیول اس آندولن پر زبردستی لگا جا رہا ہے۔

---

†Transliteration in Urdu script.

مہودے، میں اپنے بھاشن میں اس آندولن کا ذکر اس لئے کر رہا ہوں، کیوں کہ اس دیش کے اندر یہ جو آندولن شروع ہوا ہے، ایک ایسی سنستھا سے ہوا ہے، جامعہ ملّیہ اسلامیہ، جہاں کا میں برسوں تک ودھیارتی رہا ہوں۔ جب وہاں یہ آندولن شروع ہوا اور جب وہاں کے چھاتروں کے اوپر، پولیس نے جو بربرتا کی، ہمارے ہی ساتھیوں نے کچھ ایسی ایسی باتیں کہہ دیں، جو انہیں نہیں کہنی چاہئے تھیں۔ ایک سدسئے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ آتنک واد کا اڈّہ ہے۔ ایسے وشوودھیالیوں پر تالا ٹھوک دینا چاہئے۔ میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جامعہ ملّیہ اسلامیہ کی تاریخ کو نہیں جانتے، جن لوگوں نے کبھی اس سے واسطہ نہیں رکھا یا آزادی کے آندولن کو تھوڑا بہت بھی نہیں پڑھا ہے، وہی لوگ ایسی بات کر سکتے ہیں۔

مہودے، مہاتما گاندھی جی کے آہوان پر سال 1920 میں، جب سرکاری مدد سے چلنے والے وشوودھیالیوں کا بہشکار کرکے دیشی شکشا سنتھائیں بنانے کا آہوان کیا گیا تھا، اس وقت جامعہ ملّیہ اسلامیہ وجود میں آئی تھی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے الگ ہوئے تھے اور جامعہ ملّیہ اسلامیہ، اس سوادھینتا سنگرام کے سینانیوں نے بنائی تھی، جو آزادی کے آندولن میں پیش پیش تھے۔ اس لئے جامعہ کے لوگ آزادی کی اہمیت کو بھی جانتے ہیں، جامعہ کے لوگ آندولن کی اہمیت کو بھی جانتے ہیں، جامعہ کے لوگ انگریزوں سے بھی لڑنا جانتے ہیں اور جامعہ کے لوگ دیشی انگریزوں سے بھی لڑنا جانتے ہیں، یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں۔

مہودے، آج جس طریقے سے اس وشئے کو اٹھایا گیا ہے، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سرکار سی۔اے۔اے۔ کے مادھیم سے کرنا کیا چاہتی ہے؟ سی۔اے۔اے۔ کے مادھیم سے ایسا بتایا جا رہا ہے، جیسے اتنا بڑا کام کر دیا گیا ہو کہ کسی کو بھارت کی ناگرکتا ملتی ہی نہیں تھی اور انہیں ناگرکتا دینا شروع کر دیا گیا ہو، لیکن یہ حالت نہیں ہے۔ صرف ایک کام انہوں نے کیا ہے، جسے ہم کچھ حالتوں میں صحیح بھی کہہ سکتے ہیں

کہ پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کے اندر، جو دھارمک الپ سنخیک وہاں کی سرکار کی نیتیوں سے یا وہاں کے سماج کے ذریعے پرتاڑت تھے، انہیں یہ ناگرکتا، جو پہلے گیارہ سال میں ملتی تھی، اب اسے صرف پانچ سال میں دیں گے۔ اس کی مدت گھٹاکر گیارہ سال سے پانچ سال کی ہے۔ انہوں نے یہ ایک کام کیا ہے، جسے ہم صحیح بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن صحیح کام کرنے کے لئے، ہم ہندوؤں کو دیں گے، ہم سکھوں کو دیں گے، ہم بودھوں کو دیں گے، ہم جینیوں کو دیں گے، ہم پارسیوں کو دیں گے اور ہم عیسائیوں کو دیں گے، یہ کہنے کی کون سی ضرورت تھی؟ جب اس بل پر سدن میں بحث ہوئی تھا، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کے دھارمک الپ-سنخیکوں کو آپ ناگرکتا کی گیارہ سال کی شرط کو پانچ سال کرنے کی بات کرتے ہیں، تو وہ بات کلاسیفکیشن کے دائرے میں بھی آتی ہے، وہ ریزنیبل بھی ہو جاتی ہے اور ہمارے سنودھان کے انوروپ بھی ہو جاتی ہے۔ مگر انہیں تو مزا اسی میں آتا ہے کہ بھارتی سماج میں ہندو-مسلم کے نام پر متھا جاتا رہے اور اس منتھن میں سے یہ ستّہ کا امرت نکالنا چاہتے ہیں، اس لئے یہ ہندو-مسلم کا سوال لائے ہیں۔

مہودے، آج مجھے گاندھی جی کی بہت یاد آرہی ہے۔ میں تو گھبرا گیا تھا کہ سارے کوٹیشنس گاندھی جی کے، جو ان کے پرارتھنا پروچنوں میں دئے گئے ہیں، جب ہمارے شری سکھیندو شیکھر رائے بول رہے تھے، تو ایک کے بعد ایک وہ گاندھی جی کو کیوٹ کرتے جا رہے تھے۔ میں بھی کچھ لایا ہوں۔

زیادہ تر وہی تھے، لیکن ایک بچ گیا، میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں کہ گاندھی جی نے کیا کہا تھا؟ یہ پرارتھنا پروچن 10 جولائی، 1947 کا ہے۔ دھارمک الپ سنخیکوں، جو پاکستان میں اس وقت تک ہونے والے تھے، یعنی ہم انہیں ہندو سکھ بھی کہہ سکتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں گاندھی جی کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں گاندھی جی

نے کہا تھا، "پرنتو یدی مسلمان یا اور جگہوں سے لوگ ڈر کے مارے اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں آ جاتے ہیں، تو کیا ہم ان کو بھگا دیں؟ یدی ہم ایسا کریں، تو اپنے کو ہندوستانی کس منھ سے کہیں گے؟ ہم کیسے جے ہند کا نعرہ لگائیں گے؟ نیتا جی کس کے لئے لڑے تھے؟ ہم سب ہندوستانی ہیں۔ چاہے دہلی کا ہو یا گجرات کا، وہ لوگ ہمارے مہمان بن کر رہیں۔ ہم یہ کہتے ہوئے ان کا سواگت کریں کہ آئیے، یہ بھی آپ کا ملک ہے اور وہ بھی آپ کا ملک ہے۔ گاندھی جی کا یہ پروچن، گاندھی جی کا یہ واکئے سی۔اے۔اے۔ کا مکھیہ آدھار بتایا گیا ہے۔ لیکن جب میں اسی پیراگراف کا اگلا واکئہ پڑھتا ہوں، تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کتنا بڑا نظریہ تھا؟ "اس طرح سے انہیں رکھنا چاہئے۔ اور یدی راشٹریہ مسلمانوں کو بھی پاکستان چھوڑ کر آنا پڑے، تو وہ بھی یہیں رہیں گے۔ ہم ہندوستانی کی حیثیت سے سب ایک ہی ہیں۔ یدی یہ نہیں بن سکتا، تو ہندوستان نہیں بن سکتا"۔ گاندھی جی کا ان ہندوؤں کے بارے میں، ان مسلمانوں کے بارے میں یہ درشٹی-کون تھا، جو اس وقت پاکستان میں رہتے تھے۔ لیکن آج یہ مانگ نہیں ہے۔ پورے آندولن کی یہ مانگ نہیں ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کو یہاں ناگرکتا دیجئے یا بنگلہ دیش اور افغانستان کے مسلمانوں کو یہاں ناگرکتا دیجئے۔ آج کی مانگ صرف یہ ہے – کیوں کہ آپ کا یہ سنشودھن ناگرکتا قانون میں سنودھان کی مول بھاونا کے خلاف ہے، یہ ہندو-مسلم کرتا ہے، یہ اپنے ناگرکوں کو یا دیش میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ان ناگرکوں کے بیچ میں دھرم کے آدھار پر بھید کرتا ہے، تو دھرم نرپیکش راشٹر میں، دھرم نرپیکش دیش میں دھرم کے نام پر بھید کرنا ...(وقت کی گھنٹی)... سنودھان کی بھاونا نہیں ہے، اس لئے ہم اس کا ورودھ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ کل ہمارے پروفیسر رام

گوپال یادو جی اس وشئے پر بولیں گے۔ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا ہے، اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد۔

SHRI PRASANNA ACHARYA (Odisha): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. I will limit my speech so that another Member of my Party can speak, if not today, tomorrow.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time has already been allocated. Fifteen minutes for you and five minutes for Dr. Amar Patnaik. ...*(Interruptions)*...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: उपसभापति महोदय, एक बहुत ही गंभीर बात सुखेन्दु दा ने कही है। क्योंकि जिस समय वे अपना भाषण दे रहे थे, उस समय मेरे पास राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की पुस्तक नहीं थी। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नेहरू जी का कहीं जिक्र नहीं है। मैं केवल रिकॉर्ड को करेक्ट करने के लिए आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने कहा है कि चाहे पूज्य बापू जी का ग्राम स्वराज का सपना हो, बाबा साहेब अंबेडकर जी की सामाजिक न्याय की नीति हो, नेहरू जी का आधुनिक भारत बनाने का स्वप्न हो, सरदार पटेल का एक भारत, श्रेष्ठ भारत का संकल्प हो, दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का लक्ष्य हो, डा. लोहिया का समतामूलक समाज का दर्शन हो, हम भारत के लोग मिलकर इन सपनों को पूरा करेंगे। यानी कि उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आप उसको रिकॉर्ड पर देख लें और expunge करें। एक बात को बार-बार दोहराया गया है कि यह सरकार दशानन सरकार है, दस मुँह की सरकार है। आप हिंदी अच्छी तरह समझते हैं और ऐसा भी नहीं है कि सुखेन्दु दा अच्छी तरह से नहीं समझते हों कि उनके कहने का क्या अर्थ है? मेरा अनुरोध है कि इसको expunge किया जाए।

तीसरा, जो प्वाइंट है, वह यह है कि सुखेन्दु दा ने बार-बार एक बात कही है कि यह सरकार बिकाऊ सरकार है। हो सकता है कि वे टिकाऊ सरकार कहना चाहते हों, लेकिन बार-बार बिकाऊ सरकार बोल गए हों। मैं कहना चाहता हूं कि यह बिकाऊ सरकार शब्द अनपार्लियामेंटरी है, इसलिए उसे भी expunge किया जाए।

श्री उपसभापति: हम ये दोनों चीजें examine करवाएंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे। प्रसन्न आचार्य जी, आप बोलिए।

श्री सुखेन्दु शेखर राय: उपसभापति जी, आप consult कीजिए कि बिकाऊ शब्द अनापार्लियामेंटरी है या नहीं?

---

†Transliteration in Urdu script.

दूसरी बात जो इन्होंने अनपार्लियामेंटरी बोली है और expunge करने के लिए बोला है....आपने क्या बोला है?

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: दशानन।

श्री सुखेन्दु शेखर राय: उपसभापति जी, दशानन एक mythological character है, वह अनपार्लियामेंटरी है या नहीं है, आप वह देख लीजिए।

श्री उपसभापति: मैंने कहा है कि it will be examined. ...*(Interruptions)*... I have already told that it would be examined. ...*(Interruptions)*... Shri Prasanna Acharya, you have fifteen minutes' time. ...*(Interruptions)*...

श्री सुखेन्दु शेखर राय: ठीक है। ...**(व्यवधान)**... विक्रेता सरकार कर दीजिए।

SHRI PRASANNA ACHARYA: Amar Patnaikj is not here, I will save time for another colleague. Amar Patnaikji has already left for some other work with permission. So, I will save time for my another colleague.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, you send his name because Dr. Amar Patnaik's name is in the list.

SHRI PRASANNA ACHARYA: We will give it. If not today, he will speak tomorrow. So, I will be very specific.

Sir, the hon. President addresses both the Houses of Parliament. It is the constitutional duty of the hon. President of this country. You know earlier, the system was different. Initially, the President was to address all the Sessions of the Houses during the initial period. If I am correct, when late Shri G.V. Mavalankar was the Speaker of Lok Sabha, he made certain changes. Accordingly, there was Amendment made in the Constitution and the President was to address, once in a year, the Joint Session. Immediately after the elections when the new House is constituted or in the beginning of the Budget Session, the President addresses both the Houses of the Parliament. In the speech of the President, the policy, the manifesto, the future course of action of the Government is manifested there.

Sir, this time, the President has addressed both the Houses under a very peculiar situation that is prevailing in this country. Almost in every part of the country, there is unrest. In some parts of the country including the very capital city of New Delhi, there is violence. Coincidentally, we are observing the 150th Birth Anniversary of

Bapuji, the pujya Bapuji, as Sukhendu Babu was mentioning. राष्ट्रपति जी ने बोला, and he is pujya, Sir. Bapuji is pujya for the entire nation. I will say further, not only for India but Bapuji is pujya for the whole mankind, particularly, for his principle of non-violence. We are observing 150th Birth Anniversary of Bapuji. I don't think a situation is prevailing in the country which was dreamt of by Bapuji. Bapuji was the profounder of ahimsa. His every action, his every deed, his every programme, his every planning, his every message was nothing but ahimsa. He confronted the mightiest of the world that time, the Britishers, with the weapon of ahimsa and he won, the country won under his leadership. And, ahimsa prevailed upon the oppressions and we won, the country won independence. Of course, while we are mentioning about Gandhiji's ahimsa, and our Non-Cooperation Movement during the freedom struggle, we must not belittle the sacrifices made by all those revolutionaries who also rose with weapon. We cannot belittle their contribution like Shaheed Bhagat Singh, Chandra Shekhar Azad and many others. Many other freedom fighters were there who raised swords against the Britishers including, I know, Veer Surendra Sai. Many of the Members in this House may not be knowing about Veer Surendra Sai, a tribal leader in Odisha. We know Nelson Mandela spent 26 years in jail in Africa. People say that this is the largest period of a freedom fighter spending inside the jail but Veer Surendra Sai spent 37 years of his life inside the British jail. Very few people know of it. So, we cannot belittle their contribution also. But my contention is that when the President is addressing and we are quoting Gandhiji, when we are observing, celebrating the 150th Birth Anniversary of Bapuji, what the state of affairs in this country today is. A violent atmosphere, an atmosphere of hatred, an atmosphere of distrust and disbelief between each other and between communities. So, this is a very unfortunate situation. I think it is the humble duty of all of us, all the leaders in this country, irrespective of political parties, all sections of the House and all sections in the country, we must remember Gandhiji. Sir, in this context, I want to remind everybody that last year, my leader, Shri Naveen Patnaik, the Chief Minister of Odisha, wrote a letter to the leaders of almost all the political parties. And, when the preparatory meeting was convened by the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, because he is the Chairman of the Committee to commemorate the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi, Naveenji proposed as to what is the way out in this situation. We have to remind our people about non-violence and Gandhiji. Therefore, in the Preamble to the Constitution, Gandhiji's principle of non-violence should be incorporated. The people of this nation should be reminded about Gandhiji's

Bharata of *ahimsa*, and that should be reminded not only to the people of this country, but also to the leaders of all the political parties of this country, whether from this side or that side, that we need *ahimsa* today. Gandhiji's *ahimsa* is still relevant, and particularly, in this context, in this country, it is even more relevant. Therefore, Sir, I take this opportunity to propose that let us consider seriously what Shri Naveen Patnaik has proposed - to incorporate *ahimsa* in the Preamble to the Constitution. So, everyday, the bell of *ahimsa* will ring. हम लोगों के कानों में यह बजेगा - 'अहिंसा'।

Sir, there are many good points in Rashtrapati*ji*'s Speech. It has been mentioned and I quote, "Buy local for a better tomorrow". When I was going through the Speech of Rashtrapati*ji* and noticed this message, "Buy local for a better tomorrow", I felt that we have to use local products. देसी चीज़ हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। I remember Gandhiji's Khadi Movement. All of us know that there are two aspects of Gandhi*ji*'s movement. There were two types of *satyagrahis*. First were those who were actively participating from the front, quoting arrest, confronting the police and spending their lives inside the jail, like Nehru*ji* spent so many days inside the jail. Many other leaders also spent so many days inside the British jails. But another aspect of Gandhi*ji*'s movement was a constructive movement, a movement against untouchability. There were so many volunteers in the freedom struggle, of course, led by the Congress Party at that time. Khadi Movement was one of the things. The movement against untouchability was there. Hundreds and thousands of workers, inspired by Gandhi*ji*'s ideals, were working all over the country. So, the Khadi Movement was part and parcel of Gandhi*ji*'s freedom movement. The campaign against untouchability was part and parcel of Gandhi*ji*'s freedom movement. So, likewise, I think, Rashtrapati*ji*'s slogan, "Buy local for a better tomorrow", should be taken as a movement. तो राष्ट्रपति जी ने यह बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि हमें देसी चीज़ इस्तेमाल करनी है, लेकिन सर, हम देसी चीज़ तभी इस्तेमाल करेंगे, जब देश में अच्छी चीज़ पैदा की जाएगी। सरकार देश में अच्छी चीज़ पैदा करने का माहौल बनाएगी, तभी तो हम इस्तेमाल करेंगे। अब सारी चीज़ें आप बेचोगे, which were created by our forefathers immediately after independence. Yes, credit goes to Nehru*ji* and credit goes to many of those leaders who led this country immediately after independence, like Sardar Patelji, and many other leaders. They were visionary leaders. So many institutions were built in this nation. और हमारे लोगों का पैसा उसमें लगा है। अगर हम इन संस्थाओं को मज़बूत करेंगे, हमने इस देश में जो फैक्टरीज़ बनाई हैं, उनको मज़बूत करेंगे, तभी तो देसी चीज़ पैदा होगी और जब देसी चीज़ पैदा होगी, तभी तो हम देसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर देसी चीज़ पैदा ही नहीं होगी, हमारे देश की फैक्टरीज़ को हम बंद करेंगे, हमारे देश की

ऑर्गेनाइज़ेशंस को हम क्लोज़ करेंगे, तो देसी चीज़ कहां से पैदा होगी? तो "Buy local for a better tomorrow" is a good slogan, but to buy local, we have to produce good local products. Sometimes, it seems to me that this Government's policies are contradictory. हमको इस पर ग़ौर करना पड़ेगा।

The hon. President has highlighted another good point about the drinking water. Drinking water is the necessity for everybody in this country. हर किसी के लिए पानी चाहिए। इन्सान के लिए, जानवर के लिए, पशु-पक्षी के लिए सबके लिए पानी चाहिए, and to ensure the availability of sufficient potable drinking water to each rural household in the country, the Government has launched the Jal Jeevan Mission. Jal Jeevan Mission is a very good mission. राष्ट्रपति जी ने खुद बताया है that ₹ 3,60,000 crores will be required for Jal Jeevan Mission. But, the allocation in this Budget is very funny. I was going through the Budget, 31 तारीख को राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ और 1 तारीख को बजट हुआ। 31 तारीख को राष्ट्रपति जी बोलते हैं कि Government has undertaken the Jal Jeevan Mission, राष्ट्रपति जी के मुँह से खुद सरकार बोलती है कि जल जीवन मिशन के लिए 3,60,000 करोड़ चाहिए। 1 तारीख को बजट आता है और बजट में प्रोविजन कितना है - मात्र 11,500 करोड़। The requirement is ₹ 3,60,000 crores and the allocation is ₹11,500 crores, अगर आप इस हिसाब से allocation करते रहेंगे, तो इसमें आपको कितने साल लगेंगे, कितनी पंचवर्षीय योजनाएँ लगेंगी? So, you must be practical, हम राष्ट्रपति जी के मुँह से एक बात कहलवाते हैं और दूसरे दिन इसको हम नकार देते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इन सारी चीज़ों पर गौर करना चाहिए। Sir, another good thing that Rashtrapati*ji* has said in his speech, and drawrn the attention of the nation; is air and water pollution. Now, pollution is one of the biggest problems in this country, मुझे नहीं लगता कि इस बारे में राष्ट्रपति जी के मुँह से आप भाषण पढ़वाते हो और खुद सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। आज दिल्ली की क्या position है? Sir, it is unfortunate to note that 15 out of the 20 most polluted cities in this world are in India. Fifteen most polluted cities in the world are in India. आप गुरुग्राम को देखिए, गाज़ियाबाद को देखिए और खुद दिल्ली को देखिए। They have obtained first, second and eleventh position पूरी दुनिया में and not in India. This is the picture of the world. तो दिल्ली की यह position है, जहाँ हम लोग बैठे हैं, जहाँ capital है, जहाँ पार्लियामेंट है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट है और जहाँ देश का भाग्य निर्णय हम लोग कहते हैं। मुझे यह कहना है कि राष्ट्रपति जी का जो भाषण है, उस पर ज्यादा गौर सरकार को करना है। You have to be more attentive and careful about the speech of the President which has been prepared by the Government itself. इस बारे में हमें ध्यान देना है। Sir, another good thing which the hon. President has mentioned is about the museum for tribal freedom fighters. It is a very good thing. Just now, I was mentioning about Veer Surendra Sai

and others. But, as I hail from the State of Odisha, my pain is that you are going to have a museum for tribal freedom fighters at certain places, but, the State of Odisha has been excluded. Sir, I will take two or three names of the tribal leaders. Laxman Nayak was a Congress leader in the Koraput District. Once upon a time, this District was famous for its poverty. Sir, Laxman Nayak was a Gandhian. He participated in the non violent movement of 1942. While, he was leading a procession, the Britishers fired like Jallianwala Bagh in which 22 people were killed. History has ignored this. Laxman Nayak was implicated in that case. In the year 1943, Laxman Nayak was hanged in Berhampur jail, the memorial is there. Then, there was Veer Surendra Sai. Also, there was Khond movement in Odisha. Khond is a tribal community. Then, there was Bakshi Jagabandhu Bidyadhara Mohapatra, a soldier, who led a fight against the Britishers तो जिस स्टेट में इतने ट्राइबल लीडर्स रहे हैं, इतने फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जिन्होंने अपनी life sacrifice की, वहाँ आप कम से कम एक museum तो बनाओ। यह राष्ट्रपति जी की स्पीच में नहीं है। Then, there was Birsa Munda. We must not forget him. Though, Birsa Munda was born in Ranchi, the main area of operation of Veer Birsa Munda was the Sundargarh District of Odisha. People of Odisha and Jharkhand, even today, they worship Birsa Munda as God. You can find the statue of Veer Birsa Munda at different places.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have taken fifteen minutes. ...*(Time-bell rings)*...

SHRI PRASANNA ACHARYA: Sir, I will conclude in two minutes. Kandha Revolution and different revolutions were there. Sir, I am very happy, I am proud that the hon. President has mentioned about Triple Talaq law. ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया। We want emancipation of Muslim women from torture, from oppression, from social injustice but what about the women of other communities? I am not discussing it in detail because the hon. Supreme Court is seized of the matter in Sabarimala issue. On the one hand, we want emancipation of the Muslim women but, on the other hand, we want to prevent Hindu women from entering into a temple to offer their prayer to the God. This is quite contradictory, Sir. I am not discussing it in detail because the Supreme Court is seized of the matter.

SHRI T.K. RANGARAJAN: Parliament is supreme.

SHRI PRASANNA ACHARYA: Okay, Sir, but let us not make it an issue of confrontation. It is sub-judice and the Court has gone in for the full Bench and they will be hearing the matter very shortly. यह किस प्रकार की मानसिकता है? Neither I am

[Shri Prasanna Acharya]

criticising the Government nor am I pointing at the Opposition. एक तरफ तो हम चाहते हैं मुस्लिम विमेन में या किसी भी कम्युनिटी में, किसी रिलिजन में अगर कोई सुपरस्टिशन है, तो उसे हमें दूर करना होगा। अगर किसी प्रकार का भी अत्याचार है, if there is oppression against the women, we are for the emancipation of women but there should not be discrimination between Hindu women, Muslim women and Christian women. नज़रिया एक होना चाहिए। We must be broad-minded and large hearted. मुझे यही कहना है। मेरे एक-दो प्वाइंट्स और हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please keep in mind that only three minutes are left for the other speaker of your Party. You have already taken 17 minutes.

SHRI PRASANNA ACHARYA: You are gracious enough, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, it is not in my hands.

SHRI PRASANNA ACHARYA: Sir, I have many points but due to paucity of time, I am not mentioning all of them. Now, I come to my last point. I also want to give time to my other colleague. Hon. President has mentioned about tourism. It is a good thing. In his Address, hon. President has dedicated three paragraphs to tourism. Sometimes, we ignore this aspect but I am thankful to the President that he has mentioned at length the issue of tourism in the country. The Address mentions, "India has moved from 52nd to 34th position in the World Economic Forum's Travel and Tourism Competitiveness rankings". It is great to learn but my point is that Odisha seems to be neglected and marginalised in the tourism sector by the Central Government. My State has more than 450 kilometres' coastline area. You know it. Additionally, it has two big ports, namely, Paradip Port and Dhamra Port, apart from three small ports. Sir, there is a greater scope for coastal and cruise tourism in Odisha. Sir, nationally also, we have to encourage cruise tourism. Because Odisha has a vast coastline, there is vast scope for tourism. I think the Government should unfailingly try to reap the benefits by exploring these possibilities. Because there is no time left, I am not going to speak about the target of five trillion dollar economy. I will take the advantage of speaking about the economy and all those things during the Budget discussion.

With this, I compliment the hon. President of India for his Address to both the Houses. On behalf of my Party also, I express my gratitude to the hon. President for his Address to the joint session of the Parliament. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, hon. Prasanna Acharya ji. You have left only one minute for your other speaker and it should be on record. Now, Shri Ram Chandra Prasad Singh ji.

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (बिहार): उपसभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय ने जो हम लोगों को संबोधन किया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं तथा उन्हें धन्यवाद देता हूं। अभी जल जीवन मिशन के बारे में चर्चा हो रही थी। मेरा अनुरोध होगा कि जीवन के लिए जल तो जरूरी है ही और साथ ही साथ हरियाली भी जरूरी है। बिहार में हमारे नेता वहां के माननीय मुख्य मंत्री, श्री नीतीश बाबू जी ने बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन का कार्यक्रम चलाया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल जीवन के साथ हरियाली को भी अगर जोड़ लिया जाए तो यह मिशन और भी ज्यादा कारगर और टिकाऊ होगा। अभिभाषण में यह कहा गया है, जो सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ उच्च शिक्षा में लड़कियाँ की जो enrolment संख्या है, वह इस देश में पहली बार लड़कों से भी ज्यादा हो गई है। इसके लिए हम सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। जो सैनिक स्कूल्स हैं, इनके संबंध में जो mindset था कि सैनिक स्कूल में सिर्फ लड़के पढ़ सकते हैं, अब पहली बार सैनिक स्कूल में लड़कियों का भी दखिला होगा, यह भी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। इसके लिए भी मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही, यह जो fighter team है, जो एयरफोर्स में है, डिफेंस अटैची है, उसमें भी लड़कियों को जो सम्मिलित किया गया है, यह भी बहुत ही सराहनीय कदम है। बिहार में हमारे नेता ने जब लड़कियों के लिए साइकिल की योजना शुरू की थी, साइकिल बड़ी छोटी चीज दिखती है, लेकिन उसका जो प्रभाव उनके पूरे मनोवैज्ञानिक और मानसिक विकास पर पड़ता है, इसका आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं, जब तक आप उसको सामने से नहीं देखेंगे। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर सरकार की तरफ से जो काम हुआ, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ।

सर, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा है कि 2014 में हिन्दुस्तान में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ दो कंपनियाँ थीं और आज पाँच वर्षों में हमारा देश दुनिया का second largest mobile manufacturing देश हो गया है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ जो पूरा का पूरा electronic manufacturing sector है, उसमें भी काफी विकास हुआ है। जब हम लोगों को $5-trillion की economy बनानी है और उसके लिए आपने दो defence corridor और पाँच industrial corridor की भी चर्चा की है। मेरा सरकार से अनुरोध होगा, defence corridor के संबंध में बताया गया कि एक उत्तर प्रदेश में और एक तमिलनाडु में, बिहार में भी इसकी आवश्यकता है और हमारे यहाँ खास करके नालन्दा में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उसके पास काफी जमीन है, उसका उसमें उपयोग किया जा सकता है। साथ ही, जो industrial corridor है, रेलवे का जो फ्रेट कॉरिडोर बना है, उसमें भी मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि बिहार में इसको लगाया जाए। चूँकि बिहार में ऐतिहासिक कारणों से जितना industrial

[श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह]

development होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है, इसलिए यह मौका है, जिसमें बिहार को भी अवसर मिलना चाहिए और मैं आशान्वित हूँ कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

सर, अभी एक बात, जो बड़ी चर्चा में रही और मैं सुन रहा था। पहली बार मैं देख रहा था कि हमारे लीडर ऑफ दि अपोज़िशन बहुत ही डेटा दे रहे थे और compare सिर्फ दो स्टेट्स को कर रहे थे और वे स्टेट्स थे जम्मू-कश्मीर और गुजरात। यह बात कही गई कि सरकार को नॉर्थ-ईस्ट और कश्मीर पर ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी और उन्होंने 1954 का जिक्र किया। उन्होंने एक और बात का जिक्र किया कि अभी सरकार ने वहाँ पर जो बहुत सारे Ex-CMs रहे हैं, उनको जेल के अंदर डाल रखा है। हम लोग किसी को भी जेल के अंदर डालने के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन आप सबको पता होगा ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: उन्होंने 1954 गर्ल्स एजुकेशन का कहा था।

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह: हम दूसरी बात पर हैं। आज जरा याद करिए कि 1953 से 1964 तक आपने वहाँ के किनको बंद किया था? किसको बंद किया था? शेख अब्दुल्ला साहब को। आपने उनको कितने सालों तक बंद किया था?

श्री भूपेन्द्र यादव: दस साल तक।

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह: नहीं, 1953 से 1964 तक बंद किया था यानी 11 साल तक एक बार बंद किया था, उसके बाद तीन साल तीन टर्म और। अभी सब लोग स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा कर रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन में जेपी का क्या रोल था? आप लोगों ने 1975 में उनके साथ क्या किया? आपने उनको जेल में डाल दिया। आपने क्या आरोप लगाया? हमारे नेता नीतीश बाबू जेल में रहे, उन्होंने क्या अपराध किया था? देखिए, आपके लिए यह शोभा नहीं देता है कि आप यह कहें कि आपने इनको क्यों बंद कर रखा है? जिस समय आप चर्चा करते हैं।

श्री आनन्द शर्मा: इसमें जेपी का नाम नहीं है।

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह: चलिए, हम उस पर चर्चा करेंगे। हमने चर्चा कर दी न, आएगा।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज़, प्लीज़, कृपया शांत रहें।

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह: सर, अब असम की बात कर रहे हैं। आप जरा ध्यान कीजिए और 1983 को याद कीजिए। मैं यह इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उसका eyewitness था। 1983 में क्या था? President's Rule था। वहाँ पर क्या स्थिति थी? आपने वहाँ असेम्बली का चुनाव कराया। मैं चुनाव कराने गया था। उस समय विधान सभा में कितने वोट पड़े? किसी विधान सभा में 85 वोट पड़े, किसी में 200 वोट पड़े। एकमात्र हितेश्वर सैकिया, जो आपके मुख्यमंत्री बने, उनके क्षेत्र में 14,000 वोट पड़े और आपकी विधानसभा भी बन गई। मैं वहाँ था। क्या आज

ऐसा संभव है? 60 वोट पाकर, 200 वोट पाकर, 300 वोट पाकर, आपने विधान सभा बना ली। आप किसकी बात कर रहे हैं? उसी समय 1983 में याद करिए फरवरी के महीने में क्या घटना हुई? मैं Sivasagar जिले में था, बगल में ही Nillie था। आप संख्या छोड़ दीजिए, एक रात में कई हजार लोगों का कत्ल कर दिया गया। वे कौन लोग थे, किसकी सरकार थी? President's rule था। उसके बाद क्या हुआ साहब? आपने तिवारी आयोग का गठन किया, 800 एफआईआर दर्ज हुई। उन एफआईआर का क्या हुआ, अभी तिवारी आयोग की रिपोर्ट कहाँ है? आप क्या बात कर रहे हैं? अगर आप हम लोगों को खोदने लगेंगे, आपको खोदने का अधिकार नहीं है। देखिए, इस देश का एक इतिहास है, यहाँ हम जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे आप उधर हैं या इधर हैं। ...**(व्यवधान)**... जयराम रमेश जी, इस लोकतंत्र में सब लोगों को सरकार बनाने का मौका मिला है और यही हमारे लोकतंत्र की खासियत है ...**(व्यवधान)**... और जब मौका मिलता है, तब काम करना चाहिए। ...**(व्यवधान)**... सुन लीजिए साहब, अभी ज़रा सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**... बेसिक बात है। ...**(व्यवधान)**... आप लोग तो बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं। आप सीएए की चर्चा कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... जयराम रमेश जी, आप ज़रा सुन लीजिए। हम लोगों का क्या सिस्टम है? Federal system है। Federal system में क्या होता है? Union list, State list, Concurrent list होती है। Union list में 17 नंबर पर क्या है? सिटिजनशिप है, naturalization है, aliens हैं। अगर आप सीएए की बात कर रहे हैं, तो 1955 में जो हमारा सिटिज़नशिप एक्ट बना, इसका मतलब वह भी गलत था। हमारा कहना यह है कि जो विषय केन्द्र की सूची में है और केन्द्र उस पर कानून बनाता है और कानून बन जाता है, तो क्या उसे मानने के अलावा कोई और रास्ता है? अभी टी.के. रंगराजन जी कुछ बात बोल रहे थे। अगर संविधान में आप कोई कानून बनाते हैं और वह संवैधानिक नहीं है, तो आप यह तय नहीं करेंगे, सड़क पर तय नहीं होगा, बल्कि कोर्ट में तय होगा और सीएए आज कोर्ट में है, तो आप लोगों को जाकर क्यों कह रहे हैं कि इस पर आंदोलन करिए? और तो और आप विधानसभा में प्रस्ताव ला रहे हैं। साहब, यह तो अच्छी बात है। हमारी सरकार ने बिहार में शराबबंदी लागू की। चूँकि हमारी राज्य सूची में है कि आप शराबबंदी करिए और हमने उसे लागू किया, तो क्या केन्द्र सरकार उस कानून को रोक देगी? मैं यह इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को बेसिक चीजें क्लीयर होनी चाहिए। आप भी सत्ता में रहे हैं, ये भी सत्ता में हैं, हम लोग भी सत्ता में हैं, तो जिसका जो दायित्व है, जो हमारा federal structure है, उसमें हम लोगों को इस बात के लिए ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: ये सज्जन व्यक्ति हैं। ...**(व्यवधान)**... मैं कुछ कहने जा रहा हूँ और आप बोल रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... अभी माननीय राम चन्द्र प्रसाद सिंह जी ने कहा, मैं इनका सम्मान करता हूँ। ...**(व्यवधान)**... इन्होंने कहा कि राज्यों में जो विरोध हो रहा है या विधान सभाओं में प्रस्ताव पारित होता है, पहली बात यह है कि हमारे संविधान में राज्यों के लिए अलग स्थान है, पर जो प्रस्ताव पारित होने की बात है और जहाँ तक राज्यों का प्रश्न है, आपने यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट की बात ठीक कही, पर अगर संसद कोई कानून बनाती है, तो संविधान के आर्टिकल 131 में, जहाँ original jurisdiction की बात आती है, अगर राज्य किसी कानून से

[श्री आनन्द शर्मा]

सहमत नहीं है, तो वे उसे चुनौती दे सकते हैं और वही वे सर्वोच्च न्यायालय में दे रहे हैं। सिफ इतना ही है। वे अपने अधिकार से बाहर नहीं जा रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: वे कानून पास थोड़ी कर सकते हैं।...**(व्यवधान)**... यही Cooperative Federalism के खिलाफ काँग्रेस का मत है। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: आप Cooperative Federalism पर कहाँ विश्वास रखते हैं? ...**(व्यवधान)**... आपने किस राज्य से चर्चा की? ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: यह जो Cooperative Federalism है, उसका अर्थ है कि जो बैलेंस है, हम उस बैलेंस को स्वीकार करें। ...**(व्यवधान)**... वे इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इसे रेज़ कर रहे हैं। काँग्रेस यही कर रही है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record.

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, he has yielded. In the name of cooperative federalism, you are encroaching upon the powers of the States and making the States as Panchayats. That way, you cannot keep Bharat as one. That is the danger.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Rangarajanji, please take you seat now.

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह: मैंने अभी सीएए की चर्चा की। जब यह देश का कानून बन गया है, तो यह सही है या गलत है, यह संवैधानिक है या असंवैधानिक है, यह कोर्ट में है और ये सारी चीज़ें तय हो जाएँगी। आप इस इश्यू पर मूवमेंट में क्यों जाते हैं? आप लोगों को समझाइए कि हमारा क्या रोल है। देखिए, हमारा जो रोल है, उसमें हम लोग चाहते हैं कि समाज में सामाजिक सद्भाव रहे, साम्प्रदायिक सौहार्द रहे। ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश: आपने मेरे क्वेश्वन का जवाब नहीं दिया। ...**(व्यवधान)**...

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह: हम अभी उस पर आ रहे हैं।

श्री उपसभापति: कृपया बैठकर न बोलें। ...**(व्यवधान)**... Jairam Rameshji, you are a senior Member. ...*(Interruptions)*... Please. राम चन्द्र जी, आप चेयर को ऐड्रेस करें।

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह: आप एनआरसी की चर्चा कर रहे थे। एनआरसी कहाँ से शुरू हुआ था? वह किस प्रदेश में शुरू हुआ, किसने शुरू किया और किसकी सरकार थी? ...**(व्यवधान)**... बस, आप सोच लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Jairam Rameshji, please take your seat. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*...

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह: अभी आप देखिए कि हम आप सबकी बात मान लेते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ यह राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, हमें इसको मानना है। अगर उप-राष्ट्रपति जी कुछ कहते हैं, तो उसे मानना है और अगर देश के प्रधान मंत्री कुछ कहते हैं, तो उसको भी मानना है, चाहे आपके प्रधान मंत्री हों, अभी के प्रधान मंत्री हों या कोई आगे के प्रधान मंत्री हों। प्रधान मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि अभी असम के बाहर कोई एनआरसी नहीं है। इसलिए हमारे नेता, बिहार के मुख्य मंत्री, आदरणीय नीतीश बाबू ने भी यह कहा है। जब प्रधान मंत्री कह रहे हैं, तो क्या आप उन पर भरोसा नहीं कीजिएगा? ...**(व्यवधान)**... Time being हो या all the time, लेकिन समस्या यह है कि जब देश के प्रधान मंत्री कह रहे हैं, तो क्या आप उन पर भरोसा नहीं कीजिएगा? आज के टाइम में हमारे देश में सबसे बड़ा पोलिटिकल लीडर कौन होता है? आप मानें या मत मानें, वह देश का प्रधान मंत्री होता है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज़, बैठकर टिप्पणी न करें।

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह: अब चाहे कितना परसेंट आ जाए। क्या आपको कभी 50 परसेंट आया है? ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Jairam Ramesh*ji*, nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*...

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह: आपको भी कभी 50 परसेंट नहीं आया है, यह बात आप जान लीजिए। दूसरा, जयराम रमेश जी एनपीआर की बहुत चर्चा कर रहे थे। यह किसके समय में शुरू हुआ जी? वर्ष 2011 में कौन थे? आप हमको मत बताइए कि वर्ष 2011 में प्रधान मंत्री कौन थे? यह जरूर है कि उसमें कुछ इस तरह की नई सूचनाएँ माँगी जा रही हैं और उन पर आप कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। आजकल हमारे ग्रामीण इलाकों में बहुत गरीब लोग रहते हैं, जिनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं रहती है। उन सूचनाओं को माँगने से उनके मन में संदेह हो जाता है। हमारी जो एनडीए की बैठक हुई थी, उसमें हम लोगों ने इस बात को रखा है और सरकार इस पर विचार करेगी, लेकिन आप ज़रा यह सोचिए कि जब आप करें तो बड़ा अच्छा है! आप आंदोलन की बात कर रहे हैं ! आप सुन लीजिए। अभी सभी लोगों ने आंदोलन की चर्चा की। क्या जेपी मूवमेंट से भी कोई बड़ा आंदोलन इधर हुआ था? इधर क्या आंदोलन हुआ है और आज आप जा रहे हैं, हमने तो एक ही दिन सुना है। देखिए, हम लोगों को देखना चाहिए कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। एक बड़े भाई, कोई फिल्म के थे, मैं सुन रहा था। वे क्या बोल रहे थे? वे किसी जगह का नाम लेते हैं, हम किसी जगह का नाम नहीं लेते हैं। वे धरने पर क्या बोल रहे हैं? वे बोल रहे हैं कि हमारे देश की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी, दोनों एक तरह की है। वह भी अपने लोगों को मारती है और हमारी आर्मी भी अपने लोगों को मारती है। हिन्दुस्तान की आर्मी का यह कैरेक्टर नहीं है।

6.00 P.M.

श्री आनन्द शर्मा: यह किसने बोला?

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह: यह मैंने टीवी पर सुना है। मैंने यह बिल्कुल लाइव देखा है। यह "इंडिया टीवी" पर दिखाया जा रहा था, जिसको मैंने खुद सुना। देखिए, आप ज़रा जान लीजिए। हमारे देश की जो सेना है, आपमें से कुछ लोग मंत्री रहे हैं और आप लोग गए होंगे, लेकिन वे जिस जगह पर रहते हैं, वहाँ जब वे 40 मिनट अपने हाथ सेंकते हैं, तब वे लोग खड़े होकर जा पाते हैं। हम लोग नाथुला पास में गए हैं, वहाँ ट्रेनिंग में रहे हैं! आप क्या बोलते हैं! हिन्दुस्तान की जो फौज है, उसका मनोबल नीचा मत कीजिए।

श्री आनन्द शर्मा: यह किसने बोला?

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह: आप "इंडिया टीवी" देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। यह मैंने देखा है, तब बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही बात नहीं करता हूँ। मैंने उसको ऑनलाइन सुना है, इसीलिए मैं यह बता रहा हूँ। देखिए, हमारा क्या दायित्व है? हम सब लोग यहाँ हैं और यहाँ इस हॉल में हमारा दायित्व यह है कि देश में एक ऐसा माहौल बने, जहाँ सामाजिक सद्भाव हो, साम्प्रदायिक सौहार्द हो, भाईचारा हो। हम सब लोग विकास की बात करते हैं। विकास के लिए जरूरी है कि लोगों के बीच आपस में कम से कम इस प्रकार की भावना हो कि लोग एक-दूसरे पर हमेशा भरोसा करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज़, बैठकर टिप्पणी न करें। Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह: देखिए, ऐसा काम मत कीजिए, जिससे लोगों को लगे कि नहीं साहब, तरह-तरह की जो बातें होती हैं, उनमें दम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा क्या दायित्व बनता है? हमारे देश की क्या पृष्ठभूमि रही है? विविधता में एकता ...**(व्यवधान)**... आप गोली मारने के बारे में बता रहे हैं, हम आपको बताते हैं। 18 मार्च, 1974 को पटना में कितनी गोलियाँ चलाई गई थीं? किस पर गोलियाँ चलाई गई थीं? वे सारे विद्यार्थी थे। तब कितने लोग मारे गए थे? मैं तो वहाँ रहा हूँ। 1974 में किसने ऑर्डर किया था? आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वह ऑर्डर किसी मेजिस्ट्रेट ने नहीं दिया था, बल्कि वहाँ आप ही के माननीय मुख्य मंत्री थे, उन्होंने वह ऑर्डर दिया था। हम लोग केस स्टडी पढ़ते थे, इसलिए आप हमें ये सब मत बताइए। आप एक बात कह रहे थे, आपको खराब लगेगा, लेकिन मैं बोल दूं कि हम लोग चाहते हैं कि यहां जितने लोग हैं, उनमें किसी की कोई बात स्लिप न करे, गोली मारने की बात, आप इतना जान लीजिए, इसी देश में हमारे बिहार के ही एक मंत्री रहे, उन्होंने राष्ट्रपति जी के बारे में क्या कहा, राष्ट्रपति भवन के बारे में क्या कहा था, आप लोग शायद भूल गए होंगे, उस समय आतंकवाद का माहौल चल रहा था, आप याद कीजिए कि क्या कहा था। यह हमारा दायित्व है कि अगर कोई इस

तरह की बात करता है तो हम सबको उसे समझाना चाहिए, modernisation करना चाहिए, हमें किसी को encourage नहीं करना चाहिए।

श्री उपसभापति: माननीय राम चन्द्र जी, एक मिनट के लिए अपनी बात को विराम दे दीजिए, माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURLEEDHARAN): For Discussion on the Motion of Thanks, the Business Advisory Committee has allotted twelve hours. The day after tomorrow, the hon. Prime Minister is expected to reply at around 5 o'clock. I propose that if the House agrees, we may sit up to 7 o'clock.

श्री उपसभापति: माननीय सदस्यगण, बहुत सारे लोग अभी बोलना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो हम लोग देर तक बैठ सकते हैं, क्योंकि कुल 48 स्पीकर्स हैं। हम कल भी देर तक बैठ सकते हैं, मेरा इसके लिए आपसे निवेदन है। Please continue.

श्री आनन्द शर्मा: इस पर हमारी और सरकार की चर्चा हो चुकी है।

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह: उपसभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है और माननीय प्रधान मंत्री जी ने पटना में भी गांधी मैदान में कहा था कि उन्होंने अपने प्रयास से सऊदी अरब से बात करके हज का 2 लाख तक का कोटा बढ़ाया है। हम इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। आप यह जान लीजिए कि हमारे जो हुनर हाट हैं, आपको बता दूं कि बिहार में हमारे मुख्य मंत्री जी ने शुरू में हुनर योजना चलाई थी। हुनर के साथ-साथ औज़ार, हमारे कई हज़ार अल्पसंख्यक बच्चों को रोज़गार मिला। मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि हुनर हाट योजना के तहत आपने 2 लाख से ज्यादा का आवश्यक कार्य किया है। आप पूरी वक्फ़ प्रॉपर्टी को डिजिटलाइज़ करा रहे हैं, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरा एक अनुरोध होगा कि यह जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है, बिहार में हमारे नेता नीतीश बाबू ने सबसे बड़ा काम यह किया है कि जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के गरीब बच्चे पढ़ाई में पीछे रह गए थे, जितनी हमारी वक्फ़ की प्रॉपर्टी है, वहां पर जिस प्रकार से हमने अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों के लिए रेज़िडेंशियल स्कूल बनाए, इसी प्रकार से बिहार में हमारे अल्पसंख्यक बच्चों के लिए वक्फ की प्रॉपर्टी पर इस तरह से रेज़िडेंशियल स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं, अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे, वे चले गए हैं, वे कह रहे थे कि दो साल पहले आप कहां थे? मैं बता दूं कि बिहार में हम अपनी वक्फ़ की प्रॉपर्टी पर एस.सी./एस.टी. बच्चों के स्कूल्स के पैटर्न पर रेज़िडेंशियल स्कूल्स बना रहे हैं। बिहार में अभी जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उपमुख्य मंत्री हैं, वे बीजेपी के हैं, क्या उन्होंने किसी प्रकार की आपत्ति की है, नहीं की है। हम लोगों की सरकार 14 साल से चल रही है, बीच में 20 महीने

[श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह]

साथ में नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में जो हमारा अल्पसंख्यक का पूरा समाज है, वहां जिस प्रकार का माहौल बनाया गया है, वहां कहीं भी, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, जितनी भी योजनाएं हैं, उसमें हमारे बीजेपी के सहयोगी मंत्री उतना ही योगदान देते हैं। मेरा अनुरोध होगा कि अब इन सब चीज़ों को बंद करके देश में ऐसा माहौल बनाया जाए, जिसमें सबका दायित्व बनता है, आपका दायित्व भी बनता है, हमारा दायित्व भी बनता है और सरकार का दायित्व भी बनता है। हम ऐसा माहौल बनाएं, जिससे कि हमारा जो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है। आप कहीं भी बाहर जाएं तो आपको भी कहने में अच्छा लगे। हम अपने देश की इस प्रकार की इमेज बनाएं, जो भारत ने अपना नाम कमाया है, वह इमेज आगे भी बनी रहे, धन्यवाद।

श्री उपसभापति: राम चन्द्र जी, धन्यवाद। डा. के. केशव राव।

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, I thought I would be speaking tomorrow, anyhow, ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: आप लोग कृपया बैठकर चर्चा न करें।

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, I stand as a matter of rule with some kind of a reserved heart to thank the President for his Address. But I was wondering to myself as to why. The question is, is it because are we starting the 21st Century, mutilating the very Constitution and its Preamble or is it because we have sent all the millions and millions of people to the street? Good or bad, I am not trying to take this stand or that stand. We have voted for Kashmir Bill. We have voted for other Bills, which BJP had brought. We had opposed the CAA and we will continue to oppose it. But it is not without reason. There is a philosophy behind it. The philosophy is the idea of India. What is the idea of India? What is the man as such? If it is a universal man for Rabindranath Tagore and a spiritual man for Aurobindo, it is all the humanity for Mahatma Gandhi, and for Vivekananda, it is man and man, and for Dr. Radhakrishnan, East and West the same man, if that is the idea which has gone into the very creation of our Preamble and the creation of Constitution and this day when we are standing here... celebrating the completion of the 70th year of our Republic, I was wondering how would I start this debate at all. As a matter of fact, there are many things as Ram Chandra*ji* said, they are good points. Everybody agrees. Shri Prasanna Acharya raised very good points. But, what happens? Even one drop of poison in the pot of milk spoil it, would make a poison of all of it. The question is, in spite of all this, something is happening. I am asking you a simple question. It is not that I am taking one extreme stand and trying

to talk to others. But, are you not seeing today in this very debate some kind of a mindset, some kind of a suspicion of a communal polarization? Why? We have supported the abrogation of Article 370. Today, Shri Ghulam Nabi Azad came out with statistics and told you what? It is not that how the elections were held there and how many people were elected to this House and how that House was elected as Prasad said. It is about the reasons that we gave support on that day. We supported the Bill on Jammu and Kashmir. You said, "Look, these are one, two, three, four, five points on which Kashmir has gone down." And he has come out today with all the statistics given by the RBI and said, "Look, this is the truth." If that is the truth, then we were misled, I really think what exactly is happening. I can only join him in one slogan. All right, you had promised that you have made it a Union Territory, you brought Lt. Governor on the promise that you will make it soon a full-fledged State. When will you do it? Please tell us today. Please promise us that after hearing him or after convincing yourself that it must become a State. It was a State for many years. लद्दाख को छोड़ दीजिए। कश्मीर तो स्टेट था। कश्मीर अब हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया है। उस दिन प्रसन्न आचार्य जी बहुत emotions के साथ बोल रहे थे। मैं उतने emotions के साथ नहीं बोल सका, लेकिन मैं भी वही बोलना चाह रहा था। अगर वह हिंदुस्तान का पार्ट है, तो क्यों न रहे? ये सब चीज़ रहें, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि वह separate state नहीं रहना चाहिए, वह Union Territory रहना चाहिए। ठीक है, वह बात अलग है, लेकिन मैं आज की बात आपको बताना चाह रहा हूँ। Sir, we had promised and we have created it. What exactly is there in this book (showing Constitution)? On this, the entire law stands, and this law is made on the Preamble because the Preamble says that we give to ourselves the Constitution based on this Preamble. This Preamble says, "We, the people of India," who were the people at that time? You said in the report, 22 crore people. Today, we are 130 crores. Twenty-two crore people gave the Constitution, and one thirty crore people are breaking the Constitution. Are you agreeing with that? And I must tell you that not only you, other people have also supported your stand about the Lists. This is the Central List, this is the State List, this is your power and that is their power. As far as Telangana is concerned, we have decided that we are going to pass a Resolution in our Assembly opposing CAA. And after clarifying the philosophical idea as to why it should go. You can't have a law that is going to mutilate, that is going to violate the Constitution. You can have a constitutional amendment to change the Constitution; you can have a constitutional amendment to change the law; you can have a law to change the law, but, you can't have a law to change the Constitution. That is what

[Dr. K. Keshava Rao]

exactly you are trying to do today. Now, what we are trying to do is, there comes a Bill which says, "Up to 2014, people who are here as illegal - all people will get the citizenship except the Muslims. What is this? How did this thought come at all into our mind? All right, after 2014, do you think the religious persecution will stop there?

क्या persecution stop होता है? उसी लेवल पर मैं second करता हूं, जिसे आपने भी quote किया, सुखेन्दु शेखर दा ने भी कहा कि गांधी जी को quote मत कीजिए। गांधी जी को जावेद साहेब ने भी quote किया, उनका कहना entirely different था Javedji quoted Gandhi*ji*. It is entirely different. It is comment of 'The Fifth Columnist', newspaper after newspaper, were speaking up. I am a student of philosophy, the philosophy of Gandhi. He must have a broader spirit saying, 'If you are not happy there, try to come here and the Indian Government will take care of you.' The spirit was to welcome them. We are also saying that you welcome them. Why think of only some? That was the case when particularly Pakistani Sikhs were under persecution. Now, why are you trying to alienate Muslims, exclusively? Even if they come, how many would they be? You yourself said that you witnessed what and how it happened in Assam. The Assam Accord was in 1958. If the effective date in Assam Accord could be advanced to 2014, can't it still be advanced till today? Why create this suspicion? Why are you disturbing the apple cart? It was running smooth. We had a smooth sailing. All of a sudden, you brought in something to create some kind of suspicion in the minds! This suspicion is nothing but polarization. This polarization could have been rich vs. this poor; it could have been very good; my friend from the Communist Party could have supported it. Vaiko would have supported it. But, it is on the communal lines!

In Hyderabad, we have 13-14 per cent of Muslims. We are absolutely peaceful today. We are opposed to CAA. No Shaheenbagh or such thing. I should only thank our Chief Minister, Shri Chandrashekar Rao for being so bold, having such a clarity of thought and philosophy as to how a law should be made and how Constitution be respected by the supporting laws and citizenry. Once a suspicion of polarization gets into the minds of the citizenry, the nation will collapse. This was our idea and all of you would agree. Firstly, Shri Ram Chandra Prasad would agree that the central idea of India is certainly great and spiritual. It is something inclusive; it is not one or two people, at all. It is such a great inclusiveness! It is being spoiled because of one law which has no wings to fly, no legs to walk. This is exactly what is happening. Please understand as to why we are opposing it. It is because of omission of one word,

'Muslim'. I had an objection the other day when we asked as to why not include the Sri Lankan people. There is a real persecution there. Shias are persecuted there. You have brought in the word as if we are fighting with them.

These are the people who have contributed to write the Constitution for the people whom you know. You are also a part of the great Freedom Movement, which Acharya*ji* also reflected. All those people had really dreamt of the country and gave laws. I am sure that any modern state must certainly have the boundaries to determine its nationalism. Ram Chandra Prasad*ji*, you yourself said that you should have such a thing. Some hon. Member raised the issue about a fact that was raised in the Standing Committee on Home Affairs, when Pranab*da* was presiding over it. We agree that there has to be one. But, there is a difference between that day and today. That day, there was no suspicion of this kind even if you talked of strict rules being made. Why is Bihar too, today is little apprehensive or doubtful or suspicious or reserved in its own mind as far as NPR and NRC are concerned? It is only because you are saying that CAA is a first step towards NRC. It means what? About CAA, what you are thinking is, a citizenship based on community or citizenship based on religion will get into NPR. This is simple logic. It doesn't require big argument on my part to say what exactly happens. These kinds of suspicions have come into our minds and we should not allow these to get deepened. The nation will be there, the boundaries might be safe, but the minds will divide. Once the minds are divided in a nation, it is no nation at all. This is what is happening and we are not trying to feel for it. To my mind, this is not a Hindu-Muslim feeling although people perhaps are thinking. There cannot be a greater arch Hindu than our Chief Minister who has done so many *yagnas*. He is such a arch Hindu, but he doesn't have any qualms *vis-a-vis* the Muslims. He sits, dines, sings and mingles with Muslims. Why? It is only because of the way we look. This is exactly the idea where India is.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The second speaker of your party has been given five minutes to speak.

DR. K. KESHAVA RAO: People are always saying, 'what is the idea that you are talking about?' The other day I heard the Minister saying. The idea is some kind of a spiritual feeling on which we have built a nation. We have built a nation out of our dreams. The founding fathers thought that this should be 'our India'. This is our India of inclusiveness, a plural society. Such a pluralistic society cannot think in terms of

[Dr. K. Keshava Rao]

Hindu or a Muslim or a Sikh or a Parsi and particularly when things are going on smoothly. There is, what is known as the Citizenship Act of 1955. It is there in place. If you wanted to exclude Mr. Khan out of Citizenship, you could have done it within the rules without telling him. If you had that kind of mind you would have done it. What is this you are saying, 'I will bring a law. I will change my Constitution. I will mutilate my Constitution. I will destroy my Constitution. I will destroy the idea of India to see that Javed is not there.'?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Keshava Rao, you have another speaker from your party to whom you have given five minutes' time.

DR. K. KESHAVA RAO: How much time do I have?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: As per your party's request, you have already taken your time.

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, I will take only one minute more. Sir, over the last two days, this House was really disturbed and you have mistaken their concern. All the people from Trinamool Congress and from this side came and shouted. They don't belong to one particular section or one particular community. They just talked about the country as such and the unity. Sir, as I requested you, we should really have one full day allotted to Mr. Trivedi to give dharma katha. As I was a student of philosophy, I was very much interested to hear what he was saying, but let him also speak. Sir, I have a small analogy. What will happen, Mr. Ram Chander, I am asking you, or the Home Minister or the Law Minister: if all the States refuse to accept a Central Act which is not in State list under the Constitution? I am under the Constitution. In the Union of States I am one of the federal units. I am a State. Suppose I differ. I have a right to pass my resolution only to express my view. It is not passing an Act. I am expressing my view that what you are saying is wrong. So, let us imagine, tomorrow, if all the States, the 29 States say, 'no' to a Central enactment, what will happen? You must think of this. It might happen. Today, it is such a big agitation. It is poisoning the minds. Sir, there is an analogy to this. I bring it from Tamil Nadu. When Hindi was being imposed during 1960s, two Ministers, Mr. Subramaniam and Mr. Alagesan sent in their resignations from the Central Ministry. They submitted their resignation opposing to what the Centre says. But, the Prime Minister said that it is a Central Subject. They said, 'If it is a Central Subject, we are resigning.' He sent resignations to President. What happened? It went to the then hon. President, Dr. Radhakrishnan. He called the

Prime Minister and said, 'Do you want to break the country? Go and have some kind of a compromise. Talk to them and find out what exactly they want.' This is the spirit of mutuality I am asking for. It is with this spirit, I am saying this. There is law. It is what is in your mind. And, this is the view that we have in our mind. So, let us all sit together. Both of us want that the country to remain one. Both of us want that the unity of the country to remain strong. In such cases, when things like this happen, we must sit together, sort it out and find adjustments which will make a country a great nation.

With this, I am telling you again, since ancient days, it is the civilizational ethos —if I were to use the last word —which are under threat. It is not your religion or philosophy or Hinduism or Islam under threat. It is the civilization that is under threat. It is our civilization which is, perhaps, one of the oldest, if not oldest of all, while Greece, Babylonia and Egypt are in the memory of people, but not in India. It is a vibrant, kicking civilization. Let us all save it. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have taken the entire time. So, no time is left for other speaker from your party. This is for your information.

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, I am very sorry to say that the Address of the hon. President is missing the real issues being faced by people and the country.

Our country is passing through a serious economic crisis and those serious problems are not mentioned in the Address. This Government has failed miserably in protecting and upholding our Constitution. This is a Government which is using all its might to destroy the principle of secularism and fraternity enshrined in our Constitution. Those forces behind this Government are working day-and-night, putting their efforts to destroy the communal harmony in our society and perpetuate violence to make minorities of our country feel unsafe here. My dear colleagues in the Treasury Benches, your eyes and ears are closed towards the livelihood issues of this country. Your hands are stained with blood of the common man which you have squeezed out to make your corporate masters happy. The term you people are in power will be written in the history books as the dark age of our democracy.

Sir, hon. President's speech has miserably failed in addressing the shameful situation of our nation and the present condition of our nation. This Government has really worked hard to transform our country literally into a graveyard. This Address has

[Shri Elamaram Kareem]

failed to mention the worst ever economic slowdown our country is facing now. There is a consistent stagnation and decline in national savings rate, domestic capital formation, decline in growth of investment and decline in growth in various industrial sectors. Widespread unemployment and worsening situation of poverty led to sharp decline in effective demand and contraction of commodity market. This, in turn, resulted in drastic cut in capacity utilization in industries and closed down and shutdown of production leading to retrenchment, lay-off, wage cut, etc., aggravating impoverishment. Further, unemployment rate is at 45 years high! This is the present picture of our country's economy. The President's Address has failed to mention all this.

This Government has failed in defending the Constitution of our nation. It ignored its duty to protect the basic structure of our Constitution. The recent amendment to the Citizenship Act undermines the secular concept of citizenship enshrined in the Constitution. It discriminates a section of people in the country. As per our Constitution, citizenship should never be on the basis of religion. This Government has derailed this principle by passing the Citizenship (Amendment) Act. And, this Act is the latest episode in the series 'destroy India' by our rulers.

The hon. President, in his speech, congratulated this Government for passing certain legislations within a few months. But, it was through undermining the process of Parliament. No parliamentary scrutiny was allowed. What is the meaning of parliamentary process? The speech is having a mention over the Supreme Court's verdict on Ayodhya. Back in 1992, before the historical monument Babri Masjid got demolished, there were verdicts and directions from different courts. The country remembers how these people, who are in power now, treated those verdicts. They were leading the violence and demolished Babri Masjid. It is interesting to hear that these same people are now respecting the Judiciary. The speech also tells that the violence, in the name of protests, will weaken the society and the nation. So, what the citizens of this country should do when the violence is perpetrated by the Government? We have witnessed the Government-sponsored violence in different parts of the country against the peaceful protests. The incidents which happened in our prestigious educational institutions and universities clearly proved this. The other day, we saw a person firing at the students and the police, in the back side, were simply watching it, as if they were watching a game. So, doesn't all this weaken our nation?

The speech indirectly mentions about the massive mandate. What about that mandate, after the victory in Lok Sabha elections, if that position exists now? What happened in Maharashtra? The Chanakyas of the ruling party worked day and night to form the BJP Government in the State of Maharashtra. Finally, those Chanakyas were sunk in the Arabian Sea and an anti-BJP Government came to power in the Financial Capital city of India. What happened in Jharkhand? So, mandate is an old story. If you continue to argue about that mandate, is it a license given to you to enact any law as per your whims and fancies and all the citizens should obey them. I would like to remind this Government that this mandate is not for derailing our Constitution. If you enact such legislations, which are against the values and principles of our Constitution, then don't expect the people of this country to follow it. Look at the protests throughout the country, and not only throughout the country, but the protests are going on all over the world against the Citizenship (Amendment) Act. Yesterday, a group of people assembled in front of the Headquarters of the UN and protested against the CAA. Is it a matter of pride for this country? I am proud to say that the State of Kerala. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Total fourteen minutes have been allotted to your party. And, there are two speakers. You have already taken seven minutes. Please bear this in mind.

SHRI ELAMARAM KAREEM: I know, Sir.

I am proud to say that the State of Kerala has shown the way to the whole nation by unanimously passing a Resolution in the State Assembly. The lone Member of the ruling party, the BJP, also supported that Resolution. And, under the leadership of the Chief Minister. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. MURALEEDHARAN: He did not support the Resolution. He had opposed that Resolution and he has also made a request to the Speaker that the word 'unanimously' be deleted.

SHRI ELAMARAM KAREEM: That is not correct. He had not opposed the Resolution. ...*(Interruptions)*...

SHRI T.K. RANGARAJAN: *

---

* Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. T.K. Rangarajan, you are not supposed to intervene. ...*(Interruptions)*... It is not going on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI ELAMARAM KAREEM: It was passed unanimously. It is there on the record of the Assembly. ...*(Interruptions)*... And, a joint agitation was also made in Kerala. It was followed by a human chain, in which 7.5 million people of Kerala had participated. After that, different State Assemblies have passed Resolutions against the CAA. That protest should be considered by the Government. The spirit of the people should definitely be considered by the Government. Sir, I have already mentioned about the economic situation of our country. In the Budget speech, the Government has announced all-out privatisation of the prestigious public sectors. The country is being destroyed. The people of this country, particularly, the working people and the peasantry are in a miserable condition. In these circumstances, I can't support the Motion of Thanks proposed by the ruling Party Member. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, for the other speaker, only five minutes are left.

SHRI K.K. RAGESH (Kerala): Sir, ...(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. You are not supposed to speak. Your name is not there. This is not going on record. Now, Shri Tiruchi Siva.

SHRI K.K. RAGESH: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. Shri Tiruchi Siva. Nothing is going on record, Mr. Ragesh. Please take your seat. Nothing is going on record. Only what Mr. Tiruchi Siva speaks will go on record.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I thank the President for his Address to both the Houses of Parliament, standing by the convention. But, during the course of my speech, I would have to criticize or express my dissatisfaction in the contents of the President's Address. But it need not be construed as the President for only the Government speaks through the President. The President's Address narrated that this Government has achieved a lot. It was only a bureaucratic statement that he read out and not the achievements of a Government. This is not an evasive charge against what the President's Address has delivered to the nation through the Members of Parliament.

---

* Not recorded.

This Government is in power for the sixth year and this is their second term. There is a narrow difference between a lie and a promise. A lie will make a person to believe something whereas a promise will make a person to hope for something. So, when a political party gives some promises, people with the hope support them. May I ask? Because the President is very proud in saying that this Government has enacted historical legislations. What those legislations are, I will come to that later. But this Government, before coming to power, after the first election, in 2014, gave some promises. Have they kept those promises? What are they? They had said that they would unearth the black money abroad, will come and distribute ₹15,00,000/- to each individual in the country. ...*(Interruptions)*... But nothing happened. People were so anxious that they would get ₹15,00,000/- and they voted them to power. They had also said that every year, two crore people will be given employment. But nothing happened. They had said that farmers' income would be doubled. That also did not happen. So, when they could not keep their promises made in the first term, how did they come to the power in the second term? It is not because of the strength of the BJP, Sir, it is because of the lack of unity among the Opposition parties. I should say that because in Tamil Nadu we had a sweep. Except one seat, we had won all the 39 seats because the Opposition was united. So, keep it in mind. Now, there are such symptoms. When we get together, that will be the end of your race. What, actually, is your achievement, let me say? Federalism is scrambling, secularism is fading and the social country is becoming a capitalist country. All the basic tenets of the Constitution are being diluted. In the Monsoon Session, the House was extended for a week and around 35 Bills were passed. Most of the Bills were draconian in nature and the rest of the Bills were attempted clandestinely usurping the powers of the State to the Centre. Sir, we opposed. Of course, we expressed our concern, but it was only on record, and the Government with its majority just went through. Here, many of the parties which are supporting them are all regional parties. They will come to know one day or the other that their powers which the Constitution has given to us have already gone to the Centre. So, the voice, that the States should be given more powers, should be very strong. After coming to power, this Government, not directly totally, but through every Bill, they are taking away all the powers. So, federalism is scrambling, secularism is fading. Why did I say that? The President very proudly mentioned about some four Acts which have been passed by this Government. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I need the House to be in order.

श्री उपसभापति: कृपया पीछे बैठ कर बात न करें। प्लीज़।

श्री आनंद शर्मा: यह तो गलत हो रहा है।

श्री उपसभापति: यह सब तरफ से होता है, सभी से मेरा निवेदन है। ...**(व्यवधान)**... नहीं, नहीं, हर तरफ से ...**(व्यवधान)**...

SHRI TIRUCHI SIVA: This is the Government.

श्री उपसभापति: मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता।

SHRI TIRUCHI SIVA: The House should be in order.

श्री उपसभापति: सारे सदस्यों से मेरा निवेदन है कि आप सुनें। हर पक्ष से यह होता है, सभी से मेरा निवेदन है। प्लीज़ शांत रहें। Please continue.

SHRI TIRUCHI SIVA: He said the Triple Talaq, the abrogation of Article 370, the Amendment of the Citizenship Act and the Transgender Act. The Transgender Act has been now challenged in the Supreme Court. That is different. And, in these three Acts, first I will come to Triple Talaq. My friend, the hon. Member, Shri Prasanna Acharya, asked why should we differentiate between Muslim women, Hindu women and Christian women? When they brought in and enacted the law, the Triple Talaq will be invalid. There are many questions. Considering the constraints of time, I cannot go into the contents of the Bill or the Act now. It was totally impractical. Whether they agreed or not, but they said that it is for the sake of Muslim women. But I would like to remind, Sir, that in the same House, I brought a Private Member Resolution to enact a law for the welfare of the widows. That Resolution was defeated by this Ruling Party. It was put to vote, Sir. ...*(Interruptions)*... It was put to vote. They should have supported it. It was only a Resolution, not even a Bill, a Resolution to have a law for the welfare of widows. There are four crore seventy lakh widows in this country. They need something like the Acts which are in vogue in Tamil Nadu and all. But that was defeated. So, you say that you are voicing for the Muslim women but you are defeating something for the Hindu women, means, it is not for the Muslim women, Sir, it is to target the Muslims. It is to target the Muslims and so also the abrogation of Article 370 which are temporary provisions for giving special powers to the Jammu and Kashmir Valley. Sir, what is Article 371? It is 'special provisions to the States of

Maharashtra and Gujarat.' What is 371A? It is 'special provisions to the State of Nagaland.' What is 371B? It is 'Special provisions to the State of Assam.' What is 371C? It is for the special provisions to the State of Manipur. And 371D is for the State of Andhra Pradesh and Telangana. Why should you take only 370 means, again it is pointed at Muslims, one special community. That is what Dr. Keshava Rao said. Why are you polarizing? It gives an impression like that. The same is with the CAA. When the CAA came, you said that with humanitarian consideration, Mahatma Gandhi told it. Mahatma Gandhi told that the Government should not have any religion. The State cannot interfere in my or your religion. That was Mahatma Gandhi's statement.

SHRI T.K. RANGARAJAN: That is Constitution.

SHRI TIRUCHI SIVA: He said that. The Government said that those who are religiously persecuted, they are given citizenship. Then why should you exclude only one community? That is what all my colleagues asked here. It has created an apprehension in the minds. That is the agitation that is going on across the country; everywhere. Sir, in Jawaharlal Nehru University, even if a student has to enter into the campus, he has to show his ID card. Hundreds of people with iron rods went in at night in the hostel and they manhandled those people there and they were severely beaten. How it happened? Who let them in? And Kashmir students who were staying there were targeted, and the students whose rooms had a photo of Bhagat Singh and Ambedkar, those rooms were targeted. I just would like to ask how they had access into the campus. How were they allowed to attack the students when Police were waiting outside? For two hours, it has happened. Why? Because they were raising voice. Nothing has happened. No one arrested. No action has been taken. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, this is the voice of the Opposition. That's all. I am raising a genuine question. Of course, they are of the same view. How did it happen? Because they voice for these people. The whole country is still on the roads. Students are agitating and Governments are trying to bring in laws that students should not come to road and agitate. Democracy is now under a very big threat in this country. So, what all I say is, all the basic tenets of the Constitution are under threat. I said, federalism crumbling, secularism fading, socialism becoming capitalism and now

[Shri Tiruchi Siva]

democracy is under threat. Is this your achievement, Sir? And why do I say that this country is becoming a capitalist country? One per cent of the richest in this country are holding 42.5 per cent of the nation's wealth, that is, the total worth of the nation's economy; ten per cent are holding 74 per cent. And do you know how much one per cent's worth comes to? It is three times the value of the money which 935 million people are holding. That means, the wealth of 94 crore people is being held by just one per cent, and 50 per cent of the people at the bottom of the rung have just 2.8 per cent worth of the nation's economy. You say, that is your achievement!

Sir, I now come to another point. This Government says many things. Last year, before the Government came to power, during elections, they said, 'minimum government, maximum governance'. Do you know what the result is? The CAG Report has said that of the funds allocated to various ministries, 40 per cent of the money has not been spent. The Agriculture Ministry has spent just 49 per cent, the Coal Ministry, just 41 per cent, the Ministry of Civil Aviation, 39 per cent, the Ministry of Culture, 54 per cent, Electronics, 59 per cent, and so on. Apart from that, there are schemes like *Swachh Bharat* and others. I can't pronounce those Hindi names. All their schemes have Hindi names! I have to say just this thing. In 2018-19, an amount of ₹ 2,000 crore was allocated for setting up 22,000 shanties throughout India to enable farmers to sell their produce directly. However, after two years, only 376 shanties were established and the amount spent was just ₹ 10 crore. The amount allocated was ₹ 2,000 crore, Sir, but the money spent was just ₹ 10 crore. Another aspect is the President's Address. The President's Address talks about achievements and what the Government would be doing in future. This is what they have done even earlier. Now, everyone in this country is living in a sense of fear, especially a particular community. India is known for its composite and diverse culture. We embody unity in diversity. There are many religions, languages and cultures, but all of us live together. But when someone feels that there is a threat, it is not good. The genuine rights which the Constitution has bestowed upon us should be given to all citizens. It should not deprive one section of the people. And, when we talk for one section of the people, it does not mean that we are against other sections of the people.

Sir, many public sector units are being disinvested. Last year's revised estimate of the GST revenue in the Budget has not been approved whereas by way of selling off the public sector shares of the Government, they approved more and this year, their

target is 2.1 lakh crore rupees. They are selling off LIC and IDBI. What more is left here? People from outside are coming here. There are individual bosses, companies are thriving and the common man is going after MGNREGA for just 100 rupees. Even those 100 rupees are not meant for everyone; only one person in a family would be getting a job. If there are four or five persons in a poor family, there would be just one person going for a job and that too, not on all days. So, while one person is struggling to earn his bread, there are others who take away all the money. In the past three years, public sector banks have written off ₹ 2.7 lakh crore worth of bad loans. Let me quote it for State Bank alone –above ₹ 100 crores and within ₹ 500 crores, they have waived off nearly ₹ 76,600 crore. As for loans above ₹ 500 crores, they have written off ₹ 37,700 crores. What is this, Sir? When an ordinary person or a farmer takes an agriculture loan or a student takes an education loan, he is being threatened, booked, brought under CIBIL, is being targeted and is made to go through all indignity, whereas big corporate people's loans worth ₹ 2.75 crore are written off in this country. Is this your achievement?

That is what we ask. It is not against any individual.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your allotted time is over. Please conclude.

SHRI TIRUCHI SIVA: I am concluding in a minute. One renowned Professor of Economics from my State has written a verse. I am concluding with that: "Gandhi wanted village India; Nehru built modern India; Lal Bahadur stood for *Kisan* India; V.P. Singh gave social justice India, Narasimha Rao privatised India, Dr. Manmohan Singh globalised India and Modi devalued India. Air India is now ready for sale. Beware of sale of India." Thank you.

श्री उपसभापति: श्री संजय राउत। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़, प्लीज़। कृपया बैठ कर बात न करें।

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): डिप्टी चेयरमैन सर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर पूरा सदन चर्चा कर रहा है। सब सुन भी रहे हैं। आजाद साहब की बात सबने सुनी है, भूपेन्द्र यादव जी की बात भी सुनी है, सुखेन्दु दादा की बात भी सुनी है।

सर, राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है, वह तो सरकार के मन की बात होती है। ...**(व्यवधान)**... मन की आवाज़ सुनिए। बात एक व्यक्ति की होती है। यह आवाज़ है। यह सरकार के मन की आवाज़ है। वह भी हमने सुन ली, लेकिन देश में भी एक आवाज़ उठ रही है, वह भी सुननी चाहिए। जिस प्रकार का माहौल देश में आज हम देख रहे हैं या बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है, जो देश को फिर एक बार तोड़ना चाहती है, देश की

[श्री संजय राउत]

एकता को खतरा पैदा करना चाहती है, नफरत का माहौल पैदा करना चाहती है। यहाँ टुकड़े-टुकड़े गैंग की बात हुई। मैं मानता हूँ कि हो सकता है, लेकिन अगर सरकार इस टुकड़े-टुकड़े गैंग से नफरत करती है, इस प्रकार की कोई बात है, तो वह जो माहौल बन रहा है, उसको दुरुस्त करने की भी पहल आपको करनी चाहिए। लोग बैठे हैं, दो-दो महीने से सड़क पर उतरे हैं। चाहे वे किसी भी धर्म के हों, लेकिन देश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, सब हमारे हैं। आप जाइए, उनके साथ बैठिए, उनके मन में जो डर है, वह दूर कीजिए। आप कहते हैं- 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।' विकास की बात छोड़ दीजिए। 60 साल में विकास होता आया है। देश का विकास होता ही रहता है। विश्वास की बात है, साथ की बात है। अब इस साथ की बात करें, तो 30 साल का हमारा साथ था न? ...**(व्यवधान)**... विश्वास की बात करें, तो सबसे ज्यादा विश्वासघात हमसे ही हुआ है। ...**(व्यवधान)**... छोड़िए। ये जो बातें हैं, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर होती हैं। हम बात करेंगे, लेकिन देश के सामने जो असली समस्या है, उसको तो राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में टच नहीं किया। आपने कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र पर सरकार चल रही है और सरकार पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम रही है। यह बात कहने की जरूरत क्या है? हमारे मन में आपकी ईमानदारी के बारे में कोई शंका नहीं है, तो आपके मन में ईमानदारी और निष्ठा के बारे में confusion क्यों है? ऐसा कौन सा माहौल है कि आपके मन में शंका है कि आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं? सरकार ने कहा कि हमने 8 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिये हैं, 2 करोड़ गरीबों को घर दिये हैं, 38 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले हैं। उसमें 15 लाख जब आयेंगे, तो बैंक खाते पूरे हो जायेंगे। 24 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा कवच दिया है। तीन करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त बिजली के कनेक्शंस दिये हैं। ये सब आपने दिया है, हम मानते हैं, लेकिन आपने देश के लाखों-करोड़ों युवाओं को काम नहीं दिया है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आर्थिक मन्दी की वजह से इस देश में जो बेरोजगारी का राक्षस खड़ा हुआ है, देश में लगभग एक-तिहाई युवा बेरोजगार हैं। एक करोड़ युवाओं ने पिछले एक वर्ष में नौकरी गंवाई है। अगर इसका जिक्र राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण में करते तो हम इस अभिभाषण का स्वागत करते। अगर आप ईमानदारी की बात करते हो तो ईमानदारी से हमें यह बात कहनी है कि देश में आज सबसे ज्यादा बेरोजगार पैदा हुए हैं। हर दो घंटे में तीन बेरोजगार आज खुदकुशी कर रहे हैं। किसान ही नहीं, बेरोजगार भी आज खुदकुशी कर रहे हैं। बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, जान दे रहे हैं और आप जीडीपी बढ़ने की बात करते हो। अर्थव्यवस्था बरबाद हो चुकी है, बेकार हो चुकी है। बजट का सबसे लम्बा भाषण देने से अर्थव्यवस्था में तेजी नहीं आएगी, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक साल में एशिया की सबसे कमजोर करेन्सी में से एक हिन्दुस्तान का रुपया है, यह हमारी अर्थव्यवस्था है।

कश्मीर की बात हुई, वहां से आर्टिकल 370, 35ए हटा दिए गए। अच्छी बात है, हमने उसका स्वागत भी किया था। लेकिन उसके बाद जम्मू-कश्मीर में क्या हुआ, आप बताइए। तीन महीने में महाराष्ट्र के 14 जवान शहीद हुए हैं। हमारे जवान आज भी कश्मीर में शहीद होते

हैं, तो माहौल ठीक हुआ, यह आप कैसे मान सकते हैं? कितने नये उद्योग वहां गए, कितने लोगों को रोजगार मिला है, आप बताइए। आज भी हम वहां जाकर दो इंच जमीन की खरीद नहीं कर सकते, मुझे मालूम है। आपने वहां से आर्टिकल 370 हटाया है। मैं चाहता हूं कि वहां जाकर अपने पैसे से स्कूल खोलूं, मैं वहां जमीन खरीदना चाहता हूं, आप मुझे जमीन दीजिए। यह मेरा चैलेंज है, मैंने बहुत कोशिश की है। वहां से आपने आर्टिकल 370 निकाला है। कानून बनते हैं, लेकिन जो कानून होता है, वह जनता को डराने के लिए होता है, उसकी आवाज दबाने के लिए नहीं होता। जनता में एक सुरक्षा की भावना निर्माण करने के लिए होता है, लेकिन जिस प्रकार से कानून आप बनाने जा रहे हैं और बनाते हैं, उससे देश में सिविल वार लाइक सिचुएशन हो रही है। आप देखिए, बाहर लोगों के मन में कितना भय है, डर है। लोगों में कानून का डर होना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन दहशत नहीं होनी चाहिए। यह कानून का राज है, कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, डा. अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, मैं मानता हूं, लेकिन जिस तरह से कानून से डर पैदा करके जो राजनीति होती है, इससे देश को खतरा है।

अभिभाषण में हिन्दुस्तान के डिफेन्स सैक्टर के बारे में बड़ी बात कही है। सेनाओं के सुरक्षा बलों के पास पर्याप्त हथियार, सुरक्षा उपकरण, बुलेट प्रूफ जैकेट्स आदि के बारे में बात कही है। मैंने कल प्रधान मंत्री जी का भाषण सुना है। आपने कहा कि अगर हम मन में ले आएं तो पाकिस्तान को 8-10 दिन में हम धूल चटायेंगे, हरा देंगे। आप हरा दो, मैं अभिनन्दन करता हूं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारे देश के जवानों की हालत क्या है? जो हमारी पैरा-मिलिट्री फोर्स है, उनके बारे में अखबारों में भी आया है। उनको सबसे ज्यादा आर्थिक मन्दी का फटका लगा है। सीमा पर तैनात जवानों को दो महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। उन्हें 3,500 रुपये जो राशन भत्ता मिलता है, वह दो महीने से नहीं मिला है। उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं हैं, स्नो बूट्स नहीं हैं। नौ हजार फीट की ऊंचाई पर हमारे जवान लद्दाख और सियाचिन में हैं। यह सी एंड एजी की रिपोर्ट है, यह टुकड़े-टुकड़े गैंग की रिपोर्ट नहीं है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। वहां बर्फीले इलाकों में जो जवान तैनात हैं, उनके पास स्नो बूट्स नहीं हैं, जबकि आप पाकिस्तान को हराने की बात करते हो कि सबसे पहले हम पाकिस्तान को हरायेंगे। सबसे पहले हमारी फौज की जो जरूरतें हैं, उनका जो राशन का भत्ता है, उनके बच्चों को जो एजुकेशन का भत्ता मिलता है, उनको जो स्नो बूट्स, जैकेट्स, स्नो ग्लासेज मिलते हैं, वे नहीं मिल रहे हैं। उन्हें आप पहले ये सब दीजिए। उस बारे में चर्चा कीजिए। यह बात तो चलती है, विकास की बात चलेगी, विकास की बात चलेगी, सबके साथ की बात चलेगी, सालों-साल चलेगी, हम भी आपके साथ-साथ विकास करते रहेंगे। देश है...**(व्यवधान)**... आप मत बोलिए। आप मेरे खिलाफ बात मत कीजिए, यह आपको बहुत महँगा पड़ेगा। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*...

श्री राकेश सिन्हा (नाम-निर्देशित): *

* Not recorded.

श्री संजय राउत: मैं सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: संजय जी, आप चेयर को एड्रेस करके बोलें। ...**(व्यवधान)**... कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय राउत: मैं सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: राकेश जी, चूँकि आपको चेयर से परमिशन नहीं है, इसलिए आप कृपया बैठ जाएँ। ...**(व्यवधान)**... संजय जी, आप चेयर को एड्रेस करके बोलें। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय राउत: सर, मैं मानता हूँ कि देश बनाने की जिम्मेदारी, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम सब देश बनाना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**... राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का मैं अभिनंदन भी करता हूँ, लेकिन ये कुछ बातें राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आ जातीं, तो यह अभिभाषण बहुत अच्छा होता। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Rakesh Sinhaji, nothing is going on record. ...*(Interruptions)*...

श्री संजय राउत: सीएजी की रिपोर्ट है।...**(व्यवधान)**... यह सीएजी की रिपोर्ट है।...**(व्यवधान)**... आप इसको पढ़िए, इसको समझिए।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: संजय जी, आप चेयर को एड्रेस करें।...**(व्यवधान)**..... Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... संजय राउत जी, आप चेयर को एड्रेस करें। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़, आप लोग बैठें। ...**(व्यवधान)**... आप चेयर को एड्रेस कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय राउत: यह सीएजी की रिपोर्ट है और यह पार्लियामेंट में रखी गयी रिपोर्ट है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप सबसे आग्रह है कि कृपया अपनी-अपनी जगह पर बैठें। ...**(व्यवधान)**... आप लोग अपनी-अपनी जगह पर बैठें और उन्हें बोलने दें। ...**(व्यवधान)**... Rakesh Sinhaji, nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... माननीय सदस्यगण, माननीय दिग्विजय सिंह जी, कृपया आप लोग बैठें। राकेश जी, कृपया आप बैठें। अनिल देसाई जी, कृपया आप बैठें। ...**(व्यवधान)**... संजय जी, आप चेयर को एड्रेस करें।..**(व्यवधान)**... अगर कोई आपत्तिजनक बात कही जाएगी, तो वह examine होगा। ...**(व्यवधान)**... आप चेयर को एड्रेस करें। ...**(व्यवधान)**... आपको जो objection है, कहेंगे, तो वह examine होगा, कृपया आप बैठें। संजय जी, आप अपनी बात कहें। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय राउत: डिप्टी चेयरमैन सर, यह सीएजी की रिपोर्ट है और यह संसद में पेश की गई है। उसी बात को मैं सामने लेकर आया हूँ और मैं संसद में पेश रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: संजय जी, सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड पर जाएगी, इसलिए आप बोलें। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय राउत: डिप्टी चेयरमैन सर, मैं इतना ही कहूँगा कि राष्ट्रपति जी ने जो भाषण किया है, उसमें बहुत सी बातें अच्छी हैं, सरकार की हों, देश की हों, लेकिन अगर इसमें इन सभी बातों का जिक्र होता, तो यह भाषण और जोरदार तथा मजेदार होता। मैं फिर एक बार राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का अभिनंदन करता हूँ और मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री उपसभापति: अभी दो मिनट बाकी हैं। Now, Shri Majeed Memon, you can start the speech, and continue tomorrow. ...*(Interruptions)*... दो मिनट का समय है, कृपया आप बोलें।

SHRI MAJEED MEMON (Maharashtra): Sir, I will continue tomorrow. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Madhusudan Mistryji, you are not supposed to speak. You have no permission from the Chair. ...*(Interruptions)*... माननीय सदस्य, एक तरफ आप बोलना चाहते हैं और दूसरी ओर समय waste करते हैं। दोनों चीजें कैसे संभव हैं? आप देर तब बैठने को भी तैयार नहीं है, अधिक बोलना भी चाहते हैं, समय भी चाहिए, यह कैसे संभव है?

Now, we shall take up the Special Mentions. Shri K.C. Ramamurthy. Please lay on the Table.

SPECIAL MENTIONS

*Demand for setting up nature cure hospital and research centre in Mandya, Karnataka

SHRI K. C. RAMAMURTHY (Karnataka): Sir, AYUSH systems are time-tested methods to tackle life-style disorders and Karnataka is one of the leading States in providing AYUSH healthcare services to the people, particularly in rural areas. As a part of popularizing and revitalizing the AYUSH System of Medicine, a proposal for setting up of 100-bedded Nature Cure Hospital and Research Centre in Nagamangala, Mandya District of Karnataka, was submitted in 2004 and the Government of Karnataka allotted 16 acres of land for this purpose. Since then the project was languishing until the AYUSH Minister laid the foundation-stone in 2017 and upgraded proposed 100-bedded hospital to 200-bedded hospital and set a target to complete it in 20 months.

---

*Laid on the Table.